# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 22 मार्च–28 मार्च 2010



**चौथी दुनिया का राज्यसभा को जवाब**

पेज 3

**बिहार में मुसलमान**

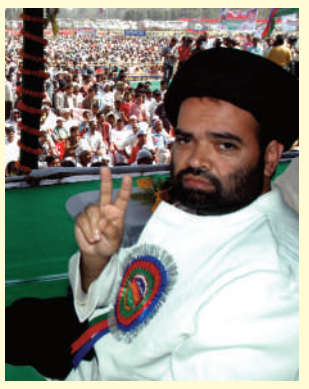

पेज 4

**कानूनी पहलू और अंतरराष्ट्रीय समुदाय**

पेज 5

**सार्वभौम साई : पानी से दीये जल उठे**

पेज 12

# यह राहुल के लिए है

**आख़िर महिला आरक्षण का तमाशा कराकर कांग्रेस और भाजपा कौन सी क्रांति करने जा रही है? न तो इससे महिला समाज बदलने वाला है, न ही आम महिलाओं की आर्थिक दशा में कोई बड़ा अंतर आने वाला है. फिर भी सभी राजनैतिक दलों में मारामारी मची है.**

कमाल अख्तर | वीरपाल सिंह | नंद किशोर यादव | आमिर अली ख़ान

एजाज़ अली | साबिर अली | सुभाष यादव



संतोष भारतीय

संसद गरम लावे की तरह सुलग रही है. इस सुलगन का कितना अंदाज़ा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भाजपा के नेताओं को है, हमें नहीं पता पर हम चाहेंगे कि उन्हें पता चले, क्योंकि जो राज्यसभा में हुआ वह अगर आने वाले कल का संकेत है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि कुछ अशुभ भविष्य में भी होने वाला है.

महिला आरक्षण बिल संसद में चौदह साल पहले गुजरात सरकार के ज़माने में रखा गया था. इस पर आम राय नहीं बन पाई इसलिए इसे संसदीय समिति के सुपुर्द कर दिया गया. एक ओर महिला संगठन इसे पास करने की मांग करते रहे, वहीं दलित पिछड़े और मुस्लिम समाज से जुड़े वर्ग कहने लगे कि इस बिल में उनके वर्गों के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए, अन्यथा उनके वर्ग की महिलाएं कभी संसद में आ ही नहीं पाएंगी. दोनों के तर्कों में अलग अलग दम तो है, पर सही तौर से दोनों ही अधूरे हैं. अब जब कि यह बिल राज्यसभा ने पास कर दिया है तो इस पर गहन विचार करने की ज़रूरत है. लेकिन यह तो देखें कि राज्यसभा में यह पास कैसे हुआ.

आठ मार्च को राज्यसभा में संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर बिल रखा जाना था. राज्यसभा में सांसदों ने हंगामा किया तथा बिल की प्रतियां सभापति हामिद अंसारी से लेकर फाड़ दीं. जो सांसद इसमें शामिल थे, उनकी पहचान डॉ. एजाज़ अली, कमाल अख्तर, आमीर अली ख़ान, साबिर अली, नंद किशोर यादव, वीरपाल सिंह यादव व सुभाष यादव के रुप में हुई. नौ मार्च को सभापति ने इन्हें बजट सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया. ये सातों सदन में धरने पर बैठ गए. इनका कहना था कि जब सरकार, भाजपा व वामपंथ ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हाथ मिला लिया है तो उनके पास अंतिम चारा यही बचा है कि वे सदन में धरने पर बैठे रहें ताकि गंभीरता का अंदाज़ा कांग्रेस के लोगों को हो. पर इनकी आशा निराशा में बदल गई.

तीन बजे सदन प्रारंभ हुआ. ये सातों सांसद नारे लगाने लगे, मुस्लिम विरोधी, पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी बिल वापस लो.

बीस मिनट इंतज़ार के बाद सभापति ने वोटिंग का फ़ैसला लिया और सदन में मार्शल बुला लिए. सांसद हैरान रह गए. सदन में मार्शलों की संख्या सौ के आसपास नज़र आई. सातों को कंधों पर लाद कर सदन से बाहर निकाल दिया गया. देश ने यह सब शर्म से देखा. राज्यसभा के सभापति ने अगर राज्यसभा के पहले के सभापतियों की परंपरा का पता किया होता तो वे राज्यसभा की गरिमा बचा सकते थे. एक छोटा किस्सा हम बताना चाहेंगे.

शंकरदयाल शर्मा राज्यसभा के सभापति थे. कुछ सांसद उन्हें अनवरत परेशान करते थे. राज्यसभा के ही कुछ सदस्य उनके पास गए और कहा कि आप इन सांसदों का नाम लीजिए और सदन से कुछ दिनों के लिए निष्कासित कर दीजिए. शंकरदयाल जी ने बिना एक मिनट लगाए इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं, सभी को अपनी राय व्यक्त करने का हक़ है. मैं उस हक़ की रक्षा के लिए हूं. बाद में सदन में शंकर दयाल शर्मा इन सांसदों के परेशान करने के कारण रो तक दिए, पर उन्होंने इन्हें निकाला नहीं. काश हामिद अंसारी साहब शंकरदयाल शर्मा से कुछ सीख ले पाते. उनके फ़ैसले पर कांग्रेस सांसदों की प्रतिक्रिया थी कि यह अशोभनीय हुआ. लोकतंत्र में बातचीत के अनगिनत रास्ते और तरीक़े हैं, अगर उन्हें नहीं अपनाएंगे तो आप तानाशाही और गुंडागर्दी के लिए रास्ता आसान करेंगे. क्या इसकी शुरुआत राज्यसभा ने नौ मार्च को कर दी है, यह बड़ा अनुत्तरित सवाल है.

इस घटना से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि सभी की सहमति से बिल पास होना चाहिए . प्रणब मुखर्जी ने एक दिन पहले मुलायम सिंह यादव और लालू यादव को दोपहर के भोजन पर बुलाकर बात की. उन्हें प्रस्ताव दिया कि पहले क़ानून बन जाने दें, बाद में उसमें कुछ संशोधन हो जाएगा, लेकिन दोनों नहीं मानें. कांग्रेस की कोर कमेटी बैठी, इसमें प्रधानमंत्री सहित सभी जबरन पास कराने में हिचक रहे थे पर सोनिया गांधी ने कहा कि आज ही बिल पास होना चाहिए. जब इन सात सांसदों को मार्शल के भेष में सीआईएसएफ के जवान कंधों पर लाद कर ले जा रहे थे, तब उन्हीं के दल के काफी सांसद अपनी सीटों पर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

## वृंदा-सुषमा-अंबिका एक हैं

सोनिया गांधी को सुषमा स्वराज, वृंदा करात और अंबिका सोनी ने सफलतापूर्वक समझा दिया कि अगर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास हो जाता है तो वे दुनिया के इतिहास में अमर हो जाएंगी और उनका नाम कार्ल मार्क्स और लेनिन की तरह लिया जाएगा तथा यह भी कि इसके बाद सारी दुनिया में महिलाओं के आरक्षण की मांग उठ खड़ी होगी. ये वे महिला नेत्रियां हैं जिन्होंने महिलाओं को बीस प्रतिशत भी टिकट देने के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी, और न ही इन लोगों ने रोज़गार के लिए रोज़ी रोटी के लिए, जिसकी वजह से महिलाओं को सचमुच आर्थिक आज़ादी मिल सकती है, कभी आवाज़ उठाई हो. इतना ही नहीं, ये तीनों और चौथी सोनिया गांधी, हमेशा निर्णायक स्थिति में रहीं, अगर वे चाहतीं तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेज सकती थीं, क्योंकि टिकटों के बंटवारे में इनकी मुख्य भूमिका रहती है. किसी भी फ़ैसले का आधार यह बनना चाहिए कि उससे समाज बदलेगा या नहीं . बदलेगा तभी जब उसमें पिछड़े, ग़रीब, दलित और अल्पसंख्यकों की भागीदारी होगी. जिस तरह से इस बिल को लाया गया है, और जैसे पास कराने की कोशिश हो रही है उससे न सामान्य महिलाओं की भागीदारी होगी और न पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यकों की महिलाएं आएंगी. वे जो दिखने में महिला लगेंगी लेकिन पुराने मूल्यों और पुराने ढांचे को बरकरार रखने में अपने परिवार के मूल्यों को देश पर थोपेंगी. इससे अंर्तविरोध बढ़ने की ज़्यादा संभावना है.

## विरोध का मतलब निकाल बाहर..

राज्यसभा में साबिर अली, डॉ. एजाज़ अली, कमाल अख्तर, आमीर अली ख़ान, नंद किशोर यादव, वीरपाल सिंह यादव व सुभाष यादव ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया. इनका कहना था कि जब कोई आवाज़ नहीं सुन रहा हो तो क्या करें. गांधी का तरीक़ा और भगत सिंह का तरीक़ा दो ही रास्ते बचते हैं. इन्होंने बहरे कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए गांधी का रास्ता चुना.

मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू यादव ने लोकसभा में विरोध का मोर्चा संभाला. मुलायम सिंह और लालू यादव तो सदन के वेल में चले गए. कम ही ऐसे मौक़े आए हैं जिनमें इनके जैसे वरिष्ठ नेता वेल में गए हों. संसदीय परंपरा में वेल में जाना विरोध का अंतिम तरीक़ा माना जाता है.

इन तीनों ने कांग्रेस को समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन कांग्रेस नहीं मानी. और उसने मार्शलों का प्रयोग कर राज्यसभा में बिल पास करा लिया. इन तीनों ने सफलतापूर्वक देश में यह बात पहुंचा दी कि कांग्रेस मुसलमानों और पिछड़ों के ख़िलाफ़ है. कांग्रेस को राज्यसभा में वोटिंग के बाद अहसास हुआ कि उसे नुक़सान हो सकता है. इसके पहले कांग्रेस एक त्वरित सर्वे में आई बी से जानकारी ले चुकी थी कि यदि सरकार गिरती है और चुनाव होते हैं, तो उसे चार सौ से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं.

यहां प्रणब मुखर्जी बीच में आए. उनसे सांसदों ने, विशेषकर कांग्रेस सांसदों ने अपनी आपत्तियां जताईं. आरक्षित सीटों के फ्लोटिंग होने की सभी को चिंता थी. सांसदों ने कहा कि पिछले साठ सालों में हम, दूसरा प्रणब मुखर्जी, दूसरा शरद पवार तो पैदा नहीं कर पाए, इस व्यवस्था में इन्हें राजनीति से अलग तो कर ही देंगे. ममता बनर्जी ने इन

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

भ्रष्टाचार के खिलाफ चली इस मुहिम को कमजोर करने की साजिश पहले से ही शुरू हो चुकी है.



# दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

## बचाव की तैयारी में नौकरशाही

सूचना के अधिकार वाले कानून ने देश में सरकारी कामकाज को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया भले शुरू कर दी हो, लेकिन नौकरशाही अब अपने बचाव के रास्ते ढूंढने में लगी है. सरकारी बाबुओं का यह वर्ग तथ्यहीन और हल्के आरोपों से बचने के लिए नए तरीके ईजाद कर रहा है. खबर है कि कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर ने एक स्क्रीनिंग कमिटी गठित की है, जो सचिव स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की पहले समीक्षा करेगी और फिर यह तय किया जाएगा कि उस पर आगे कार्रवाई हो या नहीं.

कई लोगों का मानना है कि सरकार का यह कदम इसके उसे बहु प्रचारित दावे के विपरीत है, जिसमें सरकारी कामकाज को पारदर्शी और अधिकारियों को उनके काम के लिए उत्तरदायी ठहराये जाने की बात की जाती रही है. कुछ लोग तो इसे सरकार की इस हाथ ले, उस हाथ दे की नीति का एक उदाहरण करार दे रहे हैं. आरटीआई कानून के चलते केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों की बढी सक्रियता और आमजनों के हाथों में मिली ताकत का दबाव नौकरशाही पर स्पष्ट नजर आ रहा है. सरकार के गलियारे में होने वाली हर हलचल पर नजर रखने वाले जानकार लोगों के लिए यह कोई अनहोनी नहीं है. उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि सरकारी अधिकारी ऐसा ही कोई रास्ता अख्तियार करेंगे.

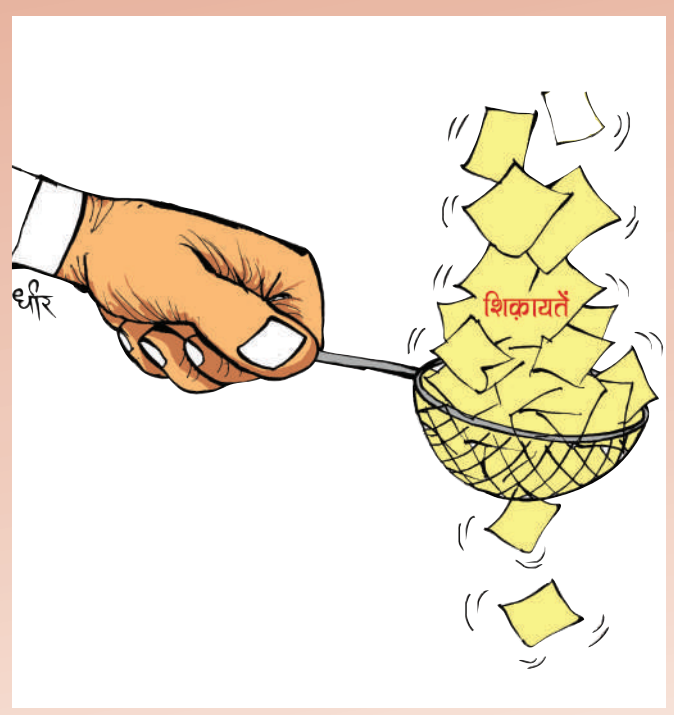


भ्रष्टाचार के खिलाफ चली इस मुहिम को कमजोर करने की साजिश पहले से ही शुरू हो चुकी है. कौन सी सूचना सार्वजनिक की जाए, इस मामले पर सरकार रोज नए–नए नियम बना रही है. और अब जबकि खुद कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली समिति वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करेगी तो आम लोगों के लिए इन शिकायतों पर कार्रवाई की उम्मीद करना दूर की कौड़ी साबित हो सकता है. लेकिन क्या चंद्रशेखर इन आवाजों को सुन भी रहे हैं या फिर अपने हमपेशों के बचाव का रास्ता तैयार कर ही खुश हैं ।

## बाबुओं ने किया कायापलट

राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के म्यूनिसिपल अधिकारियों ने, ऐसा लगता है, एक बड़ी पुरानी पहेली का हल ढूंढ लिया है. लंबे समय से लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि सरकारी अधिकारियों से काम कराया जाए तो कैसे, लेकिन गाजियाबाद नगर प्रशासन ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है. ऐसा मानने की वजह है. आप भरोसा करें या नहीं, लेकिन यह सच है कि गाजियाबाद नगर प्राधिकरण ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 121 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है. प्राधिकरण के इतिहास में यह एक नया रिकॉर्ड है और शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जब इसके पास कोष की कोई कमी नहीं है.

राजस्व के इस बढे आंकड़े से ज्यादा आश्चर्यजनक यह है कि इसका सारा श्रेय नौकरशाहों को जाता है. अब यह कैसे संभव हुआ, यह जानना मैनेजमेंट संस्थानों और प्रशासकीय विद्वानों के लिए भी रोचक हो सकता है. पिछले साल म्यूनिसिपल अधिकारियों ने मालदार माने जाने वाले पदों पर टैक्स इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए बजाब्ते निविदा प्रक्रिया अपनायी थी, जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी. बाबुओं से पहले यह पूछा गया कि वे कहां काम करना चाहेंगे और फिर उन्हें मनमाफिक पद पर नियुक्त कर दिया गया. नगर आयुक्त ए एस पांडे के मुताबिक अब ऐसे सभी अधिकारी अपना कलेक्शन टार्गेट पूरा करने के लिए दिन–रात मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने पदों पर बने रहें. जो अपने लक्ष्य से दूर रहते हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जबकि टार्गेट पूरा करने वाले अधिकारियों को समय–पूर्व प्रमोशन तक मिल सकता है. अधिकारी उत्साहित हैं क्योंकि प्रमोशन के इस रास्ते में उनके पुराने पाप भी रोड़ा नहीं अटका सकते. मतलब यह कि यदि किसी अधिकारी के खिलाफ पहले से कोई विभागीय जांच चल भी रही हो, तो भी टार्गेट पूरा करने की हालत में उन्हें प्रमोशन मिल सकता है. यह स्थिति बाबुओं और प्राधिकरण, दोनों के ही दोनों हाथों में लड्डू होने जैसी है. अब सवाल यह है कि क्या इस तरीके को अन्य जगहों पर भी आजमाया जा सकता है.

# यह राहुल के लिए है

पृष्ठ एक का शेष

बैठे या खड़े थे और बाद में अरुण जेटली का भाषण सुनते रहे. वाकआउट भी देर से किया, जबकि साथ जाना चाहिए था. शायद इसकी वजह मुलायम सिंह यादव और प्रणब मुखर्जी के साथ का भोज था.

बिल पास हुआ राज्यसभा में. लोकसभा के सांसद राज्यसभा की लॉबी में थे. उनमें बात हो रही थी कि आज नक्सलवादियों को हमने तर्क दे दिया कि हम उनकी बातें नहीं सुनते. वे ग़रीबों, दलितों आदिवासियों की हिस्सेदारी चाहते हैं, पर हम नहीं देना चाहते. सामाजिक न्याय को नकारने के राज्यसभा के पहले क़दम ने नक्सलवादियों की गोली संस्कृति में आज से बढ़ोतरी होने लगेगी. भाजपा ने राज्यसभा में मार्शलों के इस्तेमाल का समर्थन किया और सीपीएम ने भी. दोनों भूल गए कि आगे उनके सामने भी ऐसी स्थिति आ सकती है.

मैं वहीं खड़ा इन प्रतिक्रियाओं को सुन रहा था. इससे पहले संसद के केंद्रीय हाल में जितने भी सांसद मिले, किसी भी दल के, किसी ने भी इस बिल का समर्थन खुले मन से नहीं किया. सबके मन में आशंकाएं थीं, डर था, और विचार अलग अलग थे. मैं संसद की शपथ लेकर कह सकता हूं कि यदि बिना व्हिप के वोटिंग हो तो यह बिल कभी पास नहीं हो सकता. इसलिए नहीं कि सांसद महिला आरक्षण के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि इसलिए कि वे इसके तरीक़े के ख़िलाफ़ हैं. सेंट्रल हॉल में कुछ पत्रकारों ने सांसद संदीप दीक्षित को घेर लिया और बिल के पक्ष में तर्क देने लगे. संदीप दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप लोग तो क्रांतिकारी हैं, क्यों नहीं सारे मीडिया में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण लागू कर देते, उसके लिए तो किसी क़ानून की ज़रूरत नहीं. सभी क्रांतिकारी पत्रकार न केवल चुप हो गए, बल्कि खिसियानी हंसी हंसने लगे.

अब उन चिंताओं को देखें जो संसद के ज़्यादातार सदस्यों की है और जिनमें भाजपा व कांग्रेस की बहुसंख्या शामिल है. इनका कहना है कि पिछले साठ सालों में किसी भी राजनैतिक दल ने महिलाओं को पंद्रह प्रतिशत तक टिकट नहीं दिए. जिन्होंने दिए, उन्होंने किसी सदस्य के मरने के बाद उसकी पत्नी या किसी राजनेता की बेटी या बहू को ही दिए. आम महिला कार्यकर्ता को तो शायद ही कभी अपवाद के रुप में लोकसभा या विधानसभा का टिकट मिला हो. कोई बंधन नहीं था कि टिकट न दिया जा सकता हो, उन राजनैतिक दलों ने भी नहीं दिए जिनकी अध्यक्ष महिला रही हैं. कांग्रेस, भाजपा वामपंथ से लेकर. यह बात उन सब पर लागू है जो संसदीय राजनीति में हिस्सा लेते हैं. लगभग सभी राजनैतिक दल सत्ता में कहीं न कहीं रहे हैं, और किसी ने महिलाओं को हिस्–सेदारी नहीं दी. इसका उत्तर कोई तो दे.

राजनैतिक दलों की सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति न के बराबर होती है. राजनैतिक नेता अपने घर की महिलाओं के अलावा बाक़ी को चाहते हैं कि वह राजनैतिक सभा में शामिल हों. परिणाम होता है कि ज़्यादातर सभाओं में ग़रीब तबके की लाई गई महिलाएं ही शामिल होती है क्योंकि उस दिन उन्हें कुछ कमाई हो जाती हैं . जिसकी वजह से उस दिन भरपेट खाना मिल जाता है. समाज के ढांचे को बदलने की कोशिश राजनैतिक दलों ने कभी की ही नहीं.

इतना ही नहीं, इस बिल को जिसने भी बनाया या बनवाया है वह भी कमाल के दिमाग़ का आदमी है. इस बिल के सबसे कमाल के हिस्से के बारे में जनता को पता ही नहीं है. वह हिस्सा यह है कि तैंतीस प्रतिशत सीटें जो, आरक्षित होंगी, वे हर पांच साल के बाद बदलेंगी. इसका परिणाम होगा कि तैंतीस प्रतिशत सीटों पर जीतने वाली महिलाओं में एक संख्या ऐसी महिलाओं की होगी, जो कोई काम नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगली बार यह सीट उनकी नहीं रहने वाली है. वे उस कतार में आसानी से शामिल हो जाएंगी जो भ्रष्ट सांसदों की कतार है. ऐसी आशंका है पर यह केवल तैंतीस प्रतिशत महिला सीटों पर ही नहीं होगा, इसका असर बाक़ी तैंतीस प्रतिशत सीटों पर होगा जहां के सांसद को पता है कि उनके पास यह सीट अब नहीं रहने वाली क्योंकि यह अगली बार महिलाओं के लिए रिज़र्व हो जाएगी. छियासठ प्रतिशत सीटें इस नकारात्मक प्रभाव में आ जाएंगी. लूट खसोट का बाज़ार गर्म हो जाएगा. सांसदों का ख़ुद कहना है कि सांसद निधि भ्रष्टाचार और लूट के आरोपों से लबालब है. यह फ्लोटिंग सीट प्रावधान लूटखसोट और भ्रष्टाचार का खुला बाज़ार बन जाएगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी किसी के कंधों पर होगी ही नहीं.

सवाल है कि होना क्या चाहिए. मौजूदा बिल जिसे राज्यसभा ने पारित किया सही नहीं है और इसमें यदि पिछड़े दलित और मुसलमानों को आरक्षण मिल भी जाए, तो भी वह सही नहीं है. दोनों से अपेक्षित परिणाम आज तो नहीं निकलने वाला. उदाहरण के तौर पर दलितों के लिए लोकसभा के आरक्षण को देखना चाहिए. साठ साल के बाद भी दलितों के लिए कुछ खास दलित सांसद भी नहीं कर पाए हैं. होना यह चाहिए कि हर जगह नौकरियों में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए. चाहे वे पटवारी या लेखपाल हों, पी सी एस अधिकारी हों या आईएएस अधिकारी हों, स्वास्थ्य सेवाएं हों या सामान्य सरकारी नौकरियां. इतना ही नहीं पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेनाएं भी एक तिहाई नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए. इससे महिलाएं आर्थिक रुप से, सामाजिक रुप से आत्मनिर्भर होंगी. साथ ही क़ानून में प्रावधान होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनियां भी 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व रखेंगी. अगले दस सालों में इसे कार्यरुप में परिणत कर दस साल बाद संसद में भी यह आरक्षण लागू होना चाहिए. सीटें फ्लोटिंग नहीं होनी चाहिए हर शिक्षण संस्था में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व होनी चाहिए. यही न्यायपालिका में भी होना चाहिए.

अगर ऐसा नहीं होता तो अगले पचास सालों तक समाज के कमज़ोर तबके की महिलाओं के लिए न नौकरियों का रास्ता खुलेगा और न संसद का. वे हमेशा उन्हीं मूल्यों से जुड़ी रहेंगी जिन्हें मानने के लिए उनके पति या उनका समाज प्रतिबद्ध है. समाज बदलने की जगह वह उन्नीसवीं शताब्दी की ओर मुड़ जाएगा. इसका परिणाम होगा कि बंदूक़ लेकर अपना हिस्सा मांगने वाले वर्ग और ताक़त वर होंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हमारे महान लोकतंत्र में कमज़ोर वर्ग की, या कमज़ोर वर्ग के लिए आवाज़ उठाने का कोई मतलब ही नहीं बचा है. मार्शल के भेष में सीआईएसएफ के जवानों को जिन्होंने राज्यसभा में देखा है, उन्हें उस समय राज्यसभा डरावनी दिखाई दे रही थी, सांसद चूहे जैसे बैठे थे और मार्शल के भेष में बाउंसर की तरह उन्हें खा जाना चाहते थे.

आज संसदीय लोकतंत्र चलाने और उसकी साख बनाए रखने में कांग्रेस और भाजपा का बड़ा हाथ है. इन्हें संसद को, उसकी परंपराओं को, गांधी को, नेहरु को याद रखना चाहिए. कहीं इतिहास यह न कह दे कि लोकतंत्र के बिखेरने की शुरुआत हुई और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, ममता बनर्जी के साथ भाजपा के लोग भी सो रहे थे.

editor@chauthiduniya.com

## विरोध का मतलब निकाल बाहर..

पृष्ठ एक का शेष

सारी हलचलों से अपने को दूर रखा, जिसका फ़ायदा उन्हें बंगाल के आने वाले चुनावों में शायद मिले.

प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी को समझाया कि लोकसभा में मार्शल का इस्तेमाल आने वाले चुनावों में उल्टा पड़ेगा. इतनी जल्दबाज़ी की ज़रूरत नहीं है. साथ ही यह भी समझाया कि अगर इस तरह बिल पास हुआ तो फाइनेंस बिल पर सरकार को भाजपा और मार्क्सवादी मिलकर गिरा देंगे. सबूत में उन्होंने सोनिया गांधी को सुषमा स्वराज और वृंदा करात का गहराई से गले मिलता हुआ फोटो दिखाया. सोनिया को समझ में आ गया कि वह भाजपा के चंगुल में आधा फंस गई है. उन्हें शरद पवार का यह कथन भी बताया गया कि जब जब महिला विधेयक आया, सरकार गिर गई और मध्यावधि चुनाव हुए. ऐसा पहले भी दो बार हो चुका है.

हालांकि कुछ न्यूज़ चैनलों ने यह ख़बर चलाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की कि निलंबित सांसदों ने अपने किये की माफी मांग ली है. चौथी दुनिया ने इन सातों सांसदों से बात की. सभी का एक सुर में यही कहना है कि उनका विरोध हर हाल में जारी रहेगा वे अपने स्टैंड पर क़ायम रहेंगे. लिहाज़ा माफी मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता.

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 2
दिल्ली, 22 मार्च–28 मार्च 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

राज्यसभा केसदस्यों ने मांग की कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सदन केपटल पर रखी जाए. यह मांग अनसुनी कर दी गई, तब सदस्यों ने हंगामा किया.



# चौथी दुनिया का राज्यसभा को जवाब

**रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को लेकर राजनैतिक क्षेत्र में जो उठापटक मची, उसमें चौथी दुनिया का भी एक बड़ा रोल रहा. हमने इसे अपनी ज़िम्मेवारी के तौर पर माना कि अगर कोई सरकार इसे सदन के पटल पर रखने में कोताही कर रही है, तो मीडिया की इसमें सक्रिय भूमिका होनी चाहिए. एक जागरुक अख़बार को प्रहरी की तरह तैयार रहना चाहिए और अगर हमारी जनता के प्रतिनिधि कहीं अपनी ज़िम्मेवारियों से मुंह चुरा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें उनकी भूमिका याद कराते रहें. इसी प्रक्रिया में रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट हमने प्रकाशित की और सदन की कार्यवाही से अपने पाठकों को रूबरू कराया. हमने संसद की गरिमा को कम करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि हम उसकी गंभीरता समझते हैं. फिर भी राज्यसभा की ओर से हमें उसके लिए नोटिस भेज दिया गया. ज़ाहिर है कि हमें इसका जवाब भी देना ज़रुरी हो गया. हम मानते हैं कि हमारे पाठकों को भी पता होना चाहिए कि हमने देश की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा को क्या जवाब भेजा है, इसीलिए पूरा पत्र हम इस अंक में प्रकाशित कर रहे हैं.**

**आदरणीय सभापति महोदय,**
**राज्य सभा, नई दिल्ली.**

आपके द्वारा भेजे गए पत्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं

1. सबसे पहले मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं संसद की गरिमा से भली भांति वाक़िफ़ हूं और इस संस्थान की अहमियत की कद्र करता हूं. साथ ही यह भी कि मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा या ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा जिससे इसकी प्रतिष्ठ कम हो.
2. क़ानून के मुताबिक़, सदन में कही गई किसी भी बात के लिए सदस्यों के ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती. संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने वाले अख़बारों और अन्य प्रकाशन संस्थाएं भी इसी क़ानून के तहत सुरक्षित हैं.
3. संबद्ध मामले में हमने संसद की कार्यवाही की कोई ग़लत रिपोर्टिंग नहीं की है और न ही राज्य सभा के किसी सदस्य के भाषण को ग़लत ढंग से पेश किया गया है.
4. सदन के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए उपरोक्त लेख में लेखक ने सदस्यों को उनके कर्तव्यों को दुबारा याद दिलाने की कोशिश की है, जिसके लिए उन्हें चुना गया है और जिसके तहत जनसाधारण के महत्व के मुद्दों को सदन के संज्ञान में लाने की उम्मीद उनसे की जाती है. आलेख में सदन के सभी सदस्यों को संबोधित किया गया है. यदि कोई सदस्य विशेष इससे प्रभावित होने का दावा करते हैं तो वह क़ानून के तहत मेरे अथवा मेरे अख़बार के ख़िलाफ़ कोई भी क़दम उठाने को स्वतंत्र हैं.
5. ग़ौरतलब तथ्य यह है कि किसी भी सदस्य को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है. लेकिन उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों के निर्वहन के लिए प्रोत्साहित करना या ऐसा न करने पर उन पर अंगुली उठाना विशेषाधिकारों के उल्लंघन के दायरे में नहीं आता.
6. यह संभव है कि हमारी लिखी बातें कुछ सदस्यों को अच्छी न लगी हों या उन्हें अपमान बोध हुआ हो. लेकिन किसी भी हालत में हमारी बातों को संसद के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के दायरे में नहीं रखा जा सकता.
7. अब मैं आपको शब्दश: बताना चाहता हूं कि मैंने अपने लेख में सभापति महोदय, उपसभापति महोदय और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में क्या लिखा था.

सभापति महोदय के बारे में मैंने यह लिखा कि

.... राज्यसभा के सदस्यों ने मांग की कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए. यह मांग अनसुनी कर दी गई, तब सदस्यों ने हंगामा किया. दो बार के स्थगन के बाद सदस्यों को दो–दो मिनट बोलने की इजाज़त दी गई, जिसमें सभी सदस्यों ने कहा कि जब रिपोर्ट चौथी दुनिया ने छाप दी है तो क्यों इसे टेबल नहीं किया जाता. पहली बार चेयर पर सभापति थे और दूसरी बार उप सभापति. सभापति महोदय स्वयं कमज़ोर वर्ग से आते हैं. उनका नाम भी उप राष्ट्रपति पद के लिए वामपंथी दलों ने सुझाया था, लेकिन लगता है कि उप राष्ट्रपति बनने के बाद (और इसी वजह से वे राज्यसभा के सभापति हैं) उन्होंने अपने को कमज़ोर और ग़रीब तबकों से अलग कर लिया है. वे चाहते तो आसानी से सरकार को निर्देश दे सकते थे कि सरकार बताए कि कब वह रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखेगी.

... राज्यसभा के सभापति ने लोकसभा में रखी गई लिब्रहान कमीशन की तर्ज़ पर रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट रखने का निर्देश नहीं दिया, अगर उस दिन वे निर्देश दे देते तो कमीशन द्वारा पहचाने गए क्रिश्चियन समाज और मुस्लिम समाज के दलितों के लिए आरक्षण का फ़ायदा उठाने का दरवाज़ा खुल जाता. देश का ईसाई और मुस्लिम समाज तथा इनके सबसे कमज़ोर दलित वर्ग के लोग अभी कितने ख़ून के आंसू गिराएंगे, कहा नहीं जा सकता और इसकी ज़िम्मेदारी राज्यसभा के सभापति की होगी.

.... महामहिम सभापति राज्यसभा जी, राज्यसभा सदस्यों को कमज़ोर और नपुंसक मत बनाइए, इनकी मांगों पर ध्यान दीजिए और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को सदन के पटल पर पेश कराइए. क्योंकि जब तक रिपोर्ट पेश नहीं होगी, सरकार बताएगी नहीं कि वह इस पर क्या कार्रवाई करने जा रही है. जिस मांग के समर्थन में सारे दलों के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, दलों के घोषणापत्र हों, उस मांग को अनदेखा कर, सरकार को निर्देश न दे, आप उस विचारधारा का भी अपमान कर रहे हैं जिसने आपको राज्यसभा के सभापति पद तक पहुंचाया है.

राज्यसभा के सदस्यों को शायद इस बात का अहसास होगा कि देश की जनता सर्वोपरि है और उसके कमज़ोर वर्गों की आवाज़ और उसके हितों को अनदेखा करने का काम यदि ये ख़ुद करेंगे तो उनसे सवाल पूछने का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आज़ाद और निर्भीक प्रेस करेगा. क्या यह रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हो पाएगी माननीय सभापति जी राज्यसभा, और क्या माननीय राज्यसभा सदस्यों आप में अभी भी कुछ ताक़त या शर्म बची है जो आप लोकसभा सदस्यों की तरह, जैसे उन्होंने लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पेश करवा ली, रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश करवा सकते हैं?

मैंने उपसभापति महोदय के बारे में लिखा कि

चौबीस नवंबर का दिन राज्यसभा के इतिहास में दु:खद दिन के रूप में देश के लोग याद करेंगे. उस दिन राज्यसभा के सदस्यों ने मांग की कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए. यह मांग अनसुनी कर दी गई, तब सदस्यों ने हंगामा किया. दो बार के स्थगन के बाद सदस्यों को दो–दो मिनट बोलने की इजाज़त दी गई, जिसमें सभी सदस्यों ने कहा कि जब रिपोर्ट चौथी दुनिया ने छाप दी है

तो क्यों इसे टेबल नहीं किया जाता. पहली बार चेयर पर सभापति थे और दूसरी बार उप सभापति.

मैंने राज्यसभा के सदस्यों के बारे में ये बातें लिखीं

राज्यसभा सर्वशक्तिमान है. राज्यसभा में देश के चुने हुए बुद्धिजीवी, लोकतंत्र के प्रहरी माने जाने वाले नागरिक, संविधानविद्, वरिष्ठव्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, सदस्य होते हैं. उनके चुनाव में यद्यपि राजनैतिक दलों की भूमिका होती है, पर माना जाता है कि देश की बुनियादी समस्याओं पर उनका रुख़ कमोबेश एक जैसा ही होगा और वे दलों के दलालों की तरह नहीं, देश के लोकतंत्र के प्रहरी और जनता के हितों के पहरुओं की तरह काम करेंगे. यह सर्वशक्तिमान राज्यसभा कमज़ोरों का जमावड़ा बन गई है. देश के ऐसे लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, जिनके पास आवाज़ उठाने की ताक़त नहीं है.

उस दिन राज्यसभा के सदस्यों ने मांग की कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए. यह मांग अनसुनी कर दी गई, तब सदस्यों ने हंगामा किया. दो बार के स्थगन के बाद सदस्यों को दो–दो मिनट बोलने की इजाज़त दी गई, जिसमें सभी सदस्यों ने कहा कि जब रिपोर्ट चौथी दुनिया ने छाप दी है तो क्यों इसे टेबल नहीं किया जाता.

क्या हुआ राज्यसभा के सर्वशक्तिमान सांसदों की ताक़त का, लगभग हर दल के सांसद चाहते थे कि यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए, पर वे न सरकार को तैयार कर सके और न ही चेयर पर दबाव डाल सके. क्या राज्यसभा, जिस पर लोकतंत्र को संभालने की ज़िम्मेवारी है, उच्च सदन कहा जाता है, शक्तिहीनों और निर्वीर्य लोगों के बैठने का एक क्लब भर रह गया है? क्या राज्यसभा से जनता को अपना भरोसा ख़त्म कर लेना चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों को हम बताना चाहते हैं कि वे किस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को सदन में रखवाने में विफल रहे. ईसाई समाज और मुस्लिम समाज के दलितों को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए एम करुणानिधि ने प्रधानमंत्री को आठ फरवरी 2006 को एक पत्र लिखा, जिसका उत्तर प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2008 को दिया, जिसमें उन्होंने वायदा किया कि वे इन सवालों पर ध्यान देंगे. प्रकाश करात ने 11 अगस्त 2005 में, मायावती ने 2 सितंबर 2005 और 30 अगस्त 2007 में दो बार प्रधानमंत्री को लिखा. रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 14 सितंबर 2007 और रामविलास पासवान ने रसायन व उर्वरक मंत्री के नाते 29 मई 2006 को प्रधानमंत्री को ख़त लिखा. श्रीमती जयललिता ने तो मुख्यमंत्री के नाते 28 नवंबर 1995 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिंहा राव को ख़त लिख दिया था. श्री ए बी वर्धन ने 8 अक्टूबर 2007 को डॉ. मैरी जान को लिखकर वायदा किया कि उनकी पार्टी के सांसद कांस्टीट्यूशन (शेड्यूलकास्ट) ऑर्डर 1950 अमेंडमेंट बिल 1996 सदन में रखने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी. जनता दल (यू) ने इस आशय का प्रस्ताव मई 2009 में पास किया. राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को हम पुन: बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को ख़त लिखे हैं, उन्हीं की इच्छा से आप इस माननीय सदन के सदस्य बने हैं. कम से कम उनकी इच्छा का मान तो रखिए. सबसे मज़ेदार बात है कि वर्तमान क़ानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन के नाते 6 अगस्त 2007 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ख़त लिखा, जिसे हम यहां छाप रहे हैं. अब वे ख़ुद क़ानून मंत्री हैं, क्या वे अपने ख़त और सोनिया गांधी के सम्मान के लिए इस रिपोर्ट को सदन में जल्दी से जल्दी रखेंगे? आंध्र प्रदेश के स्वर्गीय मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी ने सोनिया गांधी को ख़त लिखकर इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी.

हम इस ख़त को भी राज्यसभा के सदस्यों की जानकारी के लिए छाप रहे हैं.

महामहिम सभापति राज्यसभा जी, राज्यसभा सदस्यों को कमज़ोर और नपुंसक मत बनाइए, इनकी मांगों पर ध्यान दीजिए और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को सदन के पटल पर पेश कराइए. क्योंकि जब तक रिपोर्ट पेश नहीं होगी, सरकार बताएगी नहीं कि वह इस पर क्या कार्रवाई करने जा रही है. जिस मांग के समर्थन में सारे दलों के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, दलों के घोषणापत्र हों, उस मांग को अनदेखा कर, सरकार को निर्देश न दे, आप उस विचारधारा का भी अपमान कर रहे हैं जिसने आपको राज्यसभा के सभापति पद तक पहुंचाया है. राज्यसभा के सदस्यों को शायद इस बात का अहसास होगा कि देश की जनता सर्वोपरि है. और उसके कमज़ोर वर्गों की आवाज़ और उसके हितों को अनदेखा करने का काम यदि ये ख़ुद करेंगे तो उनसे सवाल पूछने का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आज़ाद और निर्भीक प्रेस करेगा. क्या यह रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हो पाएगी माननीय सभापति जी राज्यसभा, और क्या माननीय राज्यसभा सदस्यों आप में अभी भी कुछ ताक़त या शर्म बची है जो आप लोकसभा सदस्यों की तरह, जैसे उन्होंने लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पेश करवा ली, रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश करवा सकते हैं? क्या फ़र्क़ है दोनों में, दोनों कमीशन हैं, दोनों की रिपोर्ट अख़बारों में छपी, एक की अंग्रेज़ी में और एक की हिंदी में. क्या हिंदी के अख़बार में छपी रिपोर्ट की महत्ता कम हो जाती है? देश की जनता के कमज़ोर वर्ग, ईसाई और मुस्लिम समाज से जुड़े दलित सवाल का जवाब चाहते हैं. राज्यसभा के सदस्यों अली अनवर, अमर सिंह, सीताराम येचुरी, तारिक अनवर, वेंकैया नायडू, अहलूवालिया, जयंती नटराजन और डी राजा सहित उन सभी से सवाल कि रिपोर्ट पेश कराइए, नहीं तो जनता से माफ़ी मांगिए कि हम आपके विश्वास के लायक़ हैं.

महामहिम सभापति जी, ये शब्द अपमानजनक नहीं है. ये शब्द उन्हें अपमानजनक लगेंगे जिन्हें समाज की चिंता नहीं है. यह कर्तव्यबोध कराने वाले शब्द हैं और हमारा विश्वास है कि आप राज्यसभा के सदस्य ऐसी श्रेणी में नहीं आते.

महामहिम सभापति जी, ये घटना सात और आठ दिसंबर की है. आपने आठ दिसंबर को विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत किया और नौ दिसंबर को क्या हुआ? लोकसभा में तीस से ज़्यादा सांसद चौथी दुनिया को हाथ में लेकर खड़े हो गए, माननीय मीरा कुमार जी अध्यक्ष के आसन पर थी. प्रधानमंत्री जी को सासंदों की मांग पर सदन में कहना पड़ा कि वे इसी सत्र में सदन में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट रखेंगे और लोकसभा में यह रिपोर्ट सरकार को रखनी पड़ी. इससे पहले लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट भी लोकसभा के सदस्यों ने दवाब डाल कर सदन के पटल पर रखवा ली थी.

8. एक बार फिर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं संसद की गरिमा की पूरी इज़्ज़त करता हूं और मैं या मेरा अख़बार किसी भी परिस्थिति में सदन की अवहेलना या इसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा.

आशा है आप की शंका का समाधान हो गया होगा.
धन्यवाद
आपका

(संतोष भारतीय)

रैली में नीतीश पर हमला करने से भी पासवान नहीं चूके. उन्होंने कहा कि इस सरकार में इसी गांधी मैदान में तीन दिनों तक आरएसएस का सम्मेलन हुआ.

# बिहार में मुसलमान

मौलाना कल्बे रुशैद रिज़वी

सरोज सिंह

**मुस्लिम वोटों के लिए पासवान और नीतीश की तेज़ी को देखते हुए राजद खेमा भी सक्रिय हो गया है. मुस्लिम-यादव समीकरण के सहारे 15 सालों तक सत्ता में रहे राजद ने मुसलमानों को रिझाने के लिए एक और मोर्चा खोल दिया है. पार्टी की तरफ़ से माइनरिटी वेलफेयर फ्रंट अब मुसलमानों के बीच जागरुकता अभियान चलाएगा. लालू के क़रीबी अनवर अहमद उसके प्रमुख हैं.**

चुनावी साल में बिहार के दिग्गज नेताओं को एक बार फिर सूबे के डेढ़ करोड़ मुसलमानों का दर्द सताने लगा है. मुसलमानों की ग़रीबी, उनके बच्चों के न पढ़ पाने का दर्द और सत्ता में उनकी कम भागीदारी अचानक नेताओं के एजेंडे में ऊपर आ गई है. जगह-जगह रैलियों एवं सभाओं में मुसलमानों के सम्मान और कल्याण के लिए वादों की बौछार शुरू है. इन नेताओं की आंखों में अपना दर्द निहारने वाले मुसलमानों के हिस्से में क्या आएगा, यह तो समय बताएगा पर वोट की राजनीति करने वाले नेता यह गुना-भाग करने में मशगूल हैं कि उनकी पार्टी के हिस्से में मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे आएगा. अनुमान के मुताबिक़ नए परिसीमन के बाद सूबे की तीन दर्ज़न सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के भाग्य का फ़ैसला मुस्लिम वोटरों को ही करना है. सीमांचल के चार ज़िले किशनगंज, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार के अलावा सहरसा, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, भागलपुर सहित कई और ज़िलों में कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां मुस्लिम वोटरों को दरकिनार कर कोई भी प्रत्याशी विधानसभा पहुंचने की सोच भी नहीं सकता है. यही वजह है कि नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और लालू प्रसाद ने अभी से ही मुसलमानों को रिझाने के लिए कवायद शुरू कर दी है. मुस्लिम वोटों पर जहां लालू प्रसाद अपना स्वाभाविक दावा जताते हैं, वहीं नीतीश कुमार का कहना है कि मेरी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं. रामविलास पासवान का तर्क है कि बातें तो बहुत हुईं, लेकिन मुसलमानों को उनका वाजिब हक़ नहीं मिल सका है. लोजपा की मुस्लिम रैली में पासवान ने कहा कि आज़ादी के 63 साल बाद भी देश का मुसलमान डरा हुआ है. वह अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक समझता है. मुसलमानों की चिंता जल्द ख़त्म करने का आश्वासन देते हुए पासवान ने रैली में चुनावी तड़का लगाना शुरू कर दिया. बहुचर्चित चाबी वाले अपने बयान से कुछ अलग हटते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नई सरकार की चाबी अकलियतों के हाथ में होगी और जिस दिन अकलियतों ने हमारे गठबंधन के पक्ष में मन बना लिया, सत्ता में आने से हमें कोई नहीं रोक सकता है. रैली में नीतीश पर हमला करने से भी पासवान नहीं चूके. उन्होंने कहा कि इस सरकार में इसी गांधी मैदान में तीन दिनों तक आरएसएस का सम्मेलन हुआ. उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल सरकार ने रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए दस फ़ीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर दी, तो फिर केंद्र और बिहार सरकार को ऐसा करने में क्या परहेज है. रैली में मौलाना कल्बे रुशैद रिज़वी ने मुसलामानों का दर्द बयां कर महफिल लूट ली. उन्होंने कहा कि मुस्लिम रैली के बाद पासवान की अकलियतों की प्रति ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. चिलचिलाती धूप में बैठे मुसलमानों को हिंदुस्तान का सिपाही बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया यह समझ ले कि इस देश पर बुरी नज़र रखने वालों की आंखें निकालने में यहां का मुसलमान सबसे आगे रहेगा. सांसद साबिर अली ने भी मुसलमानों के साथ लगातार हो रही नाइंसाफ़ी का मुद्दा उठाया. कुल मिलाकर रैली के माध्यम से रामविलास पासवान ने मुसलमानों को यह संदेश देने की कोशिश की कि उन्हें ठगने वालों को लोजपा सबक सिखाएगी. अगर अकलियतों का वोट लोजपा के खाते में आ जाए तो उनके आंसू पोछने के लिए पार्टी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी. दरअसल दलित वोटों में नीतीश कुमार ने सेंध लगाकर पासवान के होश उड़ा दिए हैं. दलित राजनीति करने का दंभ भरने वाले पासवान को लगता है कि नीतीश का महादलित कार्ड लोजपा के सारे गणित को फेल कर सकता है. इन वोटों की खानापूर्ति मुस्लिम वोटों से करने की रणनीति पर अमल करते हुए सारे नेताओं द्वारा मुसलमानों से ढेर सारे वादे किए जा रहे हैं.

सत्ता में आने के बाद से ही नीतीश कुमार ने कोशिश शुरू कर दी थी कि भले ही भाजपा के साथ उनकी गठबंधन की सरकार है पर उनकी छवि धर्मनिरपेक्ष बनी रहे. मुस्लिम बहुल इलाक़ों में जब भी वह गए इस बात को दोहराना न भूले कि उनके कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ. अल्पसंख्यकों की शिक्षा और रोज़गार के अलावा अन्य शुरू किए गए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नीतीश कुमार बताना नहीं भूलते. मुस्लिम रैली के माध्यम से जब पासवान अकलियतों के नज़दीक आने में जुटे तो नीतीश कुमार ने तुरंत पसमांदा मुसलमानों को आरक्षण देने का तीर चला दिया. जहानाबाद में मुस्लिम फलाही बेदारी कांफ्रेंस में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के दर्द को सहलाते हुए कहा कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ग़रीबी से त्रस्त है. इसलिए विकास में उनका विशेष हक़ होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी से चाहता हूं कि समाज का हर तबका विकास का स्वाद चखे. नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए 19 कार्यक्रम चला रखे हैं. दरअसल जिन अगड़ी जातियों ने नीतीश को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था, उनका कितना साथ इस चुनाव में उन्हें मिलेगा यह दुविधा जदयू के लिए चिंता का विषय है. खासकर ललन प्रकरण के बाद यह चिंता कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है. इसलिए पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुस्लिम वोटों में सेंधमारी का अभियान तेज़ कर दिया जाए. पसमांदा मुसलमानों को आरक्षण की बात कहकर नीतीश ने बड़ा दांव खेला है. सूत्रों पर भरोसा करें तो अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को और निखारने के लिए नीतीश आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक जोख़िम भी उठा सकते हैं.

मुस्लिम वोटों के लिए पासवान और नीतीश की तेज़ी को देखते हुए राजद खेमा भी सक्रिय हो गया है. मुस्लिम-यादव समीकरण के सहारे 15 सालों तक सत्ता में रहे राजद ने मुसलमानों को रिझाने के लिए एक और मोर्चा खोल दिया है. पार्टी की तरफ़ से माइनरिटी वेलफेयर फ्रंट अब मुसलमानों के बीच जागरुकता अभियान चलाएगा. लालू के क़रीबी अनवर अहमद उसके प्रमुख हैं. अनवर राजधानी से लेकर पंचायत स्तर तक कार्यक्रम चलाकर मुसलमानों को उनके हक़ के बारे में बताएंगे. राजद का साफ़ कहना है कि नीतीश ने मुसलमानों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं. वे बस काग़ज़ों पर हैं. बजट में करोड़ों रुपए का प्रावधान है पर अल्पसंख्यकों के हित में उसे ख़र्च नहीं किया जा रहा है. ख़तरा कांग्रेस की तरफ़ से भी लग रहा है. इसलिए राजद ने पहले से ही सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कांग्रेस को बेनकाब करने का अभियान चला रखा है. लोकसभा चुनाव में माय समीकरण के बिखराव से लगे झटके से लालू चौकन्ना हो गए हैं और चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनके माय समीकरण में कोई सेंध न लगे. बहरहाल मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए मची होड़ में कौन आगे निकलेगा यह तो आने वाला समय बताएगा पर इतना तो साफ़ है कि इस होड़ में जो आगे निकलेगा, सत्ता उसी के ज़्यादा क़रीब होगी.

feedback@chauthiduniya.com

आज हम ग्लोबल वॉर्मिंग से जुड़े क़ानूनों को एक व्यवस्थित स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समस्या यह है कि इस मामले में पहले से बने क़ानूनों और परंपराओं का नितांत अभाव है.



# ग्लोबल वॉर्मिंग
# क़ानूनी पहलू और अंतरराष्ट्रीय समुदाय

जस्टिस पी. सथाशिवम

पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, उनके कारण देश भर में इस विषय पर गंभीर बहस चलने लगी है. इन बदलावों को नियमित करने वाले क़ानून पर्यावरण से जुड़े विस्तृत न्याय व्यवस्था का एक हिस्सा हैं. इस संदर्भ में आम राय यह है कि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे है और जिसको नियंत्रित करने की दिशा में हर राष्ट्र को पहल करनी चाहिए. इसके लिए प्रत्येक देश को आगे आना चाहिए. कई साल पहले 1972 के स्टॉकहोम घोषणपत्र के सिद्धांत 21 में अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण क़ानून को विस्तृत रूप से जगह मिली. ग्लोबल वॉर्मिंग को नियंत्रित करने के मामले में अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के लिहाज़ से अच्छे पड़ोसियों की तरह व्यवहार या पड़ोसी धर्म का निर्वाह सबसे अहम है.

आज हम ग्लोबल वॉर्मिंग से जुड़े क़ानूनों को एक व्यवस्थित स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समस्या यह है कि इस मामले में पहले से बने क़ानूनों और परंपराओं का नितांत अभाव है. इसकी वजह यह है कि प्रदूषण ऐसी समस्या है जो आधुनिक युग में विज्ञान के विकास के साथ लगातार गंभीर रूप धारण करता जा रहा है. मानव समुदाय इससे पहले प्रदूषण की समस्या से इस स्तर पर कभी दो-चार नहीं हुआ था . ज़ाहिर है, इससे संबंधित क़ानूनों की ज़रुरत भी पहले महसूस नहीं की गई होगी. इस नज़रिए से देखा जाए तो यह ज़रूरी हो जाता है कि प्रदूषण से निपटने के लिए क़ानूनी तैयारी के लिए आण्विक हथियारों के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के विचारों और अन्य पर्यावरणीय क़ानूनों को एक साथ जोड़कर देखा जाए.

## पर्यावरण के परिवर्तन से निबटने की दिशा में पहला क़दम

वायु प्रदूषण और मानवीय कार्यों से पर्यावरण में बदलाव के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का पहला संगठित प्रयास जेनेवा कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन, जिसे अक्सर सीएलआरटीएपी के नाम से पुकारा जाता है, के रूप में हमारे सामने आया. यह मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के ख़िलाफ़ विश्व समुदाय को तैयार करने के लिए आयोजित किया गया था. पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाना और धीरे-धीरे इसे पूरी तरह ख़त्म करना इसका उद्देश्य था. जेनेवा कन्वेंशन के आयोजन के पीछे दो महत्वपूर्ण कारक थे. इसकी सबसे बड़ी वजह थी दुनिया भर में, और ख़ासकर यूरोप में पैदा हो रही पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे तालाबों, झीलों आदि का सूखना या पानी का गंदा होना आदि, और वैज्ञानिकों की एकमत राय कि इसके लिए वायु प्रदूषण ज़िम्मेदार है. इसकी दूसरी वजह थी 1972 में युनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एंवायरेन्मेंट इन स्टॉकहोम (स्टॉकहोम कन्वेंशन) के आयोजन के सिलसिले में दुनिया भर के नीति-निर्माताओं का एक मंच पर जमा होना. हालांकि, यह कहना बेमानी नहीं होगा कि ग्लोबल वॉर्मिंग के बड़े ख़तरे से निबटने के लिए स्टॉकहोम घोषणापत्र में कुछ ख़ास नहीं कहा गया. 51 सदस्यों की सहभागिता वाले इस सम्मेलन ने सल्फर और नाइट्रोजन उत्सर्जन जैसे पर्यावरण पर बुरा असर डालने वाले कई मुद्दों पर विचार किया, लेकिन ग्लोबल वॉर्मिंग का ख़तरा जिस गंभीरता के साथ हमारे सामने मुंह बाये खड़ा है, उससे मुक़ाबला करने के लिए इसमें कुछ ख़ास व्यवस्था नहीं की गई.

इस दिशा में दूसरा क़दम 1985 में वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के रूप में सामने आया. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य के साथ यह बहुपक्षीय कन्वेंशन 1988 में प्रभावी हुआ. हालांकि, इसके प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे सदस्य देशों को ओजोन लेयर में कमी के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार क्लोरो फ्लोरो कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ज़रूरी क़दम उठाने के लिए क़ानूनी रूप से बाध्य ठहराया जा सके, लेकिन इतना ज़रूर था कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा संगठित प्रयास की ज़रूरत को इसने रेखांकित किया. कन्वेंशन की प्रस्तावना में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समेकित प्रयास की ज़रूरत पर बल दिया गया था. सम्मेलन में विकासशील देशों की समस्याओं पर ख़ास तौर पर बल दिया गया, जिन्हें विकसित देशों के मुक़ाबले प्राकृतिक आपदाओं का ज़्यादा सामना करना पड़ता है. किसी भी मानवीय गतिविधि से पर्यावरण और ओजोन लेयर पर पड़ने वाले असर से मुक़ाबला करने के लिए आपसी सहयोग से नीतियों के निर्माण और उसे लागू करने के लिए एकमत होने की ज़रूरत पर बल दिया गया (धारा 2 (1 )(2) ). इसी के साथ जारी किए गए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में ओजोन परत को कमज़ोर करने वाले तत्वों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ज़रूरी उपायों और सभी संबद्ध पक्षों के दायित्वों को भी रेखांकित किया गया.

ओजोन परतों के बचाव के लिए वियना सम्मेलन (1985 में अनुमोदन और 1988 से प्रभावी) पारित कुछ ख़ास प्रस्ताव इस प्रकार हैं-

1. सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हर ऐसे मानवीय गतिविधि से बचाना है, जिससे अभी या भविष्य में ओजोन की परतों के कमज़ोर होने का ख़तरा है. यह उम्मीद की जाती है कि सभी संबद्ध पक्ष सम्मेलन के प्रस्तावों के अनुरूप इस दिशा में ज़रूरी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.

2. इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सभी संबद्ध पक्षों से यह उम्मीद की जाती है कि - वे मानवीय कार्यों से ओजोन लेयर पर पड़ने वाले असर और इससे पैदा होने वाली समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने की दिशा में आपसी सहयोग करेंगे, ओजोन लेयर को प्रभावित करने वाले कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी क़दम उठाने और नीतियों के निर्माण में आपसी सहयोग करेंगे. इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि कन्वेंशन के प्रस्तावों को लागू करने के लिए ज़रूरी क़दम उठाए जाएंगे और इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी सहयोग करेंगे.

मांट्रियल सम्मेलन में भी अनेक पदार्थों पर ओजोन की परतों के कारण पड़ने वाले प्रभाव ( जो 1987 में अनुमोदित हुए और 1989 से प्रभावी ) की चर्चा की गई थी.

1. ओजोन परतों के कारण अनेक पदार्थों पर पड़ने वाले प्रभावों पर मांट्रियल में जो प्रस्ताव पारित किए गए वे वियना कन्वेंशन का ही एक हिस्सा हैं. इसका उद्देश्य ओजोन लेयर को कमज़ोर करने वाले व्यावसायिक और पर्यावरण के लिहाज़ से महत्वपूर्ण तत्वों के उत्पादन और उनके इस्तेमाल को नियंत्रित करना है. ऐसे तत्वों के नाम प्रोटोकॉल के अनुलग्नकों में शामिल हैं. मॉन्ट्रियल सम्मेलन की सबसे बड़ी ख़ासियत है, धारा 6, जिसके तहत 1990 से हर चार साल बाद ओजोन लेयर को सुरक्षित रखने हेतु उठाए गए उपायों की समीक्षा आवश्यक है. इस समीक्षा में ओजोन परतों की कमज़ोरी से संबंधित प्रत्येक तथ्यों, चाहे वे वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, तकनीकी या आर्थिक हों, को ध्यान में रखना ज़रूरी है. गौरतलब है कि समस्या के बदलते स्वरूप और विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों एवं विकासशील देशों की ख़ास ज़रूरतों के मद्देनजर प्रस्तावों को दो बार संशोधित किया भी जा चुका है.

2. मॉन्ट्रियल सम्मेलन से संबद्ध पक्षों ने पारित प्रस्तावों को व्यावहारिक बनाने के लिए अब इसके स्वरूप में पांच बार बदलाव किए हैं. ये हैं लंदन संशोधन (1990), कोपेनहेगन संशोधन (1992), वियना (1995), मॉन्ट्रियल (1997) और बीजिंग (1999). लंदन संशोधन में तकनीकों के हस्तांतरण और इसके आर्थिक पहलुओं में बदलाव किया गया. प्रोटोकॉल के लिए एक बहुपक्षीय कोष का गठन किया गया जो 1992 के बाद वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एन्वॉरोन्मेंट प्रोग्राम (यूएनइपी), यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) और यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (यूएनआईडीओ) द्धारा संचालित एक स्थायी कोष बन गया. कोपेनहेगन संशोधन के अंतर्गत 1993 तक हैलॉन यौगिकों और 1995 तक हैलोकार्बन तत्वों के उत्पादन और उपभोग को समाप्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया.

## ग्लोबल वॉर्मिंग और अंतरराष्ट्रीय क़ानून

ग्लोबल वॉर्मिंग के गंभीर ख़तरे को नियंत्रित करने के लिए पहला बड़ा और सीधा क़दम 1992 के अर्थ समिट (यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एंवॉयरेन्मेंट एंड डेवलपमेंट) के रूप में सामने आया, जिसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है. अभूतपूर्व रूप से सफल रहे इस सम्मेलन में 172 देशों ने भाग लिया और इनमें से 108 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शरीक हुए. सम्मेलन में निम्न मुद्दों पर जोर दिया गया :

- उत्पादन के तरीक़ों की सिलसिलेवार समीक्षा, ख़ासकर गैसोलीन जैसे टॉक्सिक यौगिकों और रेडियोएक्टिव तत्वों और अन्य ज़हरीले अवशेषों का.
- ऊर्जा के मौजूदा स्त्रोतों से अलग ऐसे संसाधनों की तलाश करना जो पर्यावरण पर बुरा असर नहीं डालते हैं.
- आवागमन के नए साधनों पर जोर देना ताकि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के चलते होने वाले प्रदूषण में कमी हो और शहरों की प्रदूषित वायु से पैदा होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम किया जा सके.
- पानी की कमी की बढ़ती समस्या.

इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) का प्राथमिक उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को ऐसे स्तर पर नियंत्रित करना था जिससे ख़तरनाक मानवजनित कार्यों के चलते ओजोन लेयर को कमज़ोर होने से बचाया जा सके और वातावरण पर कोई ख़ास असर भी न पड़े.

कन्वेंशन के प्रावधान सदस्य देशों के लिए क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं माने जा सकते क्योंकि इसमें ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की कोई सीमा तय नहीं की गई है और न ही इस पर नज़र रखने के लिए किसी संस्था का गठन किया गया है. लेकिन इससे इसकी महत्ता कम नहीं होती क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो सदस्य देशों को इस संदर्भ में ज़रूरी क़दम उठाने के लिए और इस दिशा में भविष्य के लिए तैयारी करने हेतु प्रेरित करते हैं. दरअसल, कन्वेंशन में सदस्य राष्ट्रों को पर्यावरण सुरक्षा हेतु क़ानूनी ज़िम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन इसने इस दिशा में भविष्य में उठाए जाने वाले क़दमों की पृष्ठभूमि ज़रूर तैयार कर दी. इस लिहाज़ से क्योटो प्रोटोकॉल को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है. इसका सबसे पहला काम था ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और उसे कम करने के लिए नेशनल ग्रीनहाउस गैस इंवेंट्री का गठन करना जिसके आधार पर परिशिष्ट 1 में उल्लेखित देशों के लिए 1990 में ग्रीनहाउस गैसों के इस्तेमाल और उत्सर्जन की एक सीमा तय की गई और उन्हें इसमें कमी लाने की ज़िम्मेदारी दी गई. साथ ही यह भी कि उन्हें समय-समय पर इससे संबंधित पुनरीक्षित आंकड़े भी पेश करने की ज़िम्मेदारी दी गई.

*(लेखक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं )*

feedback@chauthiduniya.com

पान की फ़सल लगाने के लिए महाजन से लिए गए क़र्ज़ और बेटी के हाथ पीले करने का दर्द खेम चंद्र चौरसिया के चेहरे पर साफ़ दिख रहा है.



# पान किसानों पर मौसम की मार

सुरेंद्र अग्निहोत्री

लबों की शान बने बुंदेली पान की खेती उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी एवं महोबा और मध्य प्रदेश के सागर, छतरपुर एवं टीकमगढ़ आदि जनपदों में होती है. उत्पादन नगरी पाली ललितपुर में पान की खेती करने वाले किसान आज सरकारी उदासीनता और मौसम की बेरुख़ी के कारण उजाड़ ज़िंदगी जीने को अभिशप्त हैं. कमरतोड़ मेहनत के बाद पानी तलाश कर पानों के बरेजों को सींचने के लिए पत्थरों भरे रास्ते को हंसी- ख़ुशी पूरा करते हुए श्रम का फल पाने की उत्सुकता जब उछाल मार रही थी, तभी कालचक्र के क्रूर हाथों ने उम्मीदों पर तुषारापात कर दिया. अधिक ठंड ने पान के नाज़ुक पौधों को असमय काल कवलित कर किसानों को बर्बादी के भंवर जाल में फंसा दिया है. पान की फ़सल लगाने के लिए महाजन से लिए गए क़र्ज़ और बेटी के हाथ पीले करने का दर्द खेम चंद्र चौरसिया के चेहरे पर साफ़ दिख रहा है. राजाराम, हरि प्रसाद, हल्कू, दीना, घसीटे एवं रामू जैसे न जाने कितने किसान पान की फ़सल चौपट हो जाने के बाद इस उधेड़बुन में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि इस समस्या से निजात के लिए वे जाएं तो जाएं कहां? रामकली भी असमंजस की स्थिति में है कि उसे मिट्टी, अद्धों, फूस और टाट से बनाई गई कोठरी छोड़कर अब अपना पेट पालने के लिए कहीं पलायन करना होगा. पान भेजने के लिए बांस की टोकरी बनाकर अपना गुजर-बसर करने वाली रामकली इस वर्ष फसल बर्बाद हो जाने के डर से गुमसुम है. राम खिलावन को यह दर्द सता रहा है कि वह कल तक अपने खेतों में दिन-रात मेहनत करके परिवार को सम्मान के साथ जीने का हक़ देते थे, लेकिन अब वह किसके खेत में काम करेंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी पान की खेती के हुनरमंद चौरसिया परिवार सिर्फ़ यही काम जानते हैं. शहरों एवं महानगरों में मज़दूरी करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है. महोबा में भी पान कृषक कुछ-कुछ इन्हीं हालातों से जूझ रहे हैं. पांच वर्षों तक लगातार सूखे के बाद इस वर्ष उम्मीद की एक किरण जगी थी, लेकिन ठंड ने उसे भी छीन लिया. पान किसानों के साथ सरकारी रवैया भी अच्छा नहीं है. अनुदान तो दूर की बात, उन्हें फ़सल में लगने वाले कीट-पतंगों से बचाव के लिए भी कोई सुविधा नहीं दी जाती. पाली में पान किसानों के लिए खुला सरकारी संस्थान सफेद हाथी साबित हो रहा है. नई किस्में विकसित करना तो दूर की बात है, संरक्षण के अभाव में पान की अनेक दुर्लभ क़िस्में भी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं. राजा-महाराजाओं एवं नवाबों का शौक और लखनऊ, कानपुर एवं बनारस के लोगों की शान समझा जाने वाला चौरानी पान, जिसने विदेशों तक जाकर रानी के रूप में अपना सिक्का जमाया, वह आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है.

पाली एवं महोबा के देसी पान ने पाकिस्तान सहित विश्व के कई देशों में दस्तक देकर अपनी क्वालिटी के चलते एक अलग पहचान बनाई. लेकिन, हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और कोहरे के कारण इस वर्ष पाली का पान तबाह हो गया है. पाली में रहने वाले दो सौ से अधिक पान उत्पादक किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. पैदावार के लिए आवश्यक काली-दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र पाली में रहने वाले चौरसिया समाज ने दो सौ वर्ष पूर्व पान की खेती जैसे नाज़ुक और मेहनती काम की शुरुआत की थी. पान की फ़सल की बुआई फरवरी से अप्रैल के बीच होती है. इस दौरान किसान पान की बेलों को ज़मीन में रोपते हैं. इसके बाद जड़ों में सरसों की खली, राई एवं दही आदि डालते हैं. चूंकि यह एक नाज़ुक फ़सल मानी जाती है, इसलिए इसे सम मौसम की आवश्यकता होती है. यानी न ज़्यादा तेज धूप और न ही छाया. गर्म लू के थपेड़े, कड़ाके की ठंड और घना कोहरा इसके लिए घातक है. फ़सल को बचाने के लिए किसान घास-फूंस, सरकंडे एवं बांस बल्ली की सहायता से बरेजा तैयार करते हैं. बुआई के एक माह तक इन बेलों की सुबह-शाम सिंचाई करनी पड़ती है. किसान समीप स्थित छोटे कुओं से घड़ेनुमा लुटिया की सहायता से सिंचाई करते हैं. अक्टूबर-नवंबर तक पान की फ़सल पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है. यहां इतने बड़े आकार का पान पैदा होता है कि उसमें आप आराम से भोजन कर सकते हैं. यहां का देसी पान दिल्ली, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मथुरा, भोपाल, इंदौर, वाराणसी, इलाहाबाद एवं महोबा तक जाता है. इलाहाबाद, वाराणसी एवं महोबा के किसान यहां से पान के बीज भी ले जाते हैं. देसी पान दिल्ली के व्यापारियों के माध्यम से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक जाता है. पान के शौक़ीन लोग मुंहमांगी क़ीमत पर इसे ख़रीदने के लिए तैयार रहते हैं. लेकिन, विगत कुछ वर्षों से यहां के पान को किसी की नज़र लग गई है. साल दर साल कभी सूखा तो कभी अति वर्षा के कारण पान की फ़सल नष्ट होती रही. रही-सही कसर जंगली जानवरों ने पूरी कर दी. बरेजों में कभी रंजिशन तो कभी दुर्घटनावश लगी आग से लाखों रुपये के पान राख हो गए. दर्ज़नों किसान अपना सब कुछ लुटा बैठे. लाखों की लागत और कड़ी मेहनत के बावजूद इस तरह फसलें तबाह होने के कारण कई किसानों ने तो इससे तौबा कर ली और अपने पैतृक धंधे से मुंह मोड़कर वे इंदौर एवं भोपाल जैसे शहरों की ओर पलायन कर गए. पान की खेती तबाह करने में विभिन्न रोगों ने भी कोई कसर बाक़ी नहीं छोड़ी. आंधी-तूफ़ान और ओलों की बरसात ने भी ख़ूब तबाही मचाई. कड़ाके की ठंड का कहर भी पान की फ़सल पर टूटा. नतीजतन 70 प्रतिशत से अधिक फ़सल नष्ट हो गई. ठंड के कारण पान के पत्तों पर काले धब्बे एवं दाने पड़ गए हैं. बेल भी सूख गई है. पान की खेती से जुड़े हजारों किसान बुंदेलखंड से पलायन के लिए विवश हो रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा दिया गया विशेष पैकेज पान किसानों के लिए कोई राहत की सौगात लेकर नहीं आया है. हालांकि पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने किसानों को राहत दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल तो किसान दिक्कतों से जूझ रहे हैं.

पाली एवं महोबा के देसी पान ने पाकिस्तान सहित विश्व के कई देशों में दस्तक देकर अपनी क्वालिटी के चलते एक अलग पहचान बनाई. लेकिन, हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और कोहरे के कारण इस वर्ष पाली का पान तबाह हो गया है.

## कैसे होती है पान की खेती

ललितपुर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर पाली नगर पंचायत क्षेत्र में चौरसिया परिवारों का पान की खेती पर एकाधिकार है. पाली की जलवायु ऐसी है, जो 12 महीने पान की पैदावार के लिए सहायक सिद्ध होती है. इसके लिए काली मिट्टी, सम शीतोष्ण जलवायु चाहिए. यदि इसके बीज कहीं और ले जाकर लगा दिए जाएं तो वह बात नहीं बनती है. इसकी खाद में अलसी, मूंगफली और कुरंज के छिलके, अलसी का तेल और दही डाला जाता है.

## खासियत और तासीर

इसकी खासियत है कि आकार में बड़ा होने के साथ-साथ यह एक कड़क पापड़ की तरह होता है और मोड़ते ही टूट जाता है. यदि इसे खाकर मुंह में घुमाया जाए तो यह गोली जैसा बन जाता है. यह अपनी ठंडी तासीर के कारण गर्मी में ज्यादा खाया जाता है.

## पान खाने की परंपरा की वजह

कहा जाता है कि पान के बिना बड़ी से बड़ी दावत अधूरी रहती है. इसके पीछे कारण यह है कि मेहमानों को मान-मनुहार करके जब खूब खाना खिला दिया जाता है, तब पाचन की समस्या हल करने के लिए उन्हें पान दिया जाता है. पान के पत्ते से भोजन हजम हो जाता है. कत्थे से मुंह की दुर्गंध चली जाती है और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं. चूने से कैल्शियम की पूर्ति होती है. इलायची या लौंग मुख्यवास के साथ दांतों की सड़न रोकती है. पान के डंठल को अगर चबा लिया जाए तो खांसी दूर हो जाती है. जबकि आगे का कोना कामोत्तेजक होता है, इसीलिए इसे काटकर खाया जाता है. विज्ञान की दृष्टि से पान को पाइपेरीशिप फैमिली में रखा गया है. इसका वनस्पति नाम पाइपर बीटल है. पान में 125 औषधि तत्व पाए जाते हैं, जो कफ-पित्त नाशक, पाचक रसों से युक्त, प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर और कब्जियत दूर करने वाले होते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

राहुल गांधी के मुंह लगे नेताओं में से एक दिग्गी राजा अक्सर ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते रहते हैं, पर उनका आजतक कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सका.



# अब दिग्गी राजा सतर्क हो गए हैं

अजय कुमार

आजमगढ़ से गोरखपुर आते-आते कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा का सुर बदल गया. उनकी जुबान पर न तो आजमगढ़ जैसी तल्खी थी न ही किसी के ख़िलाफ़ बैर की भावना. ऐसा लग रहा था जैसे वह आजमगढ़ से गोरखपुर केवल डैमेज कंट्रोल करने आए थे.

दिल्ली में कांग्रेस की सरकार में हुए बटाला हाउस एनकाउंटर की विश्वसनीयता पर सवाल उठा कर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का जो खेल कांग्रेस के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने संजरपुर(आजमगढ़) से शुरू किया था, उसे और आगे बढ़ाने का साहस उनमें नहीं दिखा. वह 25 फरवरी को गोरखनाथ पहुंचे ज़रूर, पर आजमगढ़ वाली ग़लती उन्होंने यहां नहीं की. बल्कि उनका प्रयास रहा कि वह अपना सेक्युलरिज़्म वाला चेहरा बचाए रखें और उन पर दोबारा मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगे. इसीलिए दिग्गी राजा ने हिंदू व मुसलमान दोनों की ही रहनुमाई करने की कोशिश की. इसी कोशिश में वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में शिरकत करने से पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पहले नतमस्तक हुए. उसके बाद उन्होंने इमामबाड़ा जाकर चादरपोशी की. वहां उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता की बात की और कांग्रेस को मुसलमानों का सच्चा हितैषी बताया. इस बीच दिग्गी राजा अल्पसंख्यक सेमिनार में भाग लेने आए मेहमानों की खरी-खोटी भी सुनते रहे. पर इस सेमिनार में वह सच्चर कमेटी रूपी झुनझुने से अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने से अपने को रोक नहीं सके. सेमिनार में आए मौलवियों, उलेमाओं और मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने तो यहां तक कह दिया कि अफजल गुरु जैसे दहशतगर्दों को बीच चौराहे पर गोली मार दी जाए तो उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हमारे जवान बच्चों को सुकून से जीने दिया जाए. एक तरफ़ दिग्गी राजा मुसलमानों को लुभाने में लगे थे तो दूसरी तरफ़ कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने अलग पूर्वांचल के पक्ष में बयान देकर अमर सिंह की मुश्किलें बढ़ाने के लिए नया दांव खेला.

राहुल गांधी के मुंह लगे नेताओं में से एक दिग्गी राजा अक्सर ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते रहते हैं, पर उनका आजतक कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सका. कई बार तो नौबत यहां तक आ जाती है कि कांग्रेस उनके बयानों से अपने आप को अलग ही कर लेती है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर दिग्विजय बड़े-बड़े बोल बोलते ही जाते हैं. इतना ही नहीं वह अक्सर अपनी बात हाईकमान पर लाद भी देते हैं. अब अर्जुन सिंह तो राजनीति में क़रीब क़रीब रहे, नहीं तो दिग्गी राजा ने उनकी जगह लेने का जैसे व्रत ले रखा है. आख़िर दोनों एक ही राज्य और एक ही बिरादरी के जो हैं.

समाजवादी पार्टी की ओर मुसलमानों का झुकाव कम करने के उद्देश्य से दिग्गी राजा आजमगढ़ के संजरपुर गांव के बाद गोरखपुर पहुंचे तो उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा डा. रीता बहुगुणा, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी आदि भी मौजूद थे. गोरखपुर में उनके भाषण का सार मुसलमानों की ग़रीबी व अशिक्षा पर केंद्रित रहा. उन्होंने एक तरफ़ तो सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व का मामला उठाया तो दूसरी ओर प्रदेश की बसपा सरकार को निशाने पर लेते हुए यहां तक कह दिया कि संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि हम (केंद्र सरकार) सीधे कुछ कर नहीं सकते. केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकारें ठीक से कार्यान्वित नहीं कर रही हैं जिससे मुस्लिम समाज को सही लाभ नहीं मिल रहा है. वह यह भी कहने से नहीं चूके कि 2012 में होने वाले विधान सभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस के साथ आएं. उनके साथ आए केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने सरकार का पक्ष मुसलमानों के सामने रखते हुए बताया कि सरकार सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने चेताया कि गोरखपुर सांप्रदायिक शक्तियों के निशाने पर है. कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने तो मुसलमानों से माफी मांगते हुए यहां तक कह दिया कि पार्टी से ग़लतियां हुई हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए कांग्रेस सभी पार्टियों में बेहतर है. यदि केंद्र के 15 सूत्रीय कार्यक्रम लागू हो जाएं तो अल्पसंख्यकों की स्थिति बदल जाएगी. एक तरफ़ कांग्रेसी मुसलमानों को लुभाने में लगे थे तो दूसरी तरफ़ मुसलमानों की रहनुमाई का दम भरने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व सांसद परवेज हाशमी ने मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि मुसलमान चाहते हैं कि केंद्रीय मदरसा बोर्ड बने. पर यह बताते हुए परवेज हाशमी यह भूल गए कि दिल्ली में बैठकर मुसलमानों की राजनीति करने वाले अनेक मुस्लिम नेताओं ने मदरसा बोर्ड बनाने का ज़ोरदार विरोध भी दर्ज़ कराया हुआ है. उन्होंने आरएसएस और बजरंगदल पर दहशतगर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि दहशतगर्दी यह लोग फैलाते हैं और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं.

उनके दौरे के बाद समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायकों ने लखनऊ में एक बैठक के बाद दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली से संजरपुर की दूरी तय करने में आम आदमी को दो दिन का और वीवीआईपी को दो घंटे का समय लगता है. लेकिन हैरत की बात है कि दिग्विजय सिंह को दो साल लग गए. उन्होंने यहां तक कहा कि बाटला हाउस कांड के समय केंद्र और दिल्ली दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी. दिग्विजय सिंह के दौरे पर टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हृदय नारायण दीक्षित ने जानना चाहा कि बाटला हाउस कांड के आरोपी सैफ के पिता के घर जाने के बाद क्या उनका इरादा कसाब के घर भी जाने का है. उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को आतंकवाद समर्थक मान कर ही अफजल गुरु को अभी तक फांसी पर नहीं लटकाया है, जो देशभक्त मुसलमानों के लिए गहरा आघात है. कांग्रेस की इस मुहिम से आम मुसलमान दुखी हैं और उसकी प्रतिष्ठा गिरी है.

बहरहाल, कांग्रेस द्वारा आजमगढ़ में दिग्गी राजा के एनकांउटर से संबंधित बयान से अपने आप को अलग करने के बाद दिग्गी राजा ने गोरखपुर में अपना सुर बदलने में देरी नहीं की. पहले वह योगी आदित्य नाथ पर हमला बोल रहे थे लेकिन गोरखपुर पहुंच कर उन्होंने भाषा बदल दी. इसके उलट दिग्गी राजा डा. रीता बहुगुणा जोशी व पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के पुत्र अजय सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डा. सैयद जमाल आदि के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए. मंदिर में पूजा करने के बाद दिग्गी राजा सभी नेताओं के साथ गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ के पास जा पहुंचे. उनका आशीर्वाद लेकर उनसे बातचीत भी की. कुछ देर बाद दिग्गी राजा का क़ाफिला इमामबाड़ा पहुंचा. वहां उन्होंने बाबा रोशन अली शाह की मजार पर चादर चढ़ाई. इतना ही नहीं अल्पसंख्यक सम्मेलन में उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ पीठ और रोशन अली शाह की तारीफ़ के पुल बांधे. यह भी कह दिया कि दोनों का इतिहास दलितों और पिछड़ों को जोड़ने वाला है, पर तब भी ऐसी परंपराओं वाली जगह पर हिंदू व मुसलमान बंटा हुआ क्यों है.

feedback@chauthiduniya.com

देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का एक हिस्सा होने के नाते आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोकतंत्र का आधार हरेक इंसान की ज़रूरतों और उम्मीदों पर खरा उतरना है.

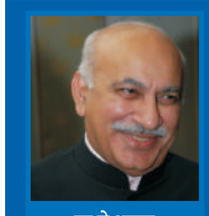

एम जे अकबर

# सर्विस इकोनोमी या सर्वेंट इकोनोमी

कुछ दिन पहले प्रकाशित एक किताब के मुताबिक़ आज से सौ साल पहले इंग्लैंड में घरेलू नौकर रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत था. साधारण सा दिखने वाला यह तथ्य एक वर्ग-आधारित समाज में व्याप्त असमानता का सटीक चित्रण करता है और विक्टोरियन एवं उसके बाद के समाज में धन और सत्ता के बीच नजदीकी रिश्तों के बारे में भी बताता है. औद्योगिक युग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वह इतना विकसित नहीं हुआ था कि वर्किंग क्लास का विस्तार हो और लेबर पार्टी की लोकप्रियता बढ़े. ब्रिटेन का उच्चवर्ग नौकरों के साथ क्रूर नहीं था, लेकिन उसकी अपनी सीमायें थीं. किसी भी बड़े घर में नौकरों को खाने-पीने की पूरी आज़ादी थी लेकिन उन्हें नीचे बने घरों में ही रहना पड़ता था.

रूस में इस पुरानी सामाजिक व्यवस्था को एकबारगी ही उखाड़ कर फेंक दिया गया, लेकिन ब्रिटेन में यह धीरे-धीरे विकसित हुआ. हालांकि इसमें कई ख़ामियां थीं और पारंपरिक असमानता इसका एक अहम पहलू था.

ब्रिटिश लोकतंत्र को प्रधानमंत्री विलियम पिट ने नई दिशा दी. निम्न वर्ग के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला. संरक्षणशाही पर आधारित व्यवस्था के ख़ात्मे से पहले दो विश्व युद्ध हुए और अमीरों के हित साधन में लगी ब्रिटिश राजशाही को और मज़बूत बनाने के लिए लाखों ग़रीब लोगों ने अपनी जान दी.

उन्नीसवीं शताब्दी के अमेरिकी समाज में नौकर नहीं थे. वहां दास प्रथा का प्रचलन था. आधिकारिक रूप से इसकी समाप्ति के बाद भी यह पूरी तरह से ख़त्म होने से पहले कई रूपों में अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था का एक अंग बना रहा. काले रंग के लोगों के प्रति ब्रिटिश नागिरकों का भी रवैया थोड़ा अलग था. रंगभेद का अस्तित्व कायम था, लेकिन इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल था. इसके लिए एक कथा कही जाती है. वह यह कि सैमुअल जॉनसन के पास एक पालतू बिल्ली थी और एक स्वामीभक्त जमैकन नौकर. लेकिन जॉनसन न तो नौकर को लेकर बाहर जा सकते थे न ही बिल्ली को साथ लेकर. इससे अघोषित तौर पर दोनों की ही प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती थी.

आधुनिक समय में अमेरिकी और यूरोपियन समाज में नौकर शब्द लोगों के ज़ेहन से करीब-करीब ग़ायब हो चुका है. सर्वेंट शब्द केवल सिविल सर्वेंट के साथ सुनाई पड़ता है, जो किसी भी हिसाब से नौकर तो नहीं ही हैं, उन्हें सिविल कहना भी बेमानी ही होगा. पश्चिमी आबादी का एक हिस्सा अभी भी घरों में काम कर अपना जीवनयापन करता है, इन देशों में इलीगल माइग्रेंट्स की बढती मांग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है. लेकिन अब इस पेशे के मायने बदल गए हैं, जो नौकरों के हक़ में हैं. मिड्ल क्लास चाह कर भी इनकी सेवायें नहीं ले सकता और उच्च वर्ग का भी एक छोटा

हिस्सा ही आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि इसका ख़र्च उठा सके.

हालांकि, ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है लेकिन मेरी धारणा यही है कि समकालीन भारतीय समाज में भी घरेलू नौकर का काम रोज़गार का सबसे बड़ा साधन है. इस लिहाज़ से देखें तो हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां आज से सौ साल पहले इंग्लैंड खड़ा था. सर्विस इकोनॉमी और सर्वेंट इकोनॉमी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है. भारत सर्विस इकोनॉमी होने का दावा करता है, लेकिन हम मूल रूप से अभी भी सर्वेंट इकोनॉमी में ही जी रहे हैं. घरेलू नौकरों का यह वर्ग भारत की आधी से ज़्यादा आबादी की आशाओं का प्रतिनिधित्व करता है.

देश में, ख़ासकर तेज़ी से आगे बढ रहे शहरी समाज में इसको लेकर तनाव स्पष्ट नज़र आता है. इसकी बड़ी वजह यह है कि समाज के इस वर्ग की मानसिकता में दया, करूणा जैसे शब्दों के लिए ज्यादा जगह नहीं है. नौकर न केवल हमारी सेवा करता है, बल्कि आधुनिक दौर में वह हमारे लिए ख़तरनाक भी बनता जा रहा है, क्योंकि वह भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हमसे बहुत अलग है. वह हमारे बर्तनों को धोने को तो मजबूर है, क्योंकि यह उसकी ज़रूरत है. लेकिन इसके एवज में उसे मिलनेवाला मेहनताना बहुत कम होता है और व्यवहार बहुत बुरा. नौकरों के द्वारा किए गए अपराधों को मीडिया में प्रमुखता से जगह मिलती है, लेकिन ख़ुद उनके साथ होने वाली हिंसा को कोई तवज्ज़ो नहीं मिलती. इसकी वजह शायद यह है कि पत्रकार भी इसी मिड्ल क्लास का हिस्सा हैं और नौकरों के ख़िलाफ़ हिंसा में उनकी भी भागीदारी होती है.

पश्चिमी देशों में घर का काम करने के लिए नौकरों की जगह रोबोट मशीनों का विकास किया जा रहा है और नौकरों का यह वर्ग तेज़ी से मध्य वर्ग का एक हिस्सा बनता जा रहा है- यह मानते हुए कि भोजन, वस्त्र, आवास जैसी प्राथमिक ज़रूरतों के लिए उनके पास साधन उपलब्ध हैं. लेकिन भारत में मशीनों के इस्तेमाल का नज़रिया भी थोड़ा अलग है. हम वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए भी नौकर रखते हैं. जो इन मशीनों को ख़रीद नहीं सकते, वह भी कपड़े धोने के लिए नौकर रखना पसंद करते हैं. यह संक्रमण का दौर है और इस हालत में ऐसी परिस्थितियां स्वाभाविक भी हैं, लेकिन सामाजिक विकास की जो तेज़ गति हमें दिखाई देती है, उसकी वास्तविकता संदाहास्पद है.

नौकरों के एक छोटे तबके में अपनी तकदीर के प्रति असंतोष को साफ देखा जा सकता है, ख़ासकर उनमें जो इसे स्वीकार नहीं करते. लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा अपनी आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट नहीं है. वो तो इससे ही खुश है कि ज़्यादा मेहनत और कम मेहनताना के बावजूद उसे भूखे नहीं सोना पड़ता. लेकिन सही मायने में देखा जाए तो यह अवस्था समाज की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिसे किसी भी हाल में अच्छा नहीं कहा जा सकता.

हालांकि, इस सबके बीच जो अच्छी चीज है वह यह कि प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन जैसी सेवाओं की कीमत बढ रही है. स्किल की बढ़ी क़ीमत धन के हस्तांतरण की ओर इशारा करता है. कई लोग दबी ज़ुबान से यह मानते हैं कि भारत एक आधुनिक समाज तब तक नहीं बन सकता जब तक कि देश में सिविल सर्वेंट मौजूद हैं. मेरा दावा है कि हमारा देश तब तक एक मॉडर्न इकोनॉमी नहीं बन सकता जब तक कि घरेलू काम करने वाले लोगों को भी सर्विस सेक्टर का एक हिस्सा माना जाए और उनके मेहनताने का स्तर सरकारी कर्मचारियों के शुरुआती वेतन के समतुल्य हो.

feedback@chauthiduniya.com

डॉ. मंज़ूर आलम

# महिला आरक्षण विधेयक को लेकर इतनी जल्दबाज़ी क्यों

आदरणीय सोनिया गांधी जी,

यह पत्र मैं एक ख़ास वजह से लिख रहा हूं या कहें तो मेरी निराशा और मेरी मजबूरी का एक परिणाम है ये. मैं यह देखकर व्यथित हूं कि किस तरह बहुमत के ज़ोर पर महिला आरक्षण बिल को जल्दबाज़ी में हमारे उपर थोपा जा रहा है. यह देश की तीस प्रतिशत जनसंख्या के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है, आबादी के ऐसे तबके से जुड़ा है, जो हमेशा से शोषित और पीड़ित रही है और इस बिल के माध्यम से उसके और ज़्यादा शोषण की ज़मीन तैयार की करने की कोशिश हो रही है. इसे बहुमत के ज़ोर पर तानाशाही नहीं तो और भला क्या कहेंगे.

देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का एक हिस्सा होने के नाते आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोकतंत्र का आधार हरेक इंसान की ज़रूरतों और उम्मीदों पर खरा उतरना है. लेकिन यहां तो तीस प्रतिशत आबादी के दौड़ में पीछे छूट जाने का ख़तरा है.

हालांकि, मैं पहले ही स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम इस विधेयक के ख़िलाफ़ नहीं हैं. लेकिन हमारी सोच के मुताबिक़ यहां सवाल लिंग भेद से ज़्यादा वर्ग भेद का है. बिल के मौजूदा स्वरूप में आबादी के उसी वर्ग के महिला आरक्षण का लाभ लेकर संसद की सीटों पर क़ाबिज़ हो जाने का ख़तरा है, जिसके पुरूष सदस्य पहले से ही सत्ता प्रतिष्ठान के केंद्र में क़ाबिज़ है. ऐसी हालत में तो वर्गभेद की खाई और चौड़ी हो जाएगी.

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसद के पटल पर विधेयक को मिला समर्थन वास्तव में एक धोखा है और यह लोगों की वास्तविक इच्छाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता. इसको समर्थन देने वाले राजनीतिक दल अपनी बाध्यताओं के चलते इसका समर्थन करने को मजबूर हैं. अगले लोकसभा चुनावों के बाद संभव है, राजनीतिक समीकरणों में बदलाव हो और तब हमें यह अहसास होगा कि हमने दलित और मुस्लिम महिलाओं के एक बड़े वर्ग के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है.

मुस्लिम, दलित और समाज के अन्य कमजोर तबकों ने बार-बार आपके नेतृत्व और आपकी पारदर्शिता में अपना भरोसा जताया है, आपको अपना रहनुमा माना है. ऐसे में यदि अपनी भलाई से जुड़े सामाजिक, शैक्षिक और सत्ता में हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर वह यूपीए सरकार से पारदर्शी और ज़िम्मेदार व्यवहार की उम्मीद रखती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है.

लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार से आगे निकलने की लगातार कोशिश करती नज़र आई है, वह हमारे लिए चिंता का विषय है. भाजपा ने पहले तो महंगाई के मुद्दे पर पूरे विपक्ष को सरकार के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया और फिर महिला आरक्षण के सवाल पर लोकसभा में सरकार के समर्थन में खड़ी हो गई.

जैसा कि आप ख़ुद भी जानती हैं, मुस्लिम और दलित महिलाओं का यह वर्ग विधेयक के प्रावधानों से संतुष्ट नहीं है. उनका अंदेशा है कि मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत समाज का वही वर्ग इसका ज़्यादा फ़ायदा उठायेगा जो पहले से ही सत्ता के क़रीब है. लिंग के आधार पर समानता की वकालत पूरे समाज के हित में है, लेकिन वर्ग भेद को बढ़ावा देना किसी हालत में समाज के हित में नहीं है.

बिल के मौजूदा स्वरूप में शोषित और पीड़ित महिलाएं इसका कितना फ़ायदा उठा पाएंगी, यह संदेह का विषय है. यही वजह है कि हम कोटा के भीतर कोटे की मांग कर रहे हैं ताकि पीड़ित और उपेक्षित महिलाओं का यह वर्ग भी महिला सशक्तिकरण आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चल सके.

दुख की बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा में भाजपा का साथ देने के लिए धर्मनिरपेक्ष दलों की आलोचना की, लेकिन महिला विधेयक पर उसी भाजपा का सहयोग लेने में उसे कोई झिझक नहीं हुई. ताज्जुब की बात तो यह है कि दोनों हालतों में फ़ायदा भाजपा को ही हुआ.

अब जबकि महिला आरक्षण विधेयक को हर हाल में लोकसभा की मंजूरी दिलाने के लिए सरकार दुश्मनों से भी हाथ मिलाने को तैयार है, समाज के पिछड़े वर्गों के बीच फैले निराशा की सहज ही कल्पना की जा सकती है. साथ ही, यह कमजोर और उपेक्षित लोगों के साथ खड़े होने के यूपीए सरकार के दावों की भी असलियत सामने लाता है.

यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा और सिद्धांतों की दुहाई देते हुए हम आपसे विधेयक के प्रावधानों की दोबारा समीक्षा करने की मांग करते हैं ताकि महिला सशक्तिकरण की आड़ में वर्ग भेद को बझाने वाला एक और कानून हमारे गले न पड़ जाए. हम देश के राजनीतिक नेतृत्व से इस पर पुनर्विचार की उम्मीद रखते हैं, ताकि उन्हें बाद में अपने किए पर पछताना न पड़े.

आख़िर में, मैं फिर से यह बताना चाहूंगा कि हम महिला आरक्षण विधेयक के ख़िलाफ़ नहीं हैं. हम आपसे केवल यह अपील करना चाहते हैं कि जल्दबाजी में कोई कदम न उठायें और समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलावों पर विचार करें.

**डॉ. मंज़ूर आलम**

*महासचिव, आल इंडिया मिल्ली काउंसिल*

## आख़िर है क्या तमाशा?

आपसे विनमे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र को छापकर पाठकों को सच से रूबरू कराएं.मैं सभी अखबारों और पत्रिकाओं से नियमित रूप से जुड़ा रहता हूं. पिछले दिनों अचानक मेरी निगाह चौथी दुनिया पर पड़ी. मुझसे रूका नहीं गया. मैने शाहरूख और फॉक्स की कवर स्टोरी देखते ही कनाट प्लेस से झट से खरीद लिया. सच कहूं तो शाहरूख बहुत बड़ ड्रामेबाज हैं. घर पहुंच कर सारा लेख जिसे मनीष कुमार ने अपनी सुंदर कलम से सजाया है पढा. लेख पढकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही विचार पढ रहा हूं. एक सच्चे देश प्रेमी होने के नाते मेरी नजर में शाहरूख और एमएफ हुसैन दोनो ही देश के दुश्मन ज्यादा नजर आते हैं.. लेकिन इस देश में भेड़चाल की माफिक चलने वालों की तादाद अधिक है. दूसरी ओर संतोष भारतीय ने भी अमन की आशा विषय पर अपने तीखे प्रहार किए और अपने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज पर करारी चोट की.

**डॉ साक्षात भसीन ( कवि, गीतकार)**

*487, करोल बाग, दिल्ली*

## महिला क्रिकेट का बुरा हाल

खेल दुनिया में बेलिंडा क्लार्क के दोहरे शतक के बारे में पढकर अच्छा लगा. ताज्जुब की बात है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने वनडे मैचों में दोहरा शतक लगाया तो अगले तीन दिनों तक अखबार से लेकर न्यूज चैनलों तक में इसके महिमामंडन की होड़ लगी रही, लेकिन किसी ने भी क्लार्क की चर्चा तक नहीं की. ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें इसकी जानकारी न हो. लेकिन हमारा पुरूषप्रधान समाज अक्सर महिलाओं की उपलब्धियों को छुपाकर रखने में ही गौरवान्वित महसूस करता है. कम ही लोगों को पता होगा कि महिलाओं की आईसीसी रैंकिंग में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही भारत की झूलन गोस्वामी और मिताली राज शीर्ष पर हैं. लेकिन गौतम गंभीर शीर्ष से खिसक कर चौथे नंबर पर सरक जाते हैं, तो इसे भी अखबारों में प्रमुखता से छापा जाता है. भारत में दूसरे खेल भले क्रिकेट को अपना सौतेला भाई मानते हों, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी सौतेली बहन एक ही है – महिला क्रिकेट.

**अनिता शर्मा,** *नांगलोई, नई दिल्ली*

## ऐसे बनते हैं सुपरस्टार

फिल्म माई नेम इज खान आज कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना रही है. देश से भी ज्यादा विदेशों में लोग इसे देखने के लिए थिएटरों पर टूट रहे हैं. सच तो यह है कि फिल्म रिलीज से पहले ही हिट हो चुकी थी जबकि इसमें ऐसी कोई खासियत नहीं थी. जाहिर है फिल्म की प्रमोशन टीम ने इसे हिट कराने के लिए मनचाहे हथकंडे अपनाए और ताज्जुब की बात है कि इसे सरकार भी नहीं समझ पाई. आपके कवर आलेख को पढकर बॉलीवुड में सुपरस्टारडम बरकरार रखने का गणित थोड़ा-बहुत समझ में आया.

रोहित राजपूत, सीकर, राजस्थान

## भविष्य की उम्मीद है जैविक खेती

बीटी बैगन के लिए मचे हो-हल्ले के बीच जैविक खेती पर आपका आलेख पढकर अच्छा लगा. इसकी जागरूकता बढाने की दिशा में मोरारका फाउंडेशन का प्रयास वास्तव में सराहनीय है. मीडिया को लोगों के ऐसे प्रयासों को सतह पर लाना चाहिए ताकि हम जान सकें कि एक प्रदूषणमुक्त और सुरक्षित जीवन के लिहाज से जैविक खेती बेहतर विकल्प है.

**आंचल द्विवेदी,** *इंदिरापुरम, गाजियाबाद*

## माई नेम इज ख़ान

चौथी दुनिया के 8 मार्च के अंक में आपने माई नेम इज खान को लेकर आपने को मुद्दा उठाया है, उसे हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए. यह सच है कि शाहरुख खान की चालाकी से उनके प्रचार में मीडिया के अनेक लोग जाने अनजाने सहयोगी बन गए. यह सही है कि जिन कुछेक अच्छी फिल्में शाहरुख खान के खाते में जाती हैं, उनमें माई नेम इज खान भी एक हो सकती है. इसके बावजूद इस फिल्म के बारे में प्रचार करते समय कम से कम मीडिया के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए थी. आपने इसे उठाया, इसके लिए बधाई.

**सौरभ सुगंध,** *शालीमार गार्डेन, साहिबाबाद, उप्र*

चौथी दुनिया ने देर से ही सही, एक अच्छा विषय उठाया है. अच्छी फिल्मों के दर्शक अब भी इस बात पर नजर रखते हैं कि कौन सा फिल्मकार कोई नया विषय लेकर बाजार में आता है. लेकिन किसी फिल्म के प्रोमोशन में अगर कोई सरकार अपनी पूरी मशीनरी के साथ लग जाए, तो उसके मूल उद्देश्य के बारे में शंका होने लगती है.

**राम सरोवर सिंह,** *बिवेक विहार, दिल्ली*

## बेहतर अख़बार

चौथी दुनिया अख़बार गजब का है इसे पढ़ने में काफी मज़ा आता है. इसमें स्टोरी और समाचार का संकलन भी बेहरतरीन है इस अख़बार को हार्दिक शुभकामनाएं, ये पहले जैसे अपना रुतबा हासिल करता जा रहा है.

**अखिलेश सिंह,** *लखनऊ, उत्तर प्रदेश*

## संक्षिप्त ख़बरों को भी जगह मिले

चौथी दुनिया को लोकप्रिय और जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा सुझाव है कि बड़े राजनीतिक समाचार को संक्षिप्त कर विभिन्न राज्यों की ख़बरों को भी प्राथमिकता दी जाए, राजनीतिक उठा पटक, भ्रष्टाचार, हिंसा और अपराध के स्थान पर समाज की सकारात्मक घटनाओं को भी प्रकाशित किया जाए.

**कंचन कुमार सिंह,** *हजारीबाग, झारखंड*

## बधाई

चौथी दुनिया 22 से 28 फरवरी 2010 के अंक में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परिशिष्ट देखकर सुखद आश्चर्य हुआ.यह उपहार देने के लिए आपको एवं आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं.

दिल वालों की दिल्ली के ग़रीबों की दुर्दशा देखकर चिराग तले अंधेरा वाली कहावत पूर्णतया चरितार्थ हुई. कृपया इन गंभीर विषयों के साथ हल्के फुल्के मनोरंजन की भी व्यवस्था करें, कार्टूनों की संख्या भी बढ़ाएं.

**रामदास धुसिया,** *जबलपुर*

## कब जागेगा प्रशासन

पिछले दिनों चौथी दुनिया अख़बार में शीला जी, कैसे ज़िंदा रहेंगे ग़रीब, लेख पढ़ा. लेखक ने दिल्ली की जनवितरण प्रणाली में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है साथ ही ग़रीबों के साथ हो रहे धोखे के बारे में भी बताया गया है और झूठे वायदों पर प्रकाश डाला गया है.

**अरुण सरोहा,** *दिल्ली विश्वविद्यालय*

## प्रधानमंत्री से अपील

जिस राज्य में कोई मंत्री करोड़ों का घोटाला कर सकता है, वहां झारखंड प्रदेश के धनबाद क्षेत्र में बीसीसीएल के अधिकारियों के ढीले ढाले रवैये के कारण एक मजदूर नंद लाल गोस्वामी के पुत्र पंकज गोस्वामी की जान चली गई. वह 4 मार्च से 7 मार्च तक खदान के अंदर गिरा पड़ा रहा, पर किसी ने उसकी परवाह नहीं की. क्या इसके लिए प्रधानमंत्री के स्तर पर किसी ठोस कदम की उम्मीद की जा सकती है?

**रवींद्र कुमार विश्वकर्मा**

*अध्यक्ष, माइंड पावर डेवलपमेंट, बरवाडा, धनबाद*

ठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

फ़ैसले के होने वाले असर की तर्कपूर्ण विवेचना किए बग़ैर इसे न्याय की कसौटी पर कसने की पीसीबी की कोशिश वास्तव में क़ाबिले तारीफ़ है.

## जब तोप मुक़ाबिल हो

# महिला बिल और नीतीश

संतोष भारतीय

महिला आरक्षण विधेयक ने भारतीय राजनीति में कुछ सफाई तो की है. इसमें पहली यह कि विधेयक बनाने वाला शख्स सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि कोई उसे पढ़ता ही नहीं है. महिला सीटें आरक्षित होंगी लेकिन फ्लोटिंग होंगी. इसका मतलब किसी भी चुनाव में जीती महिला सांसद अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होगी ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसे वहां से दोबारा लड़ना ही नहीं है. कैबिनेट ने इसे पढ़ा या नहीं, और अगर पढ़ा तो इसे कैबिनेट की समझ की बलिहारी माननी चाहिए.

इस बिल ने पार्टियों की तानाशाही भी जग ज़ाहिर कर दी. कम से कम भाजपा और कांग्रेस के सांसदों की दो तिहाई से ज़्यादा संख्या इस बिल के ख़िलाफ़ है. लेकिन दोनों दलों का नेतृत्व उनकी बात ही नहीं सुन रहा. सांसदों का विरोध महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर नहीं है बल्कि उनका कहना है कि गणेश की मूर्ति बनाते बनाते वे बंदर की मूर्ति बना रहे हैं. इंपावरमेंट या सशक्तीकरण के लिए संसद में भेजना अपरिपक्वता है, पहले उन्हें रोज़गार सहित हर स्तर पर तैंतीस प्रतिशत की हिस्सेदारी देने का क़ानून बनाना चाहिए.

किसी और दल में फूट इतनी ज़्यादा सतह पर नहीं आई, जितनी जनता दल (यू) में आ गई है. नीतीश कुमार बिल का समर्थन कर रहे हैं जब कि शरद यादव जी जान से विरोध. नीतीश के सामने बिहार का चुनाव है और बिहार में उन्होंने यह संदेश पहुंचा दिया है कि वे ऊंची जातियों के हित का ध्यान भी रख सकते हैं. अभी तक नीतीश के ख़िलाफ़ ऊंची जातियों का विरोध ही सामने आया है. भूमिहार और राजपूतों के नेता नीतीश कुमार से अलग हटने के रास्ते तलाशते दिखाई दे रहे हैं.

**लोग मानते हैं कि बिहार में भाजपा की नहीं, नीतीश कुमार की सरकार है. अगर शरद यादव या ललन सिंह के साथ रहने से उनकी पार्टी टूट जाती है, तो नीतीश को कोई घाटा नहीं होने वाला. नीतीश कुमार के साथियों का मानना है कि अगर लालू यादव व रामविलास पासवान मिलकर चुनाव लड़ते हैं और कहीं उनका कांग्रेस से समझौता हो जाता है, तो नीतीश कुमार अपने अकेले दम पर सरकार बना लेंगे**

लालू यादव के ख़िलाफ़ लड़ाई पी.के.शाही ने लड़ी तथा नाम उन्होंने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का रखा. दोनों ही भूमिहार हैं, और पी.के.शाही अभी एडवोकेट जनरल हैं. शुरू में नीतीश कुमार ने भूमिहारों को बहुत बढ़ावा दिया. अभयानंद एडीजी एडमिनिस्ट्रेशन थे. उन्होंने कुछ अपराधी कर्मियों को पकड़ा. इस पर अभयानंद को एडीजी, बिहार मिलिट्री पुलिस बना दिया. बिहार में इस पोस्ट को शंटिंग पोस्ट कहते हैं. अभयानंद को बिहार में साफ़ सुथरा चुनाव कराने का श्रेय जाता है, तथा लोग चाहते थे कि इन्हें डी.जी. बनाया जाए. अभयानंद की तस्वीर साफ़ सुथरी तो है ही, इनका नाम सुपर 30 चलाने वाली संस्था के जनक के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आईआईटी में परिणाम सौ प्रतिशत रहा है.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार के स्टैंडिंग काउंसिल गोपाल सिंह हैं, इनके पिता कांग्रेस से सांसद थे. ये भी भूमिहार हैं. भूमिहारों को तरजीह देते देख नीतीश से कुर्मी नाराज़ होने लगे. कुछ परिस्थितियां और कुछ नीतीश कुमार के काम करने का ढंग, ललन सिंह और उनमें दूरियां बढ़ीं. भूमिहारों को लगा कि पहले अभियान में ललन सिंह को नीतीश कुमार ने किनारे डाला, जब कि उस समय ललन सिंह बिहार जदयू के अध्यक्ष थे. भूमिहार नेताओं का कहना है कि ललन सिंह बिहार में झारखंड नेता के रुप में उभर रहे थे तथा मुंगेर में उनकी ज़बरदस्त जीत इसी वजह से हुई. प्रभुनाथ सिंह राजपूत हैं और उनकी भी दूरी नीतीश से बढ़ गई है. भूमिहार नेताओं का कहना है कि ललन सिंह का झारखंड नेता के रुप में उभरना नीतीश को ख़तरनाक लगा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई और भी दिखाई देने लगे. यह अलग बात है कि बिहार में डीजीपी भूमिहार हैं पर उनकी अहमियत नहीं है. अकेले त्रिपुरारी शरण हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेट्री फूड हैं और नीतीश कुमार के काफी नज़दीक हैं. त्रिपुरारी शरण दमदार अफसर माने जाते हैं. एक और भूमिहार है राजेश रंजन, जो आई जी हेडक्वार्टर हैं. इन्होंने ही हरियाणा के एपीएस राठौर को सीबीआई की मदद दिलवाई थी.

बिहार में कांग्रेस भूमिहारों को अपनी ड्राइविंग फोर्स के रूप में देख रही है. अनिल शर्मा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और भूमिहार समाज से आते हैं. कांग्रेस भूमिहारों को साथ लेना चाहती है. उधर ललन सिंह दस सांसदों के साथ हैं. उनके दोस्तों का कहना है कि अगर ममता से कांग्रेस का नाता टूटता है तो वे चौदह सांसदों के साथ कांग्रेस का समर्थन करेंगे, बशर्ते उन्हें रेल मंत्रालय मिले. ललन सिंह संसद के सेंट्रल हाल में खुले आम कांग्रेस महासिचव दिग्विजय सिंह से मिलते हैं और बिहार में क्या करना है इस पर बात करते दिखाई देते हैं.

कांग्रेस की बिहार में परेशानी यह है कि उसके पास कोई कद्दावर नेता नहीं है. कांग्रेस को मिलने वाला संपादित समर्थन यहीं रुक जाता है. जगदीश टाइटलर कांग्रेस को कोई शक्ल देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं.

यहीं इस महिला बिल ने नीतीश कुमार के सामने संभावनाओं के दरवाज़े खोल दिए हैं. लोग मानते हैं कि बिहार में भाजपा की नहीं, नीतीश कुमार की सरकार है. अगर शरद यादव या ललन सिंह के साथ रहने से उनकी पार्टी टूट जाती है, तो नीतीश को कोई घाटा नहीं होने वाला. नीतीश कुमार के साथियों का मानना है कि अगर लालू यादव व रामविलास पासवान मिलकर चुनाव लड़ते हैं और कहीं उनका कांग्रेस से समझौता हो जाता है, तो नीतीश कुमार अपने अकेले दम पर सरकार बना लेंगे. एक बड़ी वजह वे गिनाते हैं कि लालू यादव को सत्ता में आने की संभावना ही बिहार के अगड़ों को डरा देती है. इसलिए वे चाहें या न चाहें, उनका वोट नीतीश कुमार के पक्ष में ही जाएगा. नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण पंचायतों में किया है तथा ऐसी तस्वीर बनाई है कि वे ही विकास की गति बनाए रख सकते हैं. अगर उनसे कुछ सांसद टूटते भी हैं तो नीतीश को इसका फ़ायदा एक बड़े वोट के चंक के रुप में मिलेगा. अगर यह संभावना सच हो जाती है कि बिहार में कुछ महीनों पहले चुनाव हो सकता है तो फ़िलहाल लड़ाई मुस्लिम वोटों को लेकर होगी. लालू यादव पुराना मुस्लिम यादव समीकरण खड़ा करना चाहेंगे जिसमें पासवान दलितों को जोड़ेंगे और नीतीश कुमार मुसलमान वोटों में सेंध लगाना चाहेंगे.

महिला आरक्षण विधेयक सभी दलों में सांसदों के मतभेद को तो ज़ाहिर कर ही गया, पर जदयू की दूर की साफ़ साफ़ झलक भी दिखा गया है. पर यह टूट नीतीश के लिए संभावनाओं के नए कितने द्वार खोलती है, यह देखना दिलचस्प होगा.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

# पीसीबी का छलावा

एजाज बट्ट

मो. युसुफ

युनुस खान

शोएब मलिक

शाहिद अफ़्रीदी

कामरान अकमल

उमर अकमल

राणा नावेद उल हसन

पाकिस्तान क्रकेट बोर्ड (पीसीबी) आख़िर क्या साबित करना चाहता है. एक छह सदस्यीय जांच आयोग के सरफिरे सिफ़ारिशों को, उनके नतीजों के बारे में सोचे बगैर, बेतुके अंदाज़ में लागू करने के पीछे पीसीबी की आख़िर मंशा क्या थी. हो सकता है कि कर्तव्यनिष्ठा और बौद्धिक शुचिता की कसौटी पर पीसीबी ख़ुद को इस अंदाज़ में पेश करने की कोशिश कर रही हो, जो वह वास्तव में है नहीं, या फिर ऐसी सोच का बहाना बना रही हो, जो उसके ज़ेहन में कभी आए ही नहीं. मोहम्मद युसुफ और युनुस ख़ान पर आजीवन प्रतिबंध, हालांकि, अब पाक सरकार इससे इंकार कर रही है, का फ़ैसला इन दोनों की वरिष्ठता के अनुरूप जारी किया गया. पीसीबी का यह बेसिरपैर का अंदाज़ लोगों के लिए इतना ही बेतुका है जितना कि ख़ुद यह फ़ैसला. क्या टीम के ख़राब प्रदर्शन और अनुशासन भंग करने का सारा पाप इन्हीं खिलाड़ियों ने किया था या फिर देश के खेल प्रशासकों की भी इस मामले में कोई ज़िम्मेदारी बनती है.

युसुफ और युनुस को टीम का अनुशासन तोड़ने का दोषी पाया गया है, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैनेजर रहे यावर सईद और कोच के पद से बर्ख़ास्त किए गए इंतिखाब आलम को सम्मानित किया गया है. पीसीबी के दोहरे मापदंडों का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि सईद को फिर से अपने पुराने पद पर नियुक्त कर दिया गया जबकि इंतिखाब आलम नेशनल क्रिकेट एकेडमी और गेम डेवलपमेंट के निदेशक बनाए गए हैं.

इन तमाम फ़ैसलों से पीसीबी की एक हास्यपूर्ण छवि सामने आ रही है. ऐसा लगता है कि मूर्खता भरे ऐसे फ़ैसले लेना पीसीबी की फितरत में शामिल है. युनुस, युसुफ, शोएब मलिक, राणा नावेद उल हसन, शाहिद अफ़्रीदी, कामरान अकमल और उमर अकमल पर प्रतिबंध और आर्थिक जुर्माना आरोपित करने का फ़ैसला ही विरोधाभासी है, क्योंकि इसके पीछे किसी स्पष्ट सोच और नज़रिये की कमी साफ़ दिखाई देती है.

फ़ैसले के होने वाले असर की तर्कपूर्ण विवेचना किए बग़ैर इसे न्याय की कसौटी पर कसने की पीसीबी की कोशिश वास्तव में क़ाबिले तारीफ है. यह हमें होमर सिंपसन और पीटर ग्रिफिथ के डंब एंड डंबर की याद दिलाता है. लेकिन पीसीबी में ऐसे ही लोगों की भरमार है. कहा जाता है कि ज़्यादा योग्यता अक्सर बेवकूफाना शक्ल अख्तियार कर लेता है. यह दावा कि पीसीबी लगातार ऐसे नए और अनोखे हालातों से दो–चार हो रहा है कि हर मामले को पूरी बुद्धिमत्तापूर्वक हल करने की उम्मीद करना बेमानी है, सिरे से ख़ारिज किया जा सकता है. सच तो यह है कि बोर्ड के शीर्ष पदों पर क़ाबिज़ अधिकारी बार–बार उन्हीं ग़लतियों को दोहरा रहे हैं. सच यह भी है कि यदि बोर्ड ने इन मामलों में तटस्थ और निरपेक्ष रह कर विचार किया होता तो कई बेवकूफाना फ़ैसलों से बचा जा सकता था.

यदि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्रशासकों ने ऐसा फ़ैसला लिया होता तो बात समझ में आती है. कंगारुओं के देश में क्रिकेट की अपनी परंपरा है और उनका घरेलू ढांचा इतना मज़बूत है कि चयन समिति के पास सभी खिलाड़ियों के लिए उतना ही मज़बूत और विश्वसनीय विकल्प ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती. लेकिन पाकिस्तान में हालात ठीक इसके विपरीत हैं. घरेलू क्रिकेट का स्तर लगातार कमजोर होता जा रहा है और स्तरीय खिलाड़ियों की पहचान करना बेहद मुश्किल है. फिर पीसीबी के रवैये के चलते खिलाड़ी गुटबंदी और अनुशासनहीनता के शिकार हो रहे हैं.

पीसीबी ने जांच समिति में जिन लोगों को शामिल किया, उनके चुनाव का आधार भी आम लोगों की समझ से परे है. समिति में शामिल यावर सईद ख़ुद ही संदेह के घेरे में हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैनेजर रहते हुए कप्तान युनुस खान के साथ उनके मतभेद जगज़ाहिर हैं. फिर उनसे उसी खिलाड़ी के ख़िलाफ़ विवेकपूर्ण फ़ैसले की उम्मीद कैसे की जा सकती है. समिति में पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम बारी और डायरेक्टर, क्रिकेट ऑपरेशंस जाकिर ख़ान भी शामिल थे, जो शायद इस बात की गवाही देता है कि बोर्ड पहले ही अपना मन बना चुकी थी. यह जांच समिति तो महज एक बहाना है. सोचने वाली बात यह भी है कि समिति का गठन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे में घटिया प्रदर्शन की छानबीन करने के लिए हुआ था, फिर वह खिलाड़ियों पर प्रतिबंध और जुर्माने की सिफ़ारिश कैसे कर सकती है.

**पीसीबी ने जांच समिति में जिन लोगों को शामिल किया, उनके चुनाव का आधार भी आम लोगों की समझ से परे है. समिति में शामिल यावर सईद खुद ही संदेह के घेरे में हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैनेजर रहते हुए कप्तान युनुस ख़ान के साथ उनके मतभेद जगज़ाहिर हैं.**

क्या जांच समिति के पास ऐसी सिफ़ारिशें करने का अधिकार था या उसे केवल वजह तलाशने का ज़िम्मा दिया गया था. फ़ैसले के बाद मीडिया में बचे बवाल के मद्देनजर पीसीबी और उसकी जांच समिति को क्या कहा जाए– अनैतिक, सिरफिरा, शर्मिंदगी की हद तक बेवकूफाना हरकत या कुछ और. इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ऐसी कार्रवाईयों से खिलाड़ियों की शक्ति या उनके व्यवहार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला. सच तो यह है कि खिलाड़ियों की शक्ति तो एक छलावा भर है, असल मसला तो पीसीबी की शक्तिहीनता है. दोषी खिलाड़ियों के विकल्प का अभाव और युवा खिलाड़ियों के भविष्य के लिए सही रास्ता तलाश करने में नाकामी, पीसीबी को विश्वसनीय संस्था के रूप में स्थापित करने में उनकी विफलता, प्रतिबंध और फिर उससे इंकार– ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो पीसीबी का मखौल उड़ाने के लिए पर्याप्त हैं. पाकिस्तान में क्रिकेट का प्रशासन इतना पतित हो चुका है कि इससे कुछ भी उम्मीद करना बेमानी होगा, लेकिन इसे पुनर्जीवित किए जाने की ज़रूरत है. लेकिन इसमें दोबारा प्राण तब तक नहीं भरा जा सकता, जब तक एजाज बट्ट अपने पद पर मौजूद हैं. कुछ नहीं, तो उन्हें कम से कम अपनी बढती उम्र का ख्याल तो करना चाहिए. बट्ट पाकिस्तान नेवी के साथ काम कर चुके हैं. एडमिरल फिलिप के बारे में कहा जाता है कि जहाज को बचाने के प्रयास में वो ख़ुद भी उसके साथ डूब गए, लेकिन यहां तो एजाज बट्ट खुद डूब रहे हैं और उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट भी डूबने को मजबूर है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कमोबेश यहां तक माना गया है कि शराब नहीं पीने वालों की तुलना में कम पीने वालों में मोटापा बढ़ने की आशंका कम रहती है.



सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

# ऐसे बनाएं आरटीआई आवेदन...

पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि आरटीआई के इस्तेमाल में आने वाली दिक़्क़तों से कैसे निपटा जा सकता है. इस अंक से हम लगातार आरटीआई आवेदन का एक प्रारूप प्रकाशित करेंगे, ताकि आप अपना आरटीआई आवेदन ष्ठ द तैयार कर सकें. इसी कड़ी में इस बार का आवेदन नरेगा से संबंधित है. यह आवेदन नरेगा में हो रही (अगर ऐसा है तो) धांधली को सामने लाने या जॉब कार्ड बनवाने में मददगार साबित हो सकता है. हम अपने सुधी पाठकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे गांव–देहात में रहने वाले लोगों को भी इस कॉलम के बारे में बताएंगे और इसमें दिए गए आरटीआई आवेदन के प्रारूप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे. क्योंकि सरकारी योजनाओं में पनप रहे भ्रष्टाचार से लड़ने की चौथी दुनिया की इस मुहिम में आपका साथ ही असली मायने रखता है.

## क्या फाइल नोटिंग का सार्वजनिक होना अधिकारियों को ईमानदार सलाह देने से रोकेगा?

नहीं, यह आशंका ग़लत है. इसके उलट, हर अधिकारी को अब यह पता होगा कि जो कुछ भी वह लिखता है वह जन– समीक्षा का विषय हो सकता है. यह उस पर उत्तम जनहित में लिखने का दबाव बनाएगा. कुछ ईमानदार नौकरशाहों ने अलग से स्वीकार किया है कि आरटीआई उनके राजनीतिक व अन्य प्रभावों को दरकिनार करने में बहुत प्रभावी रहा है. अब अधिकारी सीधे तौर स्वीकार करते हैं कि यदि उन्होंने कुछ ग़लत किया तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा. इसलिए, अधिकारियों ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया है कि वरिष्ठ अधिकारी भी उन्हें लिखित में निर्देश दें.

## क्या बहुत लंबी–चौड़ी सूचना मांगने वाले आवेदन को ख़ारिज किया जाना चाहिए?

यदि कोई आवेदक ऐसी जानकारी चाहता है जो एक लाख पृष्ठों की हो तो वह ऐसा तभी करेगा जब सचमुच उसे इसकी ज़रूरत होगी क्योंकि उसके लिए दो लाख रुपयों का भुगतान करना होगा. यह अपने आप में ही हतोत्साहित करने वाला उपाय है. यदि अर्ज़ी इस आधार पर रद्द कर दी गयी, तो प्रार्थी इसे तोड़कर प्रत्येक अर्ज़ी में

100 पृष्ठ मांगते हुए 1000 अर्जियां बना लेगा, जिससे किसी का भी लाभ नहीं होगा. इसलिए, इस कारण अर्जियां रद्द नहीं होनी चाहिए कि लोग ऐसे मुद्दों से जुड़ी सूचना मांग रहे हैं जो सीधे सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं हैं. उन्हें सरकार के अन्य मामलों के बारे में प्रश्न पूछने की छूट नहीं दी जानी चाहिए, पूर्णत: ग़लत है. आरटीआई अधिनियम का अनुच्छेद 6(2) स्पष्टत: कहता है कि प्रार्थी से यह नहीं पूछा जा सकता कि क्यों वह कोई जानकारी मांग रहा है. किसी भी मामले में, आरटीआई इस तथ्य से उद्भुत होता है कि लोग टैक्स/ कर देते हैं, यह उनका पैसा है और इसीलिए उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कैसे ष्ठ र्च हो रहा है और कैसे उनकी सरकार चल रही है. इसलिए लोगों को सरकार के प्रत्येक कार्य की प्रत्येक बात जानने का अधिकार है. भले ही वे उस मामले से सीधे तौर पर जुड़े हों या न हों. इसलिए, दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति ऐसी कोई भी सूचना मांग सकता है जो तमिलनाडु से संबंधित हो.

## सरकारी रेकॉर्ड्स सही रूप में व्यवस्थित नहीं हैं.

आरटीआई की वजह से सरकारी व्यवस्था पर अब रेकॉर्ड्स सही आकार और स्वरूप में रखने का दवाब बनेगा. अन्यथा, अधिकारी को आरटीआई क़ानून के तहत दंड भुगतना होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

**यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें उसका पूरा विवरण नीचे लिखे पते पर भेजें, हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई–मेल भी कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है :**

**चौथी दुनिया**
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन –201301
ई–मेल: rti@chauthiduniya.com

## सवाल–जवाब

8–14 मार्च के अंक में मैने पढा कि आरटीआई से संबंधित जानकारियों के लिए हम आपसे संपर्क कर सकते है. मैं मोकामा का रहने वाला हूं और यह जानना चाहता हूं कि मैं अपनी शिकायत कहां भेज सकता हूं और क्या कोई बच्चा भी अपनी शिकायत दाखिल कर सकता है?

**अविनाश किरण**, *मोकामा, पटना.*

आप अपना आरटीआई आवेदन (जिसमें आपकी समस्या से जुड़े सवाल होंगे) संबंधित सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी ( पीआईओ) के पास स्वयं जा कर या डाक के द्वारा जमा करा सकते है. आरटीआई क़ानून के मुताबिक़ प्रत्येक सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना आवश्यक है. यह ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पीआईओ का नाम मालूम हो. यदि आप प्रखंड स्तर के किसी समस्या के बारे में सवाल पूछना चाहते है तो आप क्षेत्र के बीडीओ से संपर्क कर सकते है. केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के पते जानने के लिए आप इंटरनेट की भी मदद ले सकते है. और, हां एक बच्चा भी आरटीआई क़ानून के तहत आरटीआई आवेदन दाख़िल कर सकता है.

*चौथी दुनिया*

## नरेगा से संबंधित आरटीआई आवेदन

दिनांक :

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

*विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.*

महोदय,

.....ब्लॉक के ग्राम.....के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त गांव से एन.आर.ई.जी.ए.(नरेगा) के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए है? इसकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:
**क.** आवेदक का नाम व पता
**ख.** आवेदन संख्या
**ग.** आवेदन की तारीख़
**घ.** आवेदन पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण (जॉब कार्ड बना/जॉब कार्ड नहीं बना/विचाराधीन)
**ड.** यदि जॉब कार्ड नहीं बना तो उसका कारण बताएं
**च.** यदि बना तो किस तारीख़ को

2. जिन लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है उनमें से कितने लोगों ने काम देने का आवेदन किया है? उसकी सूची भी निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:
**क.** आवेदक का नाम व पता
**ख.** आवेदन करने की तारीख़
**ग.** दिए गए कार्य का नाम
**घ.** कार्य दिए जाने की तारीख़
**ड.** कार्य के लिए भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख़
**च.** रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति जहां इनके भुगतान से संबंधित विवरण दर्ज हैं.
**छ.** यदि काम नहीं दिया गया है तो क्यों?
**ज.** क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?

3. उपरोक्त गांव से एन.आर.ई.जी.ए. के तहत रोजगार के लिए आवेदन करने वाले जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया या दिया जा रहा है उनकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं :
**क.** आवेदक का नाम व पता
**ख.** आवेदन करने की तारीख़
**ग.** बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की तारीख़
**घ.** बेरोजगारी भत्ता के लिए भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख़
**च.** रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति जहां इनके भुगतान से संबंधित विवरण दर्ज हैं।

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रू. अलग से जमा कर रहा/रही हूं।

भवदीय

नाम :
पता :
हस्ताक्षर

# ज़रा हट के

## पांच हज़ार नई प्रजातियों की खोज

समुद्री जीवों की गणना के एक पूर्वावलोकन में पांच हज़ार से अधिक नई प्रजातियों का पता चला है. ग़ौरतलब है कि इस परियोजना के अंतर्गत कई ऐसे विचित्र क़िस्म के जीव मिले हैं, जिनसे अनेक बीमारियों का इलाज हो सकता है. पूर्वावलोकन की यह रिपोर्ट वैज्ञानिकों के एक दल ने सैंटियागो में विज्ञान की प्रगति के लिए बनी अमरीकन एसोसियशन के वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की है.

गणना का काम पिछले दस वर्षों से चल रहा है और अंतिम रिपोर्ट इसी साल अक्टूबर में प्रस्तुत की जाएगी. इस परियोजना पर 80 देशों के दो हज़ार से अधिक वैज्ञानिकों ने काम किया है. शोधकर्ताओं को आशा है कि यह गणना समुद्री जीवों से जुड़ी नीतियों के लिए एक नया वैज्ञानिक आधार तैयार करने में सहायक होगा. इसमें केकड़े के भी एक विचित्र प्रजाति को दिखाया गया. फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक डॉक्टर शिर्ले पोंपनी ने स्पंज की नई प्रजाति पर भी प्रकाश डाला. स्पंज की यह नई प्रजाति अगस्त 1999 में फ़्लोरिडा में पाई गई थी. इस प्रजाति पर किए गए अध्ययन से पता चला कि वो एक ऐसे रासायन का स्राव करता है, जिसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता है. अब इस प्रजाति पर और शोध हो रहा है, ताकि इसके चिकित्सकीय इस्तेमाल को आसान बनाया जा सके. इस परियोजना का उद्देश्य समुद्र में संरक्षित क्षेत्रों से जुड़ी वैश्विक नेटवर्क की स्थापना करना है, ताकि मछलियों केशिकार करने और अन्य मानवीय गतिविधियों को रोका जा सके. ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक का कहना है कि समुद्र की निचली सतहों में मछली मारने से कोरल रीफ़ पर ख़तरा मंडरा रहा है.

## शराब पीने से महिलाएं मोटी नहीं होतीं !

वैसे कहा जाता है कि शराब पीने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन एक नए शोध ने यह खुलासा किया है कि दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद अगर महिलाएं एक ग्लास शराब पीती हैं तो वे मोटी नहीं होती हैं, बल्कि वे अपने आप को तरोताजा महसूस करती हैं. हालांकि शराब पीने से वजन बढ़ता है जो डाइट सलाह के ठीक विपरीत है. मगर, शोधकर्ताओं का तो यही कहना है.

वास्तव में शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह भी पाया है कि, जो महिलाएं शराब पीती हैं और जो सिर्फ़ मिनरल वाटर पीती हैं, दोनों के वजन में अंतर होता है. इस शोध में दावा किया गया है कि जो महिलाएं शराब पीती हैं उनका वजन कम होता है. कमोबेश यहां तक माना गया है कि शराब नहीं पीने वालों की तुलना में कम पीने वालों में मोटापा बढ़ने की आशंका कम रहती है.

शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि शराब से मिलने वाली कैलरी का दूसरे खाद्य पदार्थों के बजाए वजन पर कम असर पड़ता है और जिस तरह से शराब शरीर से क्रिया करता है, वह काफी जटिल है.

एक अन्य सिद्धांत के अनुसार जो महिलाएं रोजाना शराब पीती हैं, उनमें लिवर शराब के असर को कम करने के लिए एक अलग मेटाबॉलिक रास्ता उत्पन्न करता है, जो अधिक ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है न कि मोटापा में. इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 39 साल से अधिक उम्र वाली क़रीब 19000 महिलाओं का परीक्षण किया, पर इसमें शामिल क़रीब 38 फ़ीसदी महिलाएं शराब नहीं पीती थीं.

# राशिफल

**22 मार्च–28 मार्च 2010**

**मेष** (21 मार्च से 20 अप्रैल)
राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सकती है. व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. आकस्मिक सुखद समाचार मिलेगा. संबंधित अधिकारी के कृपा पात्र हो सकते हैं.

**वृष** (21 अप्रैल से 20 मई)
समाज के कुछ कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे. कुछ व्यर्थ की समस्याएं बढ़ेंगी. कुछ पारिवारिक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है. रचनात्मक कार्यो में आशातीत सफलता मिलेगी. व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा.

**मिथुन** (21 मई से 20 जून)
पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. यात्रा की स्थिति सुखद व उत्साहवर्द्धक होगी. संबंधों में निकटता आएगी. भौतिक दिशा में चल रहे प्रयास आशातीत सफलता देंगे.

**कर्क** (21 जून से 20 जुलाई)
पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. संबंधों में निकटता आएगी. व्यावसायिक प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. कहीं न कहीं मन अशांत रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं.

**सिंह** (21 जुलाई से 20 अगस्त)
अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. आय के नए रास्ते बनेंगे. यात्रा की स्थिति सुखद होगी. दांपत्य जीवन सुखमय होगा. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. धन, सम्मान में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

**कन्या** (21 अगस्त से 20 सितंबर)
उदर विकार या नेत्र विकार कष्टकारी हो सकता है. आर्थिक मामलों में जोष्ठि म न उठाएं. भौतिक दिशा में आशातीत सफलता मिलेगी, लेकिन दांपत्य जीवन में झगड़ा या किसी तरह के विवाद की स्थिति आ सकती है.

**तुला** (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
व्यर्थ के विवाद आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना ही हितकर होगा. स्वधर्मी आपके लिए नई समस्या उत्पन्न कर सकता है. मित्रों से फिलहाल दूरी बनाएं रखें. समाज के कार्यों के लिए आगे रहेंगे.

**वृश्चिक** (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
भागदौड़ और आपाधापी की स्थिति कष्टकारी हो सकती है. रचनात्मक कार्यो में सफलता मिलेगी. व्यर्थ की समस्या व तनाव मिल सकता है. पिता या घर के मुखिया से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा.

**धनु** (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा. आर्थिक मामलों में जोष्ठि म न उठाएं. काफी समय से अधूरा पड़ा कार्य पूरा हो जाएगा. भागदौड़ की स्थिति स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है.

**मकर** (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
जीवनसाथी से तनाव पैदा हो सकता है, ग़लतफहमी को दूर करने का प्रयास अवश्य करें. व्यर्थ की उलझन व तनाव मिल सकता है. यात्रा देशाटन में झगड़ा विवाद न करे. वाणी पर संयम रखना ही हितकर होगा.

**कुंभ** (21 जनवरी से 20 फरवरी)
समाज के कार्यों में व्यस्त रहने के साथ मनोरंजन के सुखद अवसर प्राप्त होंगे. कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान के प्रति सचेत रहें. ज़मीन संबंधी मामलों में समस्याएं पैदा हो सकती हैं. धन, सम्मान का लाभ मिलेगा.

**मीन** (21 फरवरी से 20 मार्च)
जारी प्रयास फलीभूत होंगे. आर्थिक मामलों में प्रगति होगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. धन, सम्मान में वृद्धि का योग है. संतान के कारण चिंतित रहेंगे. पिता या घर के मुखिया के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

हाल के दिनों में हज़ारों की संख्या में छात्र और धर्मगुरू इस्लाम को शांति का धर्म बताने के लिए एक साथ हुए हैं.



# इस्लाम में आत्मघाती हमला हराम है

सुसाइड अटैक यानी आत्मघाती हमलों का इस्तेमाल इतिहास के अलग-अलग पड़ावों पर अलग-अलग सभ्यताओं ने किया है और हर बार इसका उद्देश्य धार्मिक ही नहीं रहा है. जर्मनी, जापान, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों ने इसे युद्ध के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी आम लोगों की सोच में इसे अक्सर धार्मिक, और ख़ासकर इस्लामी आतंकवादी भावनाओं से जोड़ कर देखा जाता है. आत्मघाती हमलों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और इस लिहाज़ से पिछले कुछ महीने पाकिस्तान के इतिहास में शायद सबसे रक्तरंजित रहे हैं. हालात बेकाबू होते देख उलेमाओं का एक वर्ग इस्लामी नीतिशास्त्र के अनुरूप सुसाइड अटैक का औचित्य तलाशने की कोशिश में हैं. धर्म गुरुओं ने एकमत से यह बात स्वीकार की है कि इस्लाम किसी भी हालत में लड़ाई के इस तरीक़े की इजाज़त नहीं देता.

कई लोग इसका औचित्य ठहराने के लिए अब्राहमिक मान्यताओं का उदाहरण देते हैं. इसके मुताबिक़ पैगंबर सैमसन ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि उसे आख़िरी बार इतनी शाक्ति दे कि वह उस खंभे को उखाड़ सके, जिससे उसे बांधा गया था. उसकी असली मंशा यही थी कि उस विशाल खंभे को साथ लेकर वह ज़्यादा से ज़्यादा फिलीस्तीनियों को मार सके और ख़ुद भी उनके साथ ही मर जाए. मिल्टन और हेंडेल जैसे विद्वानों ने इस साहस और जज़्बे की प्रशंसा में ख़ूब कसीदे कढे हैं, लेकिन उन्हें शायद नहीं पता कि कुरान में इस बात की कोई चर्चा तक नहीं की गई है.

इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक़ कुरान आत्महत्या की भी इजाज़त नहीं देता. उसकी दो आयतों, 195 और 29-30 को समझने से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है. आयत 195 की व्याख्या करते हुए युसुफ अली लिखते हैं, आप अपना इस्तेमाल अल्लाह के कामों के लिए करेंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल अपने विनाश के लिए नहीं करेंगे, नेक काम करेंगे और नेक काम करने वाले हर अल्लाह के बंदे से प्यार करेंगे. आयत 29-30 के बारे में हालांकि स्थिति थोड़ी संशयात्मक है.

ला तक्तालु अनफुसाकम - इसका सही मतलब ख़ुद को नहीं मारना है या एक दूसरे को नहीं मारना है- इस बारे में राय एक नहीं है. लेकिन अधिकतर शिया और सुन्नी विद्वानों का यही मानना है कि यह आत्महत्या की इजाज़त नहीं देता. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक़ आत्महत्या हरम है, क्योंकि पहले तो आत्महत्या करना ही पाप है और दूसरे यदि आत्महत्या का इस्तेमाल दूसरों की हत्या के लिए किया जाए तो यह और भी बड़ा पाप है.

कई प्रमुख न्यायविदों और धर्म गुरुओं ने आत्मघाती हमलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है. अलग-अलग देशों से संबंध रखने वाले शेख मोहम्मद अफीफी अल-अकीती, शेख मोहम्मद सैयद अल-तंतावी, अयातुल्लाह युसुफ सनेइ जैसे विद्वानों ने बार-बार इन हमलों को अधार्मिक बताया है. रोचक बात तो यह है कि कुछ दिनों पहले देवबंद संप्रदाय के कई प्रमुख विद्वान भी आतंकवाद के ख़िलाफ़ सामने आए. देवबंद बेहद प्रभावशाली है और लोकप्रियता के मामले में शायद अल-अलहर से थोड़ा ही कम है. उनकी घोषणाओं का ज़्यादा असर होता है क्योंकि इराकी मुजाहिदीन, तालिबान, हरकते इस्लाम और जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई आतंकी संगठन देवबंदी विचारधारा से प्रेरणा लेते हैं.

हाल के दिनों में हज़ारों की संख्या में छात्र और धर्मगुरू इस्लाम को शांति का धर्म बताने के लिए एक साथ हुए हैं. उनका स्पष्ट कहना है कि कुरान या पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों के आधार पर आतंकवाद को जायज़ ठहराने वाले लोग झूठे हैं. इस फतवे को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें धर्मग्रंथों की भाषा इस्तेमाल की गई है और कुरान की आयतों की मदद से तर्क को स्वीकार्य बनाने का प्रयास किया गया है. ऐसा ही एक फतवा पहले भी जारी किया गया था, इस पर हबीब उर-रहमान सहित उनके तीन साथियों के भी दस्तखत थे. लेकिन कमी ढूंढने वाले लोग, कैसे भी , अपने तर्क निकाल ही लेते हैं.

यदि हम दुनिया भर में जारी किए गए इन फतवों पर एक नज़र दौड़ाएं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सुसाइड अटैक के मामले में ज़्यादा प्रगतिशील विचारधारा अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आत्महत्या और निर्दोष लोगों की हत्या को नाजायज़ करार देने वाले तर्क सदियों से इस्लामी विधिशास्त्र का एक हिस्सा बने रहे हैं. उलेमाओं को करना बस इतना है कि इन तर्कों को ऐसी शक्ल दें जिससे सुसाइड अटैक की धार्मिक वैधता पर कोई विवाद ही न रहे. हालांकि, ऐसा करना आसान नहीं है, सदियों पुराना हमारा अनुभव यही बताता है. फिर कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है, मसलन जिहाद की घोषणा कब और कैसे की जाए एवं ऐसा करने का अधिकार किसके पास है.

आत्मघाती हमलों की अधार्मिकता को सर्वमान्य बनाने के लिए कई और मान्यताओं का सहारा भी लिया जा सकता है. लेकिन निराशाजनक बात यह है कि शेख युसुफ करादवी जैसे लोग आत्मघाती हमलों को कई बार वैध बताते हैं. उनका तर्क है कि इज़रायल को रोकने के लिए फिलीस्तीनियों द्वारा किए जाने वाले आत्मघाती हमले जायज़ हैं और ऐसे करने वाले लोग शहीद कहलाने चाहिए.

शायद वह समय आ गया है जब अलग-अलग देशों के उलेमा, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी ज़रूर शामिल हों, एक साथ सामने आएं और आत्मघाती हमलों को सार्वजनिक रूप से इस्लाम के ख़िलाफ़ घोषित करें. यह याद रखना भी ज़रूरी है कि ऐसा करने वाले लोग अक्सर ये काम निराशा में करते हैं, हमें उनकी दुश्वारियों को भी समझने की पहल करनी होगी. आत्मघाती हमलों को हरम घोषित कर देने भर का मतलब यह नहीं है कि इसको पैदा करने वाले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अन्य कारण भी एकबारगी ही समाप्त हो जाएंगे. सुसाइड हमले निजी स्वार्थ, जिद, निराशा और विफलता की पराकाष्ठा हैं. हर इंसान की आत्मा से जिद और अक्खड़पन को दूर करने के लिए केवल इस्लाम ही नहीं, हर धर्म को आगे आना होगा. अपने स्वार्थ की साधना में हमलावर वही करता है, जो कुरान में पहले ही कहा गया है- एक निर्दोष की हत्या पूरी इंसानियत के कत्लेआम के बराबर है.

**कई प्रमुख न्यायविदों और धर्म गुरुओं ने आत्मघाती हमलों के खिलाफ आवाज उठाई है. अलग-अलग देशों से संबंध रखने वाले शेख मोहम्मद अफीफी अल-अकीती, शेख मोहम्मद सैयद अल-तंतावी, अयातुल्लाह युसुफ सनेइ जैसे विद्धानों ने बार-बार इन हमलों को अधार्मिक बताया है.**

**अली खान महमूदाबादी**

*(लेखक इस्लाम धर्म के जाने माने विद्वान हैं)*

feedback@chauthiduniya.com

**प्रपत्र 4**
**(नियम 8 देखिए)**
**चौथी दुनिया**

| | |
|---|---|
| 1. **प्रकाशन का स्थान** | नई दिल्ली |
| 2. **प्रकाशन अवधि** | साप्ताहिक प्रति रविवार |
| 3. **मुद्रक का नाम** | रामपाल सिंह भदौरिया |
| **राष्ट्रीयता** | |
| (क) क्या भारत का नागरिक है | हां |
| (ख) यदि विदेशी है तो मूलदेश | XXX |
| **पता** | 29 डीडीए फ्लैट चित्रा विहार विकास मार्ग दिल्ली-110092 |
| 4. **प्रकाशक का नाम** | रामपाल सिंह भदौरिया |
| (क) क्या भारत का नागरिक है | हां |
| (ख) यदि विदेशी है तो मूलदेश | XXX |
| **पता** | 29 डीडीए फ्लैट चित्रा विहार विकास मार्ग दिल्ली 110092 |
| 5. **संपादक का नाम** | **संतोष भारतीय** |
| **राष्ट्रीयता** | |
| (क) क्या भारत का नागरिक है | हां |
| (ख ) यदि विदेशी है तो मूल देश | XXX |
| **पता** | अंकुश पब्लिकेशंस प्रा.लि. के-2 गेनन दूसरी मंजिल चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस नई दिल्ली-110001 |
| 6. **उन व्यक्तियों के नाम व पते** जो समाचार पत्र के स्वामी है एवं कुल पूंजी के एक प्रतिशत से. ज्यादा के साझेदार या शेयरधारक है. | अकुंश पब्लिकेशंस प्रा.लि. 98 मित्तल चैम्बर्स नरीमन प्वाइंट मुंबई-400021<br>1. शाकंभरी ट्रैडर्स लिमिटेड 98 मित्तल चैम्बर्स नरीमन प्वाइंट मुंबई<br>2. गेनन डंकरली फाइनेंस लिमीटेड न्यू एक्सेलर बिल्डिंग तीसरी मंजिल ए.के. नायक मार्ग फोर्ट मुंबई-400001<br>3. एम आर होल्डिंग लिमिटेड गेनन डंकरली फाइनेंस लिमीटेड न्यू एक्सेलर बिल्डिंग तीसरी मंजिल ए.के. नायक मार्ग फोर्ट मुंबई -400001 |

मैं रामपाल सिंह भदौरिया एतदद्वारा घोषित करता हूं. कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य है.

हस्ताक्षर
**रामपाल सिंह भदौरिया**
**प्रकाशक**

**दिनांक 28 मार्च 2010**

एक बार शिरडी के दुकानदारों ने संगठित होकर बाबा को तेल न देने का फ़ैसला कर लिया.



# साईं बाबा जीवित परमेश्वर हैं : सूर्य राजकमल

विकास कपूर

संस्कारों के फूल योग्य माली की बग़िया में ही खिलते हैं. प्रसिद्ध संगीत निर्देशक स्वर्गीय राजकमल के सुपुत्र सूर्य राजकमल उस समय लगभग 17–18 साल के थे, जब स्वर्गीय बी आर चोपड़ा धारावाहिक महाभारत बनाने की योजना बना रहे थे. सूर्य के भीतर की प्रतिभा को पापा जी (बी आर चोपड़ा) ने पहचाना और इस भव्य धारावाहिक के पार्श्व संगीत का उत्तरदायित्व भी सौंप दिया. उस समय कई लोगों ने पापा जी के इस फ़ैसले का विरोध भी किया, परंतु पापा जी रत्नों के पारखी थे. उन्हें अपने फ़ैसले पर पूरा विश्वास था और हुआ भी वैसा ही, जैसा उन्होंने सोचा और चाहा था. दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक महाभारत ने सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया, परंतु इसकी सफलता में सूर्य राजकमल के पार्श्व संगीत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. सूर्य को संगीत की प्राथमिक शिक्षा अपने पिता राजकमल जी से मिली थी. महाभारत की सफलता ने सूर्य राजकमल को रातोंरात व्यस्ततम संगीतकार बना दिया. विष्णु पुराण, जय मां वैष्णो देवी, मैं दिल्ली हूं, महाराणा प्रताप, क़ानून, कुसुम, विरासत, चुन्नी, घर एक मंदिर, आपबीती, पंचम, महिमा शनिदेव की, विक्रम और बेताल आदि धारावाहिकों के साथ सूर्य राजकमल के कई सफल एलबम भी सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. इनमें जगजीत सिंह के साथ श्रीराम, शिरडी साई बाबा फाउंडेशन के साथ साई की महिमा आदि प्रमुख हैं. पिछले दिनों सूर्य राजकमल से उनकी साई भक्ति पर लंबी चर्चा हुई. पेश हैं मुख्य अंश:

*आपने बहुत सारे धार्मिक धारावाहिकों में संगीत दिया, हिंदू धर्म को आप किस दृष्टि से देखते हैं?*

मेरी दृष्टि में हिंदू धर्म विश्व के अन्य सभी धर्मों से अधिक स्वतंत्र और स्वछंद है. हम अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार आराधना कर सकते हैं.

*हिंदू धर्म के दर्शन में साई बाबा का दर्शन अथवा उनकी शिक्षा किस प्रकार समाहित होती है?*

मेरा अपना मानना है कि साई बाबा को किसी भी धर्म और मज़हब के दायरे में बांधना अनुचित है. बाबा तो मानवता और इंसानियत की बात करते थे और हमेशा हर धर्म का एक समान आदर करते थे. जहां तक साई बाबा की शिक्षा और साई दर्शन की बात है तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि हमारा हिंदू धर्म हर एक की शिक्षा और दर्शन को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता है.

*आपके जीवन में कभी साई कृपा की कोई घटना घटी?*

आप जानते हैं कि मैंने बहुत युवावस्था में संगीत निर्देशन का कार्य प्रारंभ कर दिया था. हिंदुओं के लगभग सभी देवी–देवताओं के विषय को मैंने संगीत से संवारा, पर मुझे कभी भी साई बाबा पर काम करने का अवसर नहीं मिला. मेरे मन में इस बात का मलाल हमेशा बना रहता था कि साई सेवा का अवसर तुम्हें कभी क्यों नहीं मिला? यह 2007 की बात है. उस साल बाबा की महासमाधि दिवस (दशहरे) के दिन मैंने साई बाबा से यही प्रश्न पूछा? आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब मैं मंदिर से निकलते ही मेरी पत्नी रिंकू ने मुझे फोन करके बताया कि साई बाबा फाउंडेशन से फोन आया था, आपको साई बाबा पर एलबम तैयार करना है. मैं हतप्रभ था, बाबा अपने भक्तों की पुकार इतनी जल्दी सुनते हैं कि भक्त भी चकित होकर रह जाता है.

*अब तक की अपनी यात्रा अथवा अपने काम पर आपको संतोष है?*

साई कृपा से सब अच्छा है. मन में कोई असंतोष तो नहीं है, पर सच कहूं तो संतोष भी नहीं है, क्योंकि अपने काम पर संतोष हो जाना चुनौती से मुंह मोड़ने जैसा है. मैं तो एक योद्धा की भांति अंतिम सांस तक संगीत के साथ जीना चाहता हूं और साई कृपा पर मेरा विश्वास है. अभी बहुत कुछ करना है. मंज़िल (शिरडी) अभी बहुत दूर है. ॐ साई राम.

**अगले अंक में**
**ऋषभ शुक्ला के साई अनुभव**

# सार्वभौम साईं : पानी से दीये जल उठे

साई बाबा को प्रकाश से बहुत अनुराग था. वह प्रायः रात के समय द्वारका मस्जिद में कई दीपक अपने हाथों से जलाया करते थे. दीपक जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती थी, इसलिए बाबा हमेशा शिरडी के दुकानदारों से तेल की भिक्षा मांग लिया करते थे. एक बार शिरडी के दुकानदारों ने संगठित होकर बाबा को तेल न देने का फ़ैसला कर लिया. बाबा निराश से मस्जिद लौट आए. उनके पीछे–पीछे शिरडी के दुकानदार भी थे, जो देखना चाहते थे कि अब बाबा क्या करेंगे? साई बाबा ने तेल की टमरेल (पात्र) उठाकर देखा तो तली में ज़रा सा तेल था. बाबा ने उसमें पानी भर दिया और उसे पी गए. फिर बाबा ने उसी पात्र में उसका वमन

कर दिया. दीपकों में सूखी बत्ती डालकर बाबा ने वमन किया हुआ पानी दीपों में भर दिया. शिरडी के दुकानदार बाबा के कार्य पर हंस रहे थे. उधर बाबा ने दीपक जलाने शुरू कर दिए. यह शिरडी के दुकानदारों को सबक सिखाने की लीला थी अथवा साई बाबा का एक और चमत्कार, लेकिन पानी से जलाए गए दीपक पूरी रात जलते रहे. शिरडी के दुकानदार भी जड़वत वहीं खड़े होकर प्रज्जवलित दीपों को देखते रहे. उन्हें अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप हुआ और उन्होंने सौगंध लेते हुए बाबा से क्षमा–याचना की कि वे भविष्य में कभी ऐसा अनुचित आचरण नहीं करेंगे.

## हमारी भक्ति

साई बाबा के जीवन एवं सच्चरित्र और आपकी अपनी भक्ति से संबंधित किसी एक विषय पर यहां परिचर्चा की जाएगी और श्रेष्ठ विचार भेजने वाले साई भक्त के विचार यहां प्रकाशित किए जाएंगे.

*आज का विषय : आज समाज को साई शिक्षा की कितनी आवश्यकता है?*

**आपके जवाब**

1. आज सब कुछ बाज़ार में बदलता जा रहा है. उपभोक्तावादी संस्कृति ने रिश्तों का महत्व लगभग ख़त्म कर दिया है. स्वार्थ की भावना सिर चढ़कर बोल रही है. मनुष्य–मनुष्य के ख़ून का प्यासा हो गया है. ऐसे में प्रेम, दया और करुणा से भरी साई बाबा की शिक्षा भटके हुए समाज को सही दिशा दिखा सकती है.

***संजय बाजपेई (एडवोकेट),** कानपुर, उत्तर प्रदेश. (सर्वश्रेष्ठ विचार)*

2. मुझे लगता है, आज के समाज को केवल साई बाबा की शिक्षा की आवश्यकता है. हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई होने का भेदभाव भूलकर अगर हम साई शिक्षा पर अमल करते हुए केवल इंसान बन सकें तो समाज ही नहीं, संसार का भी कल्याण होगा. ***ललिता मिश्रा,** लाजपत नगर, नई दिल्ली.*

3. पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित आज की युवा पीढ़ी और आज का समाज भटक गया है. उसे सही रास्ते पर लाने का काम सिर्फ साई बाबा की शिक्षा ही कर सकती है, क्योंकि साई बाबा किसी भी विचार का विरोध न करके उसे अपने भीतर आत्मसात करने की शिक्षा देते थे, न कि उसके रंग में रंग जाने की.

**राज पांडे,** *ग़ाज़ीपुर, बिहार.*

आप अपने विचार sai4world@gmail.com पर मेल करें अथवा शिरडी साईबाबा फाउन्डेशन, पोस्ट बॉक्स नम्बर-17517, मोतीलाल नगर नम्बर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-58 पर डाक द्वारा भेजें या 09999989427 पर एसएमएस करें.

**अगले सप्ताह का विषय**
**क्या साई बाबा के जन्म स्थान, धर्म आदि के बारे में किए जा रहे दावे सच हैं?**

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious Studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Fumished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

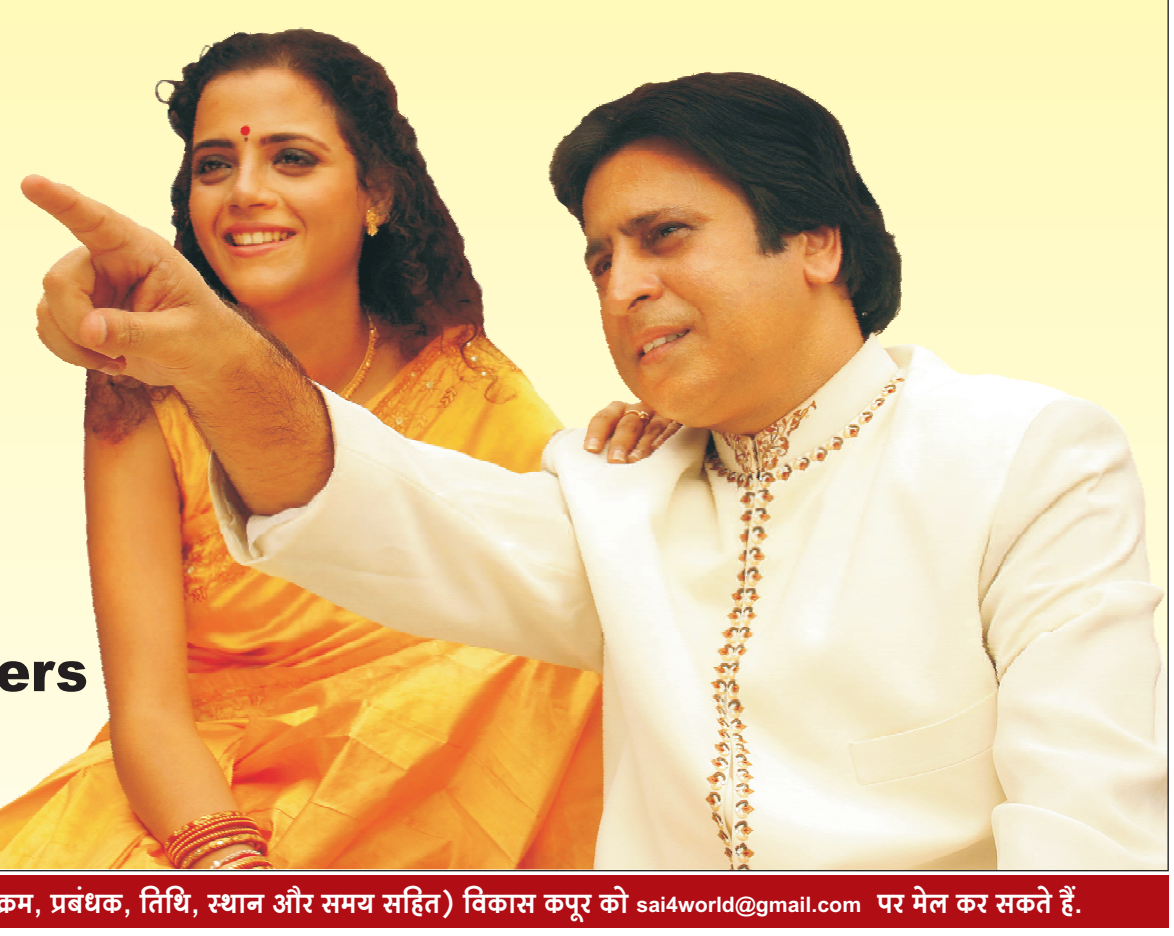

AUM Infrastructure & Developers

Aum Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.girirajsaihills.in

कुंभ कहीं भी आयोजित हो वह परंपराओं के दायरे में रहकर आयोजित किया जाता है. हमारा पूजनीय साधु समाज भी परंपरागत रीति-रिवाज़ों की दुहाई देते हुए ही कुंभ के सारे कार्य संपन्न करता और करवाता है.



# आंखें खोलो प्रगतिवादी साथी

अनंत विजय

दुनिया भर में मशहूर कूची के जादूगर मकबूल फिदा हुसैन के कतर की नागरिकता स्वीकार करने पर देशभर में कुछ चुनिंदा वामपंथी सेकुलर लेखकों और कार्यकर्ताओं ने हो हल्ला मचाया. हुसैन के भारत छोड़ने को इन परम सेकुलरवादियों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ दिया. उन्हें लगने लगा कि भारत ने यह नायाब हीरा देश में संघ और उससे जुड़े अतिवादी हिंदुओं की वजह से खो दिया. वे इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित दिखाई देते रहे कि हुसैन का विरोध उनके मुसलमान होने के कारण हो रहा है. हुसैन के विरोधियों की इस बात के लिए भी लानत मलामत की गई कि वो कौन होते हैं यह कहने वाले कि हुसैन पैगंबर की तस्वीर बना कर दिखाएं. तर्क यह कि एक कलाकार को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जो चाहे उसे चित्रित करे. लेकिन हुसैन के इस्लाम से संबंधित कोई भी चित्र नहीं बनाने से तथाकथित सेकुलरवादियों का यह तर्क कमज़ोर होता है. कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कुरान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का चित्रण हो. असली सवाल यहीं उठ खड़ा होता है कि क्या एक कलाकार की अभिव्यक्ति पवित्र कुरान और इस्लाम की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता?

जब तक भारत में इन सवालों पर बहस होती या फिर कला और कलाकार के पक्ष में खड़े होने का दंभ भरनेवाले प्रगतिवादी, जनवादी लेखक विरोध का डंडा-झंडा संभालते, हुसैन के एक इंटरव्यू ने उन सबकी हवा निकाल दी. हुसैन ने कतर से दिए एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया कि उनके भारत छोड़ने की वजह कुछ और भी है. हुसैन ने माना कि भारत में उनका रहना मुमकिन नहीं था लेकिन इसके बाद जो बात हुसैन ने कही उस पर तो छाती कूट अभियान चला रहे इन प्रगतिवादियों के पांव तले से भी ज़मीन खिसक गई. हुसैन ने अपने साक्षात्कार में कहा कि वो तीन मुख्य प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे- पहला मोहनजोदाड़ो से लेकर मनमोहन सिंह तक के भारतीय सभ्यता का इतिहास, बेबीलोन और विश्व की दूसरी अन्य सभ्यताओं का इतिहास और भारतीय सिनेमा के सौ वर्षों का इतिहास. हुसैन ने माना कि भारत में इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए उनको प्रायोजक नहीं मिल रहे थे. इसलिए जब कतर के शेख मोज़ा ने उनकी इस योजना को प्रायोजित करने की इच्छा जताई तो वो मना नहीं कर सके. मकबूल फिदा हुसैन ने यह भी माना कि भारत में कला के लिए उचित माहौल नहीं है लेकिन उसके पहले प्रायोजक नहीं मिलने की बात कहकर हुसैन ने अपनी असली परेशानी ज़ाहिर कर दी. इसके अलावा हुसैन ने जो एक बात और साफगोई से मानी वह यह कि भारत में टैक्स का ढांचा बेहद जटिल और परेशान करनेवाला है और यह भी उनके देश छोड़ने की वजहों में से एक है.

हुसैन के इन बयानों से यह साफ़ हो गया कि हुसैन ने अतिवादियों से परेशान होकर तो शायद भारत छोड़ा होता लेकिन उनकी परेशानी की वजह सिर्फ़ उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं था. अगर सिर्फ़ यह वजह होती तो हुसैन भारत जैसे सहिष्णु समाज को छोड़कर कतर जैसे कट्टर देश को नहीं चुनते. भारत में हुसैन को मुट्ठी भर लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा था, कमोबेश वे अपनी कलाकृतियों में अपनी जादुई कूची का रंग भर सकते थे लेकिन कतर में वे सिर्फ़ एक दरबारी पेंटर भर होकर रह जाएंगे. अगर हुसैन को भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिल रही थी और वो भगवा ब्रिगेड की गुंडागर्दी से परेशान थे तो कतर में उन्हें कौन सी आज़ादी मिलेगी. भारत में जितने हुसैन के विरोधी हैं उनसे ज़्यादा उनके समर्थक हैं. लेकिन पैसे और व्यावसायिक कारणों से हुसैन ने भारत को छोड़ने का फ़ैसला लिया और उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ने का खेल खेला गया. अब कतर में हुसैन मजे में हिंदू देवी देवताओं के नंगे और शर्मसार करने वाले चित्र बेख़ौफ़ होकर बना पाएंगे, वहां के शासकों की पसंद का ख्याल रखेंगे. लेकिन क्या हुसैन वहां रहकर कतर के शासकों का चित्र में प्रयोग कर पाएंगे. क्या कतर की ख़ूबसूरत औरतों में उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखाई देगी. क्या वहां के समाज की रूढ़िवादिता पर हुसैन की कूची चल सकेगी. या फिर भारी भरकम रक़म के नीचे एक कलाकार की कला दब कर रह जाएगी?

ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनपर भारत के बयानवीर लेखकों को विचार करना चाहिए. दरअसल मार्क्स के इन आधुनिक चेलों को मार्क्सवाद ने हर चीज़ को देखने की एक नई दृष्टि तो दी लेकिन उनकी दूसरी आंख से सच्चाई देखने की दृष्टि छीन ली. वो हर चीज़ को अब मार्क्सवाद के लाल चश्मे से देखने लगे. तस्लीमा का मामला अभी ताज़ा है. कर्नाटक के एक अख़बार ने तस्लीमा के एक पुराने लेख को छाप दिया, जिसपर वहां कई ज़िलों में जमकर हिंसा हुई. विरोध इतना बढ़ा कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और लाखों की संपत्ति का नुक़सान हुआ. विरोध बढ़ता देखकर कर्नाटक सरकार ने आनन-फानन में तस्लीमा के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ करा दिया. जबकि तस्लीमा यह सफाई दे चुकी थी कि उन्होंने कन्नड़ के अख़बार के लिए कोई लेख लिखा ही नहीं था. हुसैन के भारत छोड़ने पर बुक्का फाड़कर विलाप करनेवाले इन प्रगतिवादियों को तस्लीमा पर हो रहा अत्याचार नहीं दिखाई दे रहा. दरअसल मार्क्स के इन चेलों ने सबसे आधुनिक होने का दावा करनेवाले ने इस वाद को उतना ही भ्रष्ट किया है जितना हिंदू धर्म को पोंगा पंडितों ने. इन कथित मार्क्सवादियों के दोहरे रवैये की वजह से ही हिंदुओं, जो कि साधारणतया सहिष्णु होते हैं, के मन में भी यह सवाल उठने लगता है कि बुद्धिजीवियों का एक वर्ग सिर्फ़ हिंदुओं के ख़िलाफ़ ही सेकुलर क्यों होता है? प्रगतिशीलता का ताना-बाना धारण किए इन बुद्धिजीवियों को यह लगता है कि अगर वे हिंदुओं का विरोध नहीं करेंगे तो वे न तो प्रगतिशील रह पाएंगे और न ही सेकुलर.

अंत में इतना कहना चाहता हूं कि हुसैन ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारतीय संविधान सिर्फ़ एक काग़ज़ का टुकड़ा है. अगर किसी भी देशवासी के मन में उसके संविधान को लेकर इतनी ही इज़्ज़त है तो फिर वो देश छोड़कर जाए या रहे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता.

*(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं)*

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश

# मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

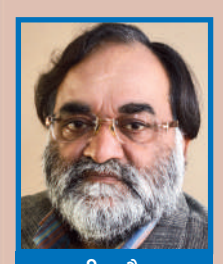

प्रदीप सौरभ

वह बोलते, गुजरात अब माखनचोर कृष्ण नहीं रहा है. वह अब जवान हो गया है. उसके हाथ में सुदर्शन चक्र है.

इस तरह वह मुसलमानों को अप्रत्यक्ष रूप से धमकाते. रामजन्म भूमि आंदोलन के बाद गुजरात में राम की जगह कृष्ण ने ले ली थी. गुजरात में राम से ज़्यादा कृष्ण की चलती है. कृष्ण भक्तों की धरती गुजरात में मोदी के सुदर्शनधारी कृष्ण चल गए थे. रौद्र रूप वाले कृष्ण. वैसे तो हिंदू ब्रिगेड का लीलाधारी मुस्कान बिखेरने वाले राम और कृष्ण दोनों से छत्तीस का आंकड़ा दिखता है. रामजन्म भूमि आंदोलन के समय भी राम को धनुष बाण लिए हिंदू ब्रिग्रेड ने अपनी प्रचार सामग्री में उतारा था. मर्यादा पुरषोत्तम वाले राम की विनयभरी मुस्कान वाली मूर्ति को उसने खंडित कर दिया था. राम गुस्से में थे. अब मोदी सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को गुजरात का ब्राण्ड एंबेसडर बनाने पर उतारू थे. यदि हिंदू ब्रिगेड की ही मानें, तो हिंदू धर्म अहिंसा में विश्वास रखने वाला धर्म है. हिंसा प्रतिहिंसा में उसका विश्वास नहीं है. फिर भी हिंदू आस्था के प्रतीकों को हिंसक रूप में पेश किया गया.

यात्रा चलने लगी. उस समर्थन मिलने लगा. मोदी उत्साहित थे. देश का पूरा मीडिया यात्रा को कवर कर रहा था. एक दिन मोदी ने आनंद भारती को अपने रथ में बुलाया. बोले देखो हमारा पांच करोड़ गुजरातियों का नारा चल गया. कांग्रेस भी अब इसका प्रयोग कर रही है. वह बोलते कम, सुनते ज़्यादा. यात्रा के हर चरण में आनंद भारती से मोदी की रथ में मुलाकात होने लगी.

आनंद भारती ने एक बार पूछा आप मिथकीय चरित्रों के माध्यम से क्यों बात कर रहे हैं?

मोदी ने जवाब दिया, जनता इसी भाषा को समझती है. इनके प्रयोग से बात सीधे लोगों के दिल तक उतर जाती है.

सुदर्शन चक्रधारी गुजरात आप जब बोलते हैं तो इसके पीछे आप मुसलमानों को धमकी देते हुए दिखते हैं. आनंद भारती ने दूसरा सवाल उठाया.

नहीं, हम गुजरात के जवान होने की बात बताते हैं. वैसे आप जो समझना चाहे समझें. मोदी ने जवाब दिया.

मोदी का जादू चल गया था. इस बीच मोदी ने मुसलमानों को सीधा धमकाया. बोले राहत शिविर बच्चे करने की जगह बन गए हैं.

ये सब नहीं चलने दिया जाएगा. इस देश में एक आदमी दर्ज़नों बच्चे पैदा करता है. एक का दो. दो का चार. चार का आठ. आठ का सोलह. सोलह का बत्तीस. बत्तीस का चौंसठ. चौंसठ का एक सौ अट्ठाइस. एक सौ अट्ठाइस का दो सौ छप्पन. दो सौ छप्पन का पांच सौ बारह.

इस पर ख़ूब बवेला मचा. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस पर हस्तक्षेप किया. विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मोदी ने सही कहा और वह पूरे गुजरात में उनके इस भाषण के पच्चीस हज़ार ऑडियो टेप बांटेगी. मोदी भी नहीं डरे. यात्रा के अगले चरण में नौसारी ज़िले के उनाई में मीडिया को फिर ललकारा. कहा अपने कैमरे वैमरे ठीक कर लो. डायरी कलम दुरुस्त कर लो. नहीं तो कहोगे कि मौक़ा हाथ से निकल गया. मोदी ने आठ का सोलह वाला भाषण फिर दोहरा दिया.

मोदी पूरे गुजरात को चुनाव से पहले हर हाल में सांप्रदायिक आधार पर बांट देना चाहते थे. रथयात्रा जैसे जैसे परवान चढ़ रही थी मोदी संघ परिवार के हिंदुत्व एजेंडे को पूरी वफ़ादारी से रख रहे थे. दंगे शांत होने लगे थे. यह इसलिए भी ज़रूरी था कि सांप्रदायिक बंटवारे की तपिश कम न हो. शुरुआत में मोदी की रथयात्रा से खुलेतौर पर दूर रहने वाले संघ परिवार के संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गावाहिनी आदि भी रथयात्रा में खुल कर शिरकत कर रहे थे.गुजरात पटरी पर आ रहा था. ज़िंदगी ढर्रे पर वापस जाने के लिए बेचैन थी. यात्रा का तीसरा चरण पूरा हो चुका था.

feedback@chauthiduniya.com

# चौथा शाही स्नान जनता के अधिकारों पर डाका है

चर्चा कुंभनगर की

डॉ. कमलकांत बुधकर

हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ को लेकर एक ताज़ा समझौता साधु-संतों के तेरह अखाड़ों की परिषद् तथा कुंभ प्रशासन के बीच हुआ है. इस समझौते के मुताबिक़ सभी तेरहों अखाड़े 15 मार्च के सोमवती अमावस्या और 14 अप्रैल के मुख्य कुंभ स्नान के बीच में 30 मार्च को एक और स्नान करेंगे और प्रशासन इस स्नान को भी शाही स्नान का दर्ज़ा देगा.

सामान्यतया हरिद्वार आकर कोई भी साधु-संन्यासी अथवा कोई भी गृहस्थी कितनी ही बार अकेले या समूह में आकर गंगास्नान कर सकता है. उस पर कोई पाबंदी नहीं है. गंगास्नान, व्यक्ति का नितांत निजी मामला है. उसे पूरा अधिकार है कि वह चाहे जितनी बार गंगा नहाए. जिस सार्वजनिक घाट पर नहाना चाहे वहां नहाए. अगर उसके गंगा नहाने से किसी और के अधिकारों का हनन नहीं होता है, तो वह गंगा नहाता रहे. पर अगर उसके नहाने से किसी और के अधिकारों का हनन होता है तो फिर यह बात चिंता के घेरे में आ जाती है. अखाड़ों और प्रशासन के इस ताज़े फ़ैसले से कुछ ऐसा ही हुआ है जिस पर चिंता, चिंतन और पुनर्विचार की आवश्यकता है. दोनों पक्षों ने मिलकर यह एक ऐसा फ़ैसला ले लिया है जो परंपरा-सम्मत तो है ही नहीं, परंपराभंजन और जनाधिकार विरोधी भी है.

कुंभ कहीं भी आयोजित हो वह परंपराओं के दायरे में रहकर आयोजित किया जाता है. हमारा पूजनीय साधु समाज भी परंपरागत रीति-रिवाज़ों की दुहाई देते हुए ही कुंभ के सारे कार्य संपन्न करता और करवाता है. कुंभ के संदर्भ में शासन और प्रशासन भी हिंदुओं के इस महापर्व की पारंपरिकता के रक्षण के लिए हमेशा से वचनबद्ध रहता आया है. मुसलमानों, मुगलों और अंग्रेजों तक ने हमारी इस परंपरा का निर्वाह किया है. इसमें कोई आपत्तिजनक बात है भी नहीं और आज भी सामान्यजन इस परंपरा निर्वाह के साथ बड़ी श्रद्धा से जुड़ते चले आते हैं.

हरिद्वार के संदर्भ में देखें तो शाही स्नान की यह परंपरा केवल तीन शाही स्नानों की है. ये तीन शाही स्नान महाशिवरात्रि, चैत्र अमावस्या और मुख्य कुंभपर्व पर संपन्न होते हैं. महाशिवरात्रि का पहला शाही स्नान केवल संन्यासी अखाड़ों का ही होता है. तब बैरागी वैष्णव अखाड़े वृंदावन में एकत्र होते हैं. चैत्र अमावस्या से पहले अलबत्ता बैरागी हरिद्वार पहुंच चुके होते हैं, अतएव बाद के दोनों स्नानों पर तेरहों अखाड़े अपने अपने क्रम से गंगास्नान करते हैं. सैकड़ों बरसों से यहां इन्हीं तीन शाही स्नानों की परंपरा चलती आ रही है. इसके अलावा कुंभ स्नान के बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन बैरागियों की जमात के द्वारा अलग से गंगास्नान करने की परंपरा भी रही है, पर यह स्नान शाही स्नान की कोटि में नहीं माना जाता है.

शाही स्नान के दिन हरिद्वार के मुख्य और अमृत-पावन माने जाने वाले स्नान स्थल हरकी पौड़ी पर साधु-संतों के तेरहों अखाड़े बाजेगाजे, हाथी-घोड़े, रथ-पालकियों सहित शोभायात्रा के साथ आकर अपने अपने अखाड़े के देवताओं, भालों, आचार्यों, महामण्डलेश्वरों और नागा तथा वस्त्रधारी साधुओं के साथ गंगास्नान करते हैं. ऐसे शाही स्नान दिवस पर लगभग आठ-दस घंटों के लिए हरकी पौड़ी ब्रह्मकुण्ड पर सामान्य श्रद्धालु तीर्थयात्री को न जाने दिया जाता है और न नहाने दिया जाता है. जो व्यक्ति हज़ारों मील चलकर और हज़ारों रुपए ख़र्च करके, यात्रा के सारे कष्ट और असुविधाएं झेलता हुआ हरिद्वार आता है वह सदियों से चली आ रही इस परंपरा के चलते हरकी पौड़ी पर स्नान करने से वंचित रह जाता है. पर उसे परंपरा और श्रद्धा के चलते कोई शिक़ायत नहीं होती.

लेकिन इस बरस हरिद्वार कुंभ में कुछ नया ही हो रहा है. कुंभ के शाही स्नानों में एक और शाही स्नान की बढ़ोत्री करके सामान्य श्रद्धालुओं का हरकी पौड़ी ब्रह्मकुण्ड पर नहाने का अधिकार उनसे छीना जा रहा है. अनेक ज्येख़-श्रेख़संत और बड़ी संख्या में साधु समाज भी इस निर्णय से व्यथित हैं. कई अखाड़ों अनेक महामण्डलेश्वर भी इस अपरंपारिक स्नान में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वे इसे सरासर परंपराभंजन ही मानते हैं. लोगों का मानना है कि अखाड़ा परिषद् और कुंभ प्रशासन का यह निर्णय जनता को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है. यदि यह निर्णय लेने से पहले आम जनता की हरकी पौड़ी स्नान की इच्छा-आकांक्षा और भावनाओं का ख़याल रखा होता तो यह परंपरा विरोधी निर्णय न लिया जाता.

कुछ लोग इस निर्णय को नवयुग की नई परंपरा का बीजारोपण कह रहे हैं. ऐसे लोगों को वे कहते हैं कि नई परंपराएं डालने में क्या हर्ज़ है. बहुत अच्छी बात है. नई और स्वस्थ और समयानुकूल परंपराएं डालने में कोई हर्ज़ा नहीं है. पर उन्हें इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि सैकड़ों करोड़ रुपए ख़र्च करके तथा हज़ारों शासकीय कर्मचारियों के कार्य दिवस पर ख़र्च करके की जाने वाली व्यवस्थाएं क्या केवल तीस चालीस हज़ार साधुओं के लिए ही होती हैं. ऐसा नहीं है. बल्कि सच यह है कि कुंभपर्व लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का भी उतना ही है जितना चंद साधु संतों का. सरकारी पैसा और सरकारी समय ख़र्च करके सारी व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए की जाती हैं. यह अलग बात है कि हमारे आदरणीय संतगण अधिकांश सुविधाएं और व्यवस्थाएं सिर्फ़ साधु समाज के लिए ही मान बैठे हैं और वक़्त की नज़ाकत के चलते प्रशासन भी केवल उन्हीं की मांगों, व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर अधिक ध्यान दे रहा है. चौथे शाही स्नान का निर्णय भी संतसमाज की इसी दबाव की नीति और 3शासन-प्रशासन की उनके आगे निरीहता का नतीजा है.

अखाड़ा परिषद् को अगर नई परंपरा शुरू करनी ही थी तो वह उस गृहस्थ समाज की भावनाओं को देखते हुए करती जिनके दान-पुण्य और श्रद्धा पर साधु समाज टिका हुआ है. अखाड़ा परिषद् को सोमवती अमावस्या का शाही स्नान आम जनता को समर्पित करके कुंभ का वास्तविक पुण्यार्जन करना चाहिए था. नई परंपरा ही शुरू करनी ही थी तो इक्कीसवीं सदी में भी विवस्त्र नागाओं के गंगास्नान पर चिंतन किया जाना चाहिए था. आज जब सामान्य परिवारों में भी तीन साल के बच्चों तक को नग्न नहीं रहने दिया जाता, समाज में लोग इसे असभ्यता मानते हैं तब युवा वृद्ध नागा संन्यासियों को खुले आम सड़कों पर शोभायात्रा में ले जाना और उनका सार्वजनिक स्थल पर नग्न होकर स्नान करना चिंतन का विषय हो सकता था. इस परंपरा पर पुनर्विचार करना चाहिए था. अगर कुंभ को नया रूप ही देना था तो उसे जनोन्मुखी बनाने की सोचते. शाहों-शहंशाहों के बीते युग के शाही स्नान की जगह नए फ़कीरी स्नान की परंपरा डालते. पर ऐसा सब कुछ करने में अगर परंपराएं बाधा बन रही थीं तो फिर यह चौथे स्नान की नई परंपरा डालने का भला क्या मतलब था? यह जनविरोधी निर्णय लेकर अखाड़ा परिषद् के हमारे पूज्य संतों ने आम जनता से चैत्र पूर्णिमा के दिन हरकी पौड़ी पर स्नान करने का पुण्य अवसर छीन लिया है. क्या यही अच्छा होता कि कुंभ प्रशासन और अखाड़ा परिषद् मिलकर निर्णय लेते कि 30 मार्च को चैत्र पूर्णिमा का स्नान साधु समाज आम जनता के साथ करेगा. यूं भी तो अखाड़े अपने शाही जुलूसों में साधुओं से ज़्यादा गृहस्थियों को ले ही जाते हैं. अंतर केवल यह है कि वे गृहस्थ उनके अपने दान-दक्षिणा देने वाले चेले चपाटे और उनके परिवार होते हैं. असल में बेचारे आम स्नानार्थी के बारे में न तो प्रशासन सोच रहा है और न ही साधु समाज.

kk@budhkar.in

देश में अपने कुछ नेटबुक और नोटबुक लांच करने के बाद कंपनी ने भरपूर मुनाफा पाया है. इससे खुश होकर एमएसआई ने देशवासियों के लिए तोहफे के तौर पर नई घोषणा की है.

# बाथरूम में गूंजे संगीत

अक्सर हम बाथरूम में नहाते हुए कोई गीत गुनगुनाते हैं. कुछ लोग तो प्राय: एक ही गीत रोज गुनगुनाते हैं, क्योंकि वह गीत उनकी ज़ुबान पर चढ़ा होता है. कई बार उनके सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता. ऐसे में अगर उन्हें कोई नया या अपना पसंदीदा गीत सुनने को मिल जाए तो क्या बात हो. कुछ लोग म्यूज़िक के इतने शौकीन होते हैं कि वे चाहे जहां भी रहें, उन्हें म्यूज़िक सुनना ही होता है. संगीत और गानों के शौकीन लोगों के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं होगा कि वे किसी भी समय और किसी भी जगह पर म्यूज़िक सुन सकें, चाहे वो नहाने का वक़्त ही क्यों न हो. पर हम सब जानते हैं कि पानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का मेल कुछ अच्छा नहीं है. तो क्या आप यक़ीन कर पाएंगे कि पानी के टब या शॉवर में आपके साथ एमपी थ्री प्लेयर स्पीकर्स भी रह सकता है? जी हां, ऐसा मुमकिन होने वाला है. आजकल टेक्नॉलॉजी ने इतनी तरक़्क़ी कर ली है कि यह सपना भी हक़ीक़त बन सकता है. हाल ही में एक जापानी कंपनी द्वारा लांच की गई म्यूज़िक प्लानेट एमपी थ्री प्लेयर स्पीकर्स, के बारे में दावा किया गया है कि वह वाटरप्रूफ यानी पानी में ख़राब नहीं होने वाला है. गोल आकार का यह छोटा सा स्पीकर गीले होने पर भी बिना डैमेज हुए बेहतरीन म्यूज़िक प्ले करता है. इसमें एफएम रेडियो के साथ अलार्म घड़ी भी है. इसमें अपने कंप्यूटर द्वारा एसडी, एसडीएचसी और यूएसबी ड्राइव के ज़रिए गाने डाले जा सकते हैं. ये वाटरप्रूफ प्लेयर और स्पीकर 6 एए बैट्री पर चल सकेंगे. इसकी बैट्री लगातार 9 से 13 घंटे तक गाने प्ले कर सकती है. इतने फीचर्स के साथ इतना प्यारा गैजेट आपको और कहीं नहीं मिलेगा. नहाना का नहाना और गाना का गाना. तो बस फिर देर मत कीजिए, और आज ही मार्केट से इस एमपीथ्री प्लेयर को ले आइए . इस ख़ास एमपी थ्री प्लेयर स्पीकर्स की क़ीमत 120 डॉलर है.

# ट्रेंडी गैजेट्स का नया ठिकाना

आजकल बच्चे, बड़े या बूढ़े सभी अत्याधुनिक तकनीक के कायल हैं. चाहे वह मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, नोटबुक हो या नेटबुक . बावजूद इसके कि हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी जहां ग़रीब कहलाती है वहीं देखा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तकनीक वाली कंपनियां बेहतरीन मुनाफ़ा प्राप्त कर रही हैं. इस श्रेणी में कई मल्टी नेशनल कंपनियों के नाम के साथ पिछले दिनों एमएसआई (माइक्रो स्टार इंटरनेशनल) का नाम भी जुड़ गया है.

देश में अपने कुछ नेटबुक और नोटबुक लांच करने के बाद कंपनी ने भरपूर मुनाफ़ा पाया है. इससे ख़ुश होकर एमएसआई ने देशवासियों के लिए तोहफ़े के तौर पर नई घोषणा की है. गैजेट्स और ट्रेंडी चीज़ों के प्रति भारत में लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए , एमएसआई ने देश में अपना पहला ब्रांड रिटेल स्टोर खोला है. यह स्टोर हाईटेक हब कहे जाने वाले बेंगलुरू में स्थित है. इस स्टोर को लांच करने के बाद कंपनी इसी साल देश के 80 शहरों में ब्रांडेड आउटलेट खोलेगी. जिससे इस आउटलेट से न सिर्फ़ इस शहर के लोग लाभ उठा पाएंगे, बल्कि दूसरे शहरों के लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे. इस स्टोर में एमएसआई की नोटबुक और नेटबुक को मूल्यों के कई रेंज में लिया जा सकता है. यहां उपलब्ध नेटबुक एमएसआई की अल्ट्रापोर्टेबल श्रृंखला के हैं और नोटबुक स्टाइलिश एक्स स्लिम, क्लासिक, एंटरटेनमेंट और गेमिंग सीरीज़ के हैं. यहां ग्राहकों को आर्डर देने के पहले किसी भी तरह का कंफ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि यहां मेन्यू के ज़रिए अपने पसंदीदा मॉडल के लुक और कॉन्फिगरेशन को अपने अनुकूल बना पाएंगे. कंपनी के ब्रांड आउटलेट पर शुरुआती दौर में प्रत्येक बिक्री पर वायरलेस कीबोर्ड और माउस जैसी चीज़ें बतौर तोहफ़े में दी जाएंगी. एमएसआई ने इससे पहले कुछ गैजेट शॉप में एक्सेस प्वाइंट भी बनाया था, पर भारतीय बाज़ार में क़दम बढ़ाते हुए कंपनी ने एक्सक्लूसिव ब्रांडेड आउटलेट खोलने का मन बनाया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# बच्चों के लिए हाइटेक लोककथाएं

आजकल एकल परिवार का चलन बढ़ने की वजह से दादा-दादी के किस्सों के रूप में बच्चों को कहानियां सुनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है. ऐसे में आजकल के बच्चे उन अमर चित्र कथाओं से महरूम रहते हैं और इस तरह इन कथाओं के जरिए मिलने वाली शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं. यही वजह है कि आजकल के बच्चे उन संस्कारों, परंपराओं और रीति-रिवाजों से अंजान रह जाते हैं. बच्चों को इन कथाओं से परिचित कराने के लिए एसीके मीडिया ने एंडरॉएड (मल्टीमीडिया में फीचर की एक नई तकनीक) का माध्यम अपनाया है. कंपनी की ओर से ऐसी अमर चित्र कथाओं को बच्चों की पसंद अनुसार एंडरॉएड तकनीक के इस्तेमाल से दिखाया जाएगा. इस कंपनी ने अब तक टिंकल, करादी टेल्स, सुपंडी, शिकारी शंभु, आदि के साथ अब अमर चित्र कथा के नाम से नई कथा सीरीज को जोड़ा है. अमर चित्र कथा की सभी कथाएं एंडरॉएड हैं और आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध होंगी. इसके लिए कंपनी ने एमओ फर्स्ट नाम की मोबाइल एप्लीकेशन प्रोड्क्टस व सर्विसेज कंपनी के साथ गठबंधन किया है. एसीके मीडिया बच्चों और युवाओं के मनोरंजन व ज्ञान के लिए प्रिंट, ऑनलाइन सर्विसेज, मोबाइल, गेम्स, टेलीविज़न, फ़िल्म व अन्य चीज़ें बनाती है. अमर चित्र कथाओं की सीरीज़ में भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्रचलित सुपर हीरो की कहानियों को रेखाचित्रों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जाएगा. इन कथाओं को फुल कलर हाई रीज़ोल्यूशन में लाइव वालपेपर और विशेष जूम जैसे विकल्पों के साथ उपलब्ध कराया जाएगा. 1967 से अबतक अमर चित्र कथा की 90 मिलियन कॉपियां पौराणिक कथाओं, महाकाव्यों और किस्सों-कहानियों के रूप में 400 शीर्षकों के साथ बिक चुकी हैं. कहानी कहने के पुरातन तरीक़े की तरह ही एसीके ने चित्र कथा तैयार की है जिसे कॉमिक रूप में ढाल कर एनिमेशन के ज़रिए डायलॉग और रेखाचित्रों के साथ पेश किया जाएगा. एंडरॉएड पर अमर चित्र कथा और टिंकल के इस सीरीज में कृष्णा, बुद्धा, गीता, साईंबाबा, ईसामसीह, दशावतार, विष्णु और शिव की कथाएं हैं. इन्हें अपने मोबाइल पर लाने के लिए एंडरॉएड एप्लीकेशन लोड करने के बाद अमर चित्र कथा, टिंकल या दूसरी कथाओं के नाम से खोजें. इन्हें ख़रीदने के लिए कुछ शुल्क देय होगा.

# सिक्योरिटी और बिल्डिंग मैनेजमेंट का संगम

रनी डर इलेक्ट्रिक ने हाल ही में जीकॉम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. इसके तहत कंपनी ने जीकॉम के इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम के बिजनेस में साझेदारी करते हुए ख़ुद को मार्केट में इन नए क्षेत्र में स्थापित किया है. कंपनी ने बिल्डिंग सॉल्यूशन ग्रुप और स्पेशल प्रोजेक्ट ग्रुप नाम से इस क्षेत्र में शुरुआत की है. जैसा कि ज्ञात है कि जाइकॉम भारत की सबसे बड़ी और स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम के अंतर्गत सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है. इसने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में फील्ड सिटी सर्विलेंस, रेलवे और एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं. सिर्फ़ इतना ही नहीं जाइकॉम गवर्नमेंट फैसीलिटी, कमर्शियल बिल्डिंग और होटल के प्रोजेक्ट आदि में अपनी गुणवत्ता और बेहतर सुविधा के आधार पर बाज़ार में अपनी पकड़ मज़बूत बना रखी है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जाइकॉम के साथ हाथ मिलाना हर तरीक़े से फ़ायदे का सौदा था. इसी को देखते हुए स्नीडर ने जाइकॉम के साथ साझेदारी की है. इस क़दम से इस कंपनी ने भारत के बाज़ार में उभरते हुए बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ने एक खास मुक़ाम हासिल कर लिया है. स्नीडर इलेक्ट्रिक इंडिया के भारत में कंट्री प्रेसीडेंट ऑलिवर ब्लम के मुताबिक़ हमारा यह क़दम भारत में एक नई क्रांति लाएगा. हमें हमेशा से ही मालूम था कि भारत इस क्षेत्र के लिए उभरता हुआ बाज़ार है. यहां पर बिजनेस के अनुकूल परिस्थितयां है. हमने भी अपने पूरे पेशन के साथ भारतीय बाज़ार में अपना काम करेंगे और यहां के बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम को दुरस्त करते हुए एक नई मिशाल पेश करेंगे.

# युवाओं के लिए हाईटेक बाइक

दोपहिया वाहन उद्योग की अग्रणी कंपनी टीवीएस लगातार बेहतरीन पेशकश कर रही है. कंपनी ने वैश्विक रुझानों के साथ कामयाब तालमेल बनाए रखने और ऑटोमोबाइल डिज़ाइन करने की नई तकनीकों को अपनाकर कई विश्वस्तरीय नए मॉडल्स लांच किए हैं. हाल ही में लांच की गई टीवीएस जाईव भारत की पहली ऑटो क्लच मोटरसाइकिल है. इस खास मॉडल के लिए दावा किया जा रहा है कि स्वदेशी रूप से निर्मित देश की पहली फोर स्ट्रोक बाईक है. 110 सीसी की क्षमता वाले इंजन से लैस इसमें अनूठी टी-मैटिक तकनीक है. टी मैटिक सिस्टम बेहद खास है, जिसमें रोटरी गियर तकनीक है और जिसे ऑटोमेटिक क्लच के साथ जोड़ा गया है.

मोटरसाइकिल की चार स्पीड लेवल, फोर स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन इसे खास बनाती हैं. और साथ में चार ऑटोमेटिक गियर राइडर्स को परेशानी में अक्सर बचा लेते हैं. टीवीएस जाइव 500 आरपीएम पर 8.1 बीएचपी पावर जबरदस्त परफोरमेंस देता है. इस बाइक का 5500 आरपीएम पर 8.1 एनएम का टॉर्क ड्राइव को स्मूथ बनाता है. मात्र 110 किलोग्राम वजन के टीवीएस जाइव को चलाना बिल्कुल आसान और आरामदेह है. इसके एलॉय व्हील्स, इसे 1260 एमएम का व्हील बेस उपलब्ध कराते हैं जिससे मोड़ आदि पर इसे निकालना आसान है. इस बाईक के ईंधन टैंक की क्षमता 12 लीटर की है जिसमें दो लीटर रिजर्व में रह सकता है. क्लच लीवर का न होना, इस मोटरसाइकिल की सबसे खास ख़ूबी है, इससे इस मोटरसाइकिल को चलाना एक हैंडफ्री जैसा अनुभव देता है.

इसका एंटी-स्टॉल मैकेनिज़्म, इस मोटरसाइकिल की एक अन्य अनूठी विषेशता है जिससे ऊंचे गीयर में होने पर भी कम गति पर आसानी से सवारी की जा सकती है और इंजन बंद नहीं होता. यह तकनीक रेग्युलर सिस्टम वाली मोटरसाइकिलों में नहीं पाई जाती. दूसरे बाईक से अलग इसकी एक और ख़ूबी यह है कि इसे स्टार्ट करते समय गियर को न्यूट्रल में रखना कतई ज़रूरी नहीं है. बाइक किसी भी गियर में स्टार्ट की जा सकती है अगर किक मारने में भी असुविधा हो तो इसमें सुगमता के लिहाज़ से इलेक्ट्रिक स्टार्ट का सिस्टम भी फिट किया गया है.

इसकी एक्स-शोरूम क़ीमत 415000 रुपये है. तीन रंगों काले, ब्लू और लाल में उपलब्ध यह बाईक राइडर्स के लिए एक अच्छी च्वाइस होगी.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

जडेजा की इन कोशिशों को आईपीएल के नियमों का उल्लंघन मानते हुए उन्हें एक साल के लिए टूर्नामेंट में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया.



## विश्व कप हॉकी

# हार का ग़म नहीं

नई दिल्ली के नेशनल ध्यानचंद स्टेडियम में खेला गया विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का पहला दिन. एशियाई उपमहाद्वीप के दो चिर-परिचित प्रतिद्वंद्वी, भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थी. दोनों ही टीमों के लिए यह पहला ही मैच था. जब मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होता है तो वह केवल एक मुक़ाबला भर नहीं होता, उसमें भावनाओं का ऐसा सैलाब जुड़ा होता है जिसकी धमक मैदान से बाहर भी दूर तक सुनाई देती है. लोग बेसब्री से इसके शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे. एक बार जब मुक़ाबला शुरू हुआ तो मैदान पर जो देखने को मिला वह किसी सपने से कम नहीं था. शिवेंद्र सिंह, प्रभजोत सिंह, विक्रम पिल्लई और संदीप सिंह के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत पाकिस्तान को 4-1 की करारी शिकस्त देने में कामयाब रहा. जीत के अंतर से ज़्यादा अहम बात यह थी कि भारतीय टीम ने पूरे मुक़ाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और पाकिस्तानी टीम कभी भी आक्रमण करने की हालत में नहीं आ पाई. यह जीत भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कराने वाली थी. लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वह तो किसी भी हालत में एक दु:स्वप्न से कम नहीं था. मैच के अगले दिन अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने शिवेंद्र सिंह को तीन मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया. उनपर जानबूझकर विरोधी टीम के खिलाड़ी फरीद अहमद को चोट पहुंचाने और घायल करने का आरोप लगाया गया. हालांकि, शिवेंद्र के ख़िलाफ़ किसी ने कोई शिक़ायत नहीं दर्ज़ कराई गई थी, लेकिन एफआईएच ने ख़ुद ही मामले का संज्ञान लेते हुए उन पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया. फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील के बाद सजा को कम कर इसे दो मैचों तक सीमित कर दिया गया लेकिन इस सारे प्रकरण ने टीम के मनोबल को इस तरह से प्रभावित किया कि अगले मुक़ाबलों में टीम एक अदद जीत के लिए तरस कर रह गई.

अब ज़रा इस मामले के दूसरे पक्ष को देखें. पाकिस्तान के बाद भारतीय टीम को अपना अगला मुक़ाबला ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ खेलना था. पहले मुक़ाबले में भारतीय टीम ने जो फॉर्म दिखाया था और खिलाड़ियों ने जिस तरह आक्रामक रवैया अपना कर पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित किया था, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे टीम कुछ कर गुजरने के लिए कृत संकल्प है.

हैरत की बात तो यह है कि शिवेंद्र के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने वाले टूर्नामेंट डायरेक्टर केन रीड ऑस्ट्रेलिया के ही हैं. ख़ुद पाकिस्तानी टीम ने माना कि शिवेंद्र के साथ ज़्यादती हुई है. इतना ही नहीं, पाक टीम के एक खिलाड़ी ने तो एफआईएच पर एशियाई खिलाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप तक लगा दिया. भारतीय टीम के साथ अधिकारियों के इस सौतेले व्यवहार का सिलसिला यहीं नहीं रूका. दक्षिण अफ़्रीकी टीम के ख़िलाफ़ अपने चौथे मुक़ाबले में रेफरल प्रणाली ने टीम को एक निश्चित जीत से मरहूम कर दिया. दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ हाफ टाइम तक भारतीय टीम 2-1 से आगे चल रही थी. ब्रेक के बाद मैच के 46वें मिनट में सरवनजीत सिंह के दूसरे गोल की मदद से भारत ने 3-2 की मदद ले ली. तभी विरोधी टीम ने रेफरल की मांग की. वीडियो रेफरल के बाद भारत के गोल को खारिज कर दक्षिण अफ़्रीका को पैनल्टी कॉर्नर दे दिया गया जिसे गोल में तब्दील कर टीम ने उल्टे भारत पर 3-2 की बढ़त हासिल कर ली. मैच अधिकारियों के मनमानेपूर्ण रवैये का कोप टीम को पांच मिनट बाद एक बार फिर झेलना पड़ा, जब टीवी अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद एक और गोल को मानने से इंकार कर दिया. चंद लम्हों पहले जीत के राह पर आगे बढ़ती भारतीय टीम एकबारगी ही हार के मुहाने पर खड़ी थी. वो तो शिवेंद्र सिंह का कमाल था जिन्होंने मुक़ाबला ख़त्म होने के ठीक पहले गोल कर टीम को बराबरी दिलाई और भारत ग्रुप बी में चौथे स्थान पर रहने में कामयाब हुआ. मैच ख़त्म होने के बाद टीम के खिलाड़ियों और कोच के चेहरे पर निराशा स्पष्ट झलक रही थी. कोच होजे ब्रासा ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि रेफरल के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं की जा सकती. अधिकारियों के मनमानेपूर्ण रवैये ने टीम को फिर से जीत की दहलीज से वापस लौटा दिया था. सबसे रोचक बात तो यह है कि इस मुक़ाबले में टीवी अंपायर की भूमिका में इंग्लैंड के एंडी मायर थे. मुक़ाबला ख़त्म होने के बाद दक्षिण अफ़्रीकी टीम के कप्तान ऑस्टिन स्मिथ ने ख़ुद माना कि क़िस्मत ने उन्हें हार से बचा लिया. ऐसे में यदि एशियाई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन पर सौतेलेपूर्ण व्यवहार को आरोप लगाते हैं तो इसे सिरे से ख़ारिज नहीं किया जा सकता. हालांकि, टीम के इस प्रदर्शन के लिए केवल विदेशी अधिकारियों को ही ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ मुक़ाबले के बाद कोच ब्रासा ने कहा कि मैदान पर पानी की कमी के चलते उनके खिलाड़ियों को कठिनाई हुई. हैरत की बात तो यह है कि मैच शुरू होने से पहले उन्होंने इस बाबत टेक्निकल ऑफिसर से शिक़ायत भी की थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. अब यदि अपने घरेलू मैदान पर भी किसी टीम को ऐसी मुश्किलों से दो-चार होना पड़ता है तो उसके हश्र के बारे में सहज ही कल्पना की जा सकती है. ख़ुद इंडियन हॉकी फेडरेशन अपनी भूमिका का सही निर्वाह करने में नाकाम रहा है. विश्व कप से ठीक पहले खिलाड़ियों ने फेडरेशन के ख़िलाफ़ बकाया भुगतान को लेकर मोर्चा खोल दिया. खिलाड़ियों की मांग थी कि पहले उन्हें उनके बकाया पैसों का भुगतान किया जाए तभी वे ट्रेनिंग कैंप में भाग लेंगे. जब दोनों पक्ष अपनी मांग पर अड़े रहे तो काफी जद्दोजहद और कई राज्य सरकारों एवं पूर्व खिलाड़ियों ने बीच बचाव कर सुलह करवाया तभी जाकर ट्रेनिंग कैंप शुरू हो पाया. लेकिन इससे टीम की तैयारियों पर बुरा असर पड़ा. इससे पहले भी टीम के चुनाव में फेडरेशन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं. विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में दीपक ठाकुर का चयन इसका सबसे ताजा उदाहरण है. दीपक को पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद भी टीम में जगह दी गई और कोई आश्चर्य नहीं कि उनके ख़राब प्रदर्शन से टीम की सुरक्षा पंक्ति प्रभावित हुई हो.

यह कड़वा सच है कि भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर भी विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने में नाकाम रही, लेकिन केवल खिलाड़ियों को ही इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता. उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी. अब यह बात और है कि क़िस्मत और परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया और रही-सही कसर टूर्नामेंट अधिकारियों ने पूरी कर दी. फिर भी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिली जीत और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए भविष्य के सपनों को उड़ान तो दी ही जा सकती है. और पिछले कई सालों से जिस तरह भारतीय हॉकी लगातार पतन के गर्त की ओर जाती नज़र आई थी, उसे देखते हुए यह उपलब्धि कोई कम नहीं है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

# आईपीएल 3 से बाहर रहेंगे रवींद्र जडेजा

आईपीएल और बीसीसीआई के मनमाने रवैये के चलते भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और इंडियन प्रीमियर लीग के पहले दो सीजन में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलने वाले रवींद्र जडेजा टूर्नामेंट के तीसरे सीजन में शरीक नहीं हो पाएंगे. जडेजा पर आरोप है कि उन्होंने बिना पूर्व अनुमति के दूसरी टीमों के साथ अनुबंध करने के लिए मोल-भाव करने की कोशिश की.

जडेजा की इन कोशिशों को आईपीएल के नियमों का उल्लंघन मानते हुए उन्हें एक साल के लिए टूर्नामेंट में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया. जडेजा ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की, लेकिन बीसीसीआई ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और भारतीय क्रिकेट का यह उभरता हुआ सितारा खेल के इस सबसे ग्लैमरस अवतार में अपनी भागीदारी से वंचित रह गया.

हालांकि, जडेजा इन आरोपों से इंकार कहते हैं. उनका कहना है कि राजस्थान रॉयल्स के साथ उनका करार दिसंबर 2009 में ही ख़त्म हो गया था और इसके नवीकरण के संबंध में टीम प्रबंधन ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी. उनका यह भी कहना है कि वह दूसरी टीमों से बातचीत करने से पहले बीसीसीआई की अनुमति लेने को इच्छुक थे, लेकिन अनेक कारणों से ऐसा नहीं हो पाया.

ताज्जुब की बात तो यह है कि जडेजा की अपील पर आईपीएल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए. आईपीएल के चेयरमैन ललित मोदी ने एक बयान में कहा कि अपील पर फ़ैसला लेने का अधिकार केवल बीसीसीआई के पास है. बीसीसीआई ने उनकी अपील को खारिज करते हुए यह तर्क दिया कि वह इस फ़ैसले के माध्यम से बाक़ी खिलाड़ियों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहती है ताकि ऐसे मामले दोबारा न हों. घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र के लिए खेलने वाले जडेजा भारतीय वनडे टीम के एक स्थायी सदस्य हैं. अब सवाल यह है कि यदि जडेजा को अनैतिक व्यवहार का दोषी मानते हुए उन्हें आईपीएल में खेलने से रोका गया तो फिर वह भारतीय टीम इंडिया का हिस्सा कैसे बने रह सकते हैं. साथ ही यह भी कि किसी टीम के साथ अनुबंध की अवधि ख़त्म होने के बाद यदि कोई खिलाड़ी दूसरी टीम के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, तो इसे अनैतिक कैसे ठहराया जा सकता है.

**जडेजा इन आरोपों से इंकार कहते हैं. उनका कहना है कि राजस्थान रॉयल्स के साथ उनका करार दिसंबर 2009 में ही खत्म हो गया था और इसके नवीकरण के संबंध में टीम प्रबंधन ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी.**

# पाकिस्तान में कई क्रिकेट खिलाड़ियों पर बैन

ऑस्ट्रेलिया दौरे में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में मचा भूचाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है. कोच के रूप में वकार युनुस की नियुक्ति के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टीम के दो पूर्व कप्तानों मोहम्मद युसुफ और यूनुस खान पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है जबकि एक और पूर्व कप्तान शोएब मलिक एवं तेज गेंदबाज़ नावेद उल हसन राणा पर एक-एक साल का प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल एवं उनके छोटे भाई उमर अकमल एवं ऑलराउंडर शाहिद अफ़्रीदी पर भारी आर्थिक जुर्माना आरोपित किया गया है.

ग़ौरतलब है कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था और पूरे दौरे में टीम एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी. दौरे के बीच में ही टीम में गुटबंदी और खिलाड़ियों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा था. टीम के स्वदेश वापस लौटने पर पीसीबी ने एक जांच समिति गठित की थी. वसीम बारी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कई खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की थी.

पीसीबी ने हालांकि समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया, लेकिन इसके आधार पर खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. ख़बरों के मुताबिक़ रिपोर्ट में मोहम्मद युसुफ, युनुस खान, शोएब मलिक एवं नावेद उल हसन राणा पर टीम हितों के ख़िलाफ़ काम करने का आरोप लगाया गया है. दौरे पर विकेटकीपिंग एवं बल्लेबाजी में बुरी तरह असफल रहने वाले कामरान अकमल के बारे में कहा गया है कि आख़िरी टेस्ट से पहले उन्होंने पीसीबी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ टीम में ख़ुद के शामिल होने संबंधी बयान दिए थे, जबकि उमर अकमल ने इसी मैच में चोटिल होने का बहाना करते हुए टीम से बाहर रहने की कोशिश की थी. पाकिस्तानी टी-20 टीम के कप्तान शाहिद अफ़्रीदी पर जानबूझकर गेंद की हालत बिगाड़ने और पाकिस्तानी क्रिकेट की प्रतिष्ठा कम करने का आरोप है. इस अपराध के लिए आईसीसी पहले ही अफ़्रीदी को दंडित कर चुकी है.

पीसीबी की इस कार्रवाई के बाद कुछ ही दिनों बाद होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियों पर बुरा असर पड़ सकता है. अफ़्रीदी की कप्तानी में टीम ने पिछली बार इस टूर्नामेंट में खिताबी जीत हासिल की थी लेकिन इस घटनाक्रम के बाद कई और खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की संभावना व्यक्त की जा रही है. पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों ने पीसीबी के इस क़दम की आलोचना करते हुए रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है. टीम के नए कोच वकार युनुस भी इस कार्रवाई से ख़ुश नहीं हैं. ऐसे में पाकिस्तानी क्रिकेट को लेकर कयास का दौर अभी जारी रह सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 22 मार्च–28 मार्च 2010

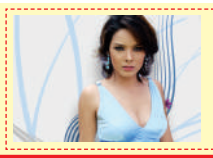

देहरादून से ताल्लुक रखने वाली लड़की असल ज़िंदगी में भी भूतों से डरती है और उसे कई बार अलग-अलग तरह की आशंकाएं होती रहती हैं.



# फिटनेस का नया राज़

दिल्ली की कुड़ी मिनिषा लांबा ने कभी नहीं चाहा था कि वह फ़िल्मों में आएं, पर मोहतरमा फ़िल्मों में आईं भी और छाईं भी. उनका जादू ऐसा चला कि श्याम बेनेगल जैसे निर्देशक ने उन्हें काम दिया है. दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से अंग्रेजी विषय में ब्रेजुएशन करने के बाद उनका रुझान मॉडलिंग की ओर गया. वह हमेशा से पढ़ाई-लिखाई में अव्वल रहने की वजह से अपना करियर एकेडमिक्स में बनाना चाहती थीं और साथ ही मनोरंजन के तौर पर मॉडलिंग भी करना चाहती थीं. एक ऑडिशन के ज़रिए उन्हें कैडबरी के ऐड में सेलेक्ट भी कर लिया गया. इसके बाद उन्हें एलजी, सोनी, हाजमोला, एयरटेल एवं सनसिल्क जैसी बेहतरीन कंपनियों के ऐड मिलने लगे. यहीं किसी फ़िल्म निर्माता की नज़र मिनिषा पर पड़ी और उन्हें फ़िल्म का ऑफर भी मिल गया. ऐसी फेरीटेल जैसी कहानी है मिनिषा की. इसके बाद उनके सितारे चमकते ही गए. बेहतरीन फ़िल्म निर्माताओं, निर्देशकों और कलाकारों के साथ काम करके मिनिषा ने अपने पांव बॉलीवुड में जमा लिए. लगभग ग्यारह फ़िल्में करने के बाद मिनिषा श्याम बेनेगल की अगली फिल्म वेल डन अब्बा में नज़र आएंगी. इस फ़िल्म में उनके किरदार की खासियत यह है कि वह एक ग्रामीण नॉन ग्लैमरस लड़की का रोल अदा कर रही हैं. किडनैप की बिकनी गर्ल को डी ग्लैम रोल में देखना वाकई अच्छा अहसास होगा. पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी बॉडी का ख्याल रखना बंद कर दिया है. ग्रामीण लड़की का किरदार निभाने के लिए उन्हें स्लिम-ट्रिम और जिम वाली टोंड बॉडी होना ज़रूरी नहीं है, पर ख़ुद को शेप में रखने के लिए उन्होंने नया तरीक़ा आजमाया है. वह शूटिंग के दौरान प्रतिदिन दो घंटे स्क्वैश खेलती हैं और फिट रहती हैं. वाह, क्या तरीक़ा आजमाया है मिनिषा ने फिट रहने का. इसे कहते हैं काम के प्रति समर्पित होना. शायद यही वजह है कि मिनिषा इतने कम वक़्त में इतने अच्छे मुक़ाम पर पहुंच गई हैं.

# आत्मविश्वास ज़रूरी है: तनुश्री दत्ता

काफी समय बाद हॉरर फिल्म रोक से वापसी करने वाली तनुश्री दत्ता अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों पर यकीन करती हैं. चौथी दुनिया ने पिछले दिनों तनुश्री से एक लंबी बातचीत की. पेश हैं प्रमुख अंश:

*काफी दिनों बाद फिल्मों में नजर आ रही हैं, इसकी वजह?*

हां, थोड़ा लंबा वक्त हो गया. वैसे इन दिनों फिल्मों की शूटिंग में ही व्यस्त थी. कुछ दिनों पहले मेरी तमिल फिल्म तिरधा विलाइतु पिल्लई रिलीज हुई है, जो तीन हफ्ते तक हाउसफुल रही है. इसके अलावा हिंदी फिल्मों रोक और अपार्टमेंट की शूटिंग में व्यस्त थी. तमिल फिल्म तिरधा विलाइतु पिल्लई के बाद रोक रिलीज हो रही है और इसके बाद अपार्टमेंट रिलीज होगी. यानी 2009 का पूरा साल शूटिंग ही करती रही.

*एक ऐक्ट्रेस के तौर पर तमिल फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड में क्या फर्क महसूस होता है?*

फर्क तो कुछ खास नहीं है. हां, भाषा की थोड़ी दिक्कत होती है. पर मैं बॉलीवुड में ज्यादा काम करना चाहूंगी. इससे पूरे देश की जनता के सामने आने का मौका मिलता है, ज्यादा ग्लैमरस है. बॉलीवुड की वजह से ही मुझे क्षेत्रीय फिल्मों में काम मिल पाया, इसलिए बॉलीवुड के प्रति शुक्रगुजारी का एहसास भी है.

*आप झारखंड के शहर जमशेदपुर से ताल्लुक रखती हैं, कैसा रहा बॉलीवुड तक पहुंचने का सफर?*

आप कहीं से भी हों, कुछ भी करने के लिए आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी है. जब आप बड़े हो जाते हैं, माता-पिता के आंचल से छूट जाते हैं, तब आपको अपने जीवन की लड़ाई के लिए खुद ही तैयार होना पड़ता है. अगर आप परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तभी सफलता मिलती है. आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तब जिंदगी से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होनी चाहिए. कहते हैं न, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती.

*किस तरह की फिल्में और रोल करना चाहती हैं?*

मैं किसी खास जॉनर की फिल्में नहीं करना चाहती, बल्कि चाहती हूं कि हर बार अलग-अलग किरदारों वाली फिल्में मिलें. मैंने अब तक के करियर में भी जहां तक संभव है, इस चाहत को बरकरार रखा है. जैसे फिल्म आशिक बनाया आपने में मेरा किरदार कॉलेज जाने वाली आम लड़की का था. फिल्म चॉकलेट में मेरी भूमिका काफी ग्लैमरस थी. कुछ फिल्मों में कॉमेडी एवं निगेटिव शेड थे. मैंने ऐसे ही अलग-अलग किरदार निभाने की कोशिश की है.

*फिल्मों के अलावा क्या करती हैं?*

मैं समाजसेवा नहीं करती हूं, पर मेरे कई शौक हैं, जैसे पढ़ना, फ़िल्में देखना और यात्राएं करना. मैंने इतनी यात्राएं की हैं कि मेरे तीन-चार पासपोर्ट फुल हो चुके हैं. फिर भी लगता है कि अभी बहुत सी अच्छी जगहें देखना बाक़ी हैं. मुझे अंतरराष्ट्रीय फिल्में बेहद पसंद हैं.

*आपके पसंदीदा कलाकार कौन हैं?*

मेरे पसंदीदा हॉलीवुड स्टार हैं जॉनी डेप और एंजेलना जॉली. बॉलीवुड सितारों में मुझे आमिर खान बेहद पसंद हैं. आज के दौर में उनके अंदर जो परफेक्शन और काम के प्रति समर्पण है, वह बहुत कम लोगों में ही देखने का मिलता है. मैं उनके साथ काम भी करना चाहती हूं.

रीतिका सोनाली
ritika@chauthiduniya.com

# उदिता गोस्वामी का डर

फ़िल्मों में अपनी छवि बदलने के लिहाज़ से उदिता गोस्वामी ने हाल में आई हॉरर फ़िल्म रोक में एक आम मैनेजमेंट स्टूडेंट का किरदार निभाया है. इस फ़िल्म में उनके साथ तनुश्री दत्ता भी हैं. अपने इस रोल को लेकर वह उत्साहित हैं. साथ ही इसे अंजाम देने के बाद उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अलग-अलग जॉनर की फ़िल्में करने को मिलेंगी. देहरादून से ताल्लुक रखने वाली लड़की असल ज़िंदगी में भी भूतों से डरती है और उसे कई बार अलग-अलग तरह की आशंकाएं होती रहती हैं. इसके लिए वह समझती है कि यह शायद उसके पिछले जन्म का कोई प्रभाव है. यही नहीं, उदिता को अपनी हॉरर फ़िल्म रोक की स्क्रिप्ट पढ़ते वक़्त भी डर लगा था. यहां तक कि शूटिंग के दौरान वह कई सीन फ़िल्माते वक़्त डर गई थीं. उन्हें अपने घर में, जो कि एक बिल्डिंग के तेरहवीं मंजिल पर स्थित है, अकेले जाते हुए डर लगता है. वह कभी भी, कहीं भी अकेले नहीं जाती हैं. उनके साथ हमेशा परिवार या दोस्तों में से कोई न कोई ज़रूर होता है. उनके दोस्त उन्हें किसी तांत्रिक के पास जाने की सलाह देते हैं, जिससे जो भी राज उनके पिछले जन्म का है, वह सामने आ जाए.

## फिल्म रिव्यू

### अतिथि तुम कब जाओगे

कोंकणा सेन और अजय देवगन स्टारर फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे अश्विनी धीर द्वारा निर्देशित है. टीवी धारावाहिक ऑफिस-ऑफिस का निर्देशन कर चुके अश्विनी ने इस फिल्म के जरिए भी अपने हुनर का लोहा मनवाया है. महान लेखक शरद जोशी द्वारा लिखे गए एक लेख तुम कब जाओगे अतिथि से प्रेरणा लेकर अश्विनी ने इस फिल्म की पटकथा तैयार की और उसे फिल्माया. बिना किसी खास चमक-धमक, तड़क-भड़क और ग्लैमर के काफी समय के बाद कोई पारिवारिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतारी गई है. हमारे देश में प्रचलित कहावत अतिथि देवो भव: की तर्ज पर अतिथि तुम कब जाओगे एक कॉमेडी फिल्म है. यह मुंबई में रहने वाले एक आम एकल परिवार की कहानी है, जिसमें कोंकणा सेन यानी मुनमुन एक इंटीरियर डिजायनर है. परिवार का मुखिया एवं उसका पति अजय देवगन (पुनीत) स्क्रिप्ट राइटर और उनके परिवार को पूरा करता छह साल का बच्चा आयुष. उनके घर एक ग्रामीण अतिथि परेश रावल (लंबोदर चाचा) आ जाते हैं और परिवार के सारे नियम-कानून, अनुशासन को ध्वस्त कर देते हैं. हद तो तब होती है, जब वह जाने का नाम ही नहीं लेते हैं और पुनीत-मुनमुन उन्हें चले जाने का संकेत देते-देते परेशान हो जाते हैं. मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां हर ओर दिखावे का लबादा चढ़ा रहता है, चाचा जी के सरल व्यवहार की वजह से उन्हें कई तरह की कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बावजूद इसके, पुनीत चाचा जी के साथ रूखा व्यवहार नहीं करता. हालांकि हर पत्नी की तरह मुनमुन की नाराजगी अपने पति पर ही व्यक्त होती है. कोंकणा ने छह वर्ष के बच्चे की मां, एक पत्नी, एक बहू और पेशेवर महिला का आधुनिक किरदार बखूबी निभाया है. अजय देवगन पुनीत के किरदार में खूब जमे हैं, सिवाय फिल्म के आखिरी सीन में, जहां उन्हें भावनात्मक रोल प्ले करना था. एक्शन, कॉमेडी और गंभीर किरदार में अपना नाम पूर्णत: स्थापित करने वाले अजय भावनात्मक किरदार में रंग नहीं जमा पाए. ऐसा लगता है कि जिस किरदार को हम लगातार दो घंटे से देखते आ रहे हैं, वह अचानक बदल जाता है. इससे पटकथा का तारतम्य टूटता है, साथ ही कंफ्यूजन पैदा हो जाता है. पूरी फिल्म परेश रावल के किरदार लंबोदर चाचा के इर्द-गिर्द घूमती है. अपने सशक्त अभिनय से इस किरदार का जादू उन्होंने खूब चलाया है. पूरी फिल्म में कोंकणा, अजय और परेश रावल पर फिल्माए गए दृश्य दर्शकों को हंसाने में सौ प्रतिशत कामयाब होते हैं. प्रस्तुतिकरण का श्रेय सिर्फ कलाकारों को ही नहीं, संवाद लेखक अश्विनी धीर को भी जाता है. फिल्म का संगीत देने में प्रीतम और अमित मिश्रा ने जो रेट्रो स्टाइल पर प्रयोग किया है, वह क़ाबिल-ए-तारीफ़ है. 60-70 के दौर की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों जैसा संगीत, गीत के बोल और प्रस्तुतिकरण खास है. और, फिल्म की कहानी के साथ फिट भी. इस संगीत के साथ फिल्माए गए दृश्य रेट्रो लुक में भी साधारण होकर खास लगते हैं. इसके अलावा आजकल शहरों में पूजापाठ में इस्तेमाल होने वाले संगीत पर विशेष प्रस्तुति के साथ व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है.

## फिल्म प्रिव्यू

### लव सेक्स और धोखा

ओए लकी लकी ओए और खोसला का घोसला जैसी साफ सुथरी और बेहतरीन फिल्में बना चुके निर्देशक दिबाकर बनर्जी इस बार काफी बोल्ड सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं. फिल्म लव सेक्स और धोखा उनकी तीसरी फिल्म है. इस फिल्म के जरिए दिबाकर ने आज की नई पीढी में हो रहे सांस्कृतिक बदलाव और गिरती मानसिकता के पेश करने की कोशिश की है. फिल्म में कहानी केंद्र में कुछ जोडे हैं जो आज कल की नई जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं. सबके अपने अपने सपने और लक्ष्य हैं. इन्हें हासिल करने के लिए किस तरह के समझौते होते हैं यह सब दिखाती है यह फिल्म. फिल्म में एक न्यूड सीन को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है. देखना होगा कि सेंसर इस सीन को पास करता है या नहीं. लव सेक्स और धोखा टीवी जगत की जानी मानी हस्ती एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही है. पिछले दिनों सुनने में आया था कि एकता कपूर फिल्म के निर्देशक दिबाकर बनर्जी के काम से उतना खुश नहीं हैं. उनके मुताबिक दिबाकर ने उन्हें जो कहानी पहली सुनाई थी वह अब पूरी तरह से बदल चुकी है. उनका कहना है कि फिल्म को अश्लील लुक दे दिया गया है इससे दर्शक परिवार सहित देखने में सकुचाएगा. दरअसल फिल्म के प्रोमो में कैमरे को दिखाते हुए कहते हैं कि कैमरे का अविष्कार जब हुआ था तब इसका सुदपयोग होता था पर आज इस कैमरे ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है. फिल्म में ज्यादातर कलाकार नए हैं. फिल्म का स्क्रीन प्ले दिबाकर का है जबकि कहानी उर्मी जुवेकर ने लिखी है. फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है. आज के युग की टेक्नो जेनरेशन को यह फिल्म खासी पसंद आएगी.

# चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 22 मार्च-28 मार्च 2010

www.chauthiduniya.com


# तार-तार होता कांग्रेस का मिशन बिहार

जगदीश टाइटलर के साथ रंजीता रंजन

सरोज सिंह

बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार ज़ोर पकड़ रही हैं. जहां हर पार्टी चुनाव से पहले अपने संगठन और नेताओं को तैयार करने में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस अपनी आंतरिक लड़ाईयों में ही व्यस्त है. पार्टी में गुटबाज़ी चरम पर है जो अक्सर आपसी जूतमपैजार की शक्ल अख्तियार कर लेती है. आलम यह है कि प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा और प्रदेश प्रभारी जगदीश टाइटलर भी एक दूसरे की टांगखिंचाई में ही लगे हैं. डर यह है कि कहीं राहुल गांधी के मिशन बिहार का सपना शुरू होने से पहले ही टूट कर बिखर न जाए.

बिहार में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए पिछले दिनों कांग्रेस ने गांव-गांव, पांव -पांव का नारा बुलंद किया था, पर हाल की कुछ शर्मसार कर देने वाली घटनाओं से लगता है कि प्रदेश में कांग्रेसियों के पांव कम और हाथ कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं. समारोह व सभाओं में हंगामा, धक्का-मुक्की व मारा-मारी की वजह चाहे जो हो, पर इससे निकलने वाला संदेश साफ़ है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर की गुटबाज़ी व नेताओं की एक-दूसरे को नीचा दिखाने की करतूत से राहुल गांधी के मिशन बिहार का सपना तार-तार हो रहा है. यह प्रदेश नेताओं की अति महत्वाकांक्षा ही है जिसके चलते नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ एक मज़बूत विकल्प के तौर पर कांग्रेस का चेहरा उभर नहीं पा रहा है. कांग्रेस चार क़दम बढ़ती है पर अगले ही दिन तीन क़दम वापस लौट जा रही है. प्रदेश प्रभारी जगदीश टाइटलर लाख छुपाएं पर यह बात स्पष्ट है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वह पूरी पार्टी को एकजुट नहीं कर पाए हैं. पार्टी विधायक कुछ सोचते हैं तो संगठन कुछ और. दोनों एक-दूसरे से मुक़ाबला करने की भाषा सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं. यह सभी मान रहे हैं कि इस बार पार्टी के लिए बेहतर मौक़ा और माहौल है, पर हम बड़े कि तुम में सारा खेल ख़राब हो रहा है.

प्रदेश कांग्रेस में गुटबाज़ी कोई नई कहानी नहीं है पर अनिल शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद से इस कहानी की पटकथा में कई नए किरदार जुट गए. लालू प्रसाद से अलग होने के बाद से प्रदेश की जनता में यह उम्मीद जगी कि कांग्रेस अब अपना पुराना गौरव फिर से हासिल करने में जुटेगी. इसका आग़ाज़ भी अच्छा हुआ, लोगों के समर्थन से कांग्रेस के वोट बैंक में इज़ाफ़ा हुआ और ऐसा लगा कि संगठन को मज़बूत कर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में एक मज़बूत विकल्प बनेगी. लेकिन नई कमिटी के गठन के बाद से जो विवाद शुरू हुआ, वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है. ताजा विवाद रंजीता रंजन, पप्पू यादव व साधु यादव को लेकर उभरा है. राहुल के युवा भारत के सपनों को साकार करने के मक़सद से पूर्व सांसद व पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने अपने से जुड़े युवा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करने के लिए मिलन समारोह का आयोजन किया. बताया जाता है कि इस मिलन समारोह के लिए जगदीश टाइटलर से भी इजाज़त ले ली गई थी. लेकिन इस समारोह में प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा शामिल नहीं हुए. अनिल शर्मा ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में नहीं बताया गया था. उन्होंने हैरानी जताई कि जो कांग्रेसी सोनिया गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वे पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा कैसे लगा सकते हैं. सोनिया गांधी व पप्पू यादव की एक साथ तस्वीर वाले पोस्टरों पर भी उन्होंने नाराज़गी जताई. अनिल शर्मा रंजीता रंजन से भी ख़फ़ा दिखे. उन्होंने कहा कि रंजीता रंजन का यह बयान बेहद आपत्तिजनक है कि सोनिया गांधी व राहुल गांधी बिहार में पार्टी को नहीं जिता सकते. हालांकि रंजीत रंजन ने इस तरह के बयान देने का खंडन करते हुए कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन शर्मा के इस बयान से अगले दिन होने वाले प्रतिनिधि सम्मेलन की पटकथा तैयार हो गई. एसके मेमोरियल हॉल में प्रतिनिधि सम्मेलन में पार्टी अनुशासन की जमकर धज्जियां उड़ीं. मंच पर हंगामा, धक्का मुक्की व मारा-मारी की शुरुआत रंजीता रंजन के भाषण के साथ ही हो गई. भाषण के दौरान रंजीता रंजन ने अनिल शर्मा से सवाल पूछा कि क्यों चालीस साल से पार्टी का झोला ढोने वाले डा अशोक कुमार आज यहां न आकर कहीं और बैठक कर रहे हैं. पप्पू यादव पर की गई टिप्पणी से ख़फ़ा रंजीता रंजन ने दूसरा सवाल यह दागा कि शर्मा जी यह बताएं कि उनके जम्बो पीसीसी में कितने ऐसे लोग हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा नहीं है. रंजीता रंजन के इतना कहते ही एसके मेमोरियल हॉल हंगामे में डूब गया. रंजीत रंजन को इस हंगामे के कारण समारोह से बीच में ही उठ कर जाना पड़ा. एसके मेमोरियल में जब यह सारा कुछ चल ही रहा था, उसी समय डा. अशोक कुमार के घर पर कांग्रेस के विधायकों व जिला प्रतिनिधियों ने अनिल शर्मा को तुरंत हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया. रंजीता रंजन ने अगले दिन दिल्ली जाकर तमाम घटनाओं की जानकारी आलाकमान को दी। पप्पू यादव ने भी कहा कि वह गांव-गांव घूमकर कांग्रेस को मज़बूत करने में लगे हैं ताकि सोनिया गांधी व राहुल गांधी का सपना साकार हो सके. अपने आपराधिक छवि पर पप्पू यादव ने तो कुछ नहीं कहा पर उनके समर्थक यह ज़रूर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जब चुनाव आता है, तभी पप्पू यादव याद आते हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में कई ऐसे प्रत्याशी थे, जिन्होंने पप्पू यादव को अपने क्षेत्र में भेजने का आग्रह पार्टी कार्यालय में किया. पप्पू उन इलाक़ों में गए भी. समर्थकों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि उस समय कांग्रेस पप्पू यादव की आपराधिक छवि क्यों नहीं देख पाई.

आरा में कांग्रेस सभा में हंगामा करते कार्यकर्ता

अनिल शर्मा से ख़फा चल रहे साधु यादव ने रंजीता रंजन के साथ हुई घटना को हवा देते हुए प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया. साधु ने कहा कि इसी तरह चलता रहा तो सोनिया गांधी व राहुल गांधी के सपनों को बिहार में साकार करना मुश्किल हो जाएगा. इसके बाद बारी अनिल शर्मा की थी. जैसे ही साधु यादव ने महिला बिल में कोटा के भीतर कोटा की बात की, आनन-फानन में उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया. लेकिन शाम होते-होते अनिल शर्मा को जगदीश टाइटलर ने ही झटका दे दिया. टाइटलर ने साफ़ किया कि साधु को निलंबित किया ही नहीं गया है. पार्टी लाइन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ है, कुछ संवादहीनता थी जिसे साधु ने दूर कर दिया. लेकिन पूरे दिन चैनलों में आए साधु यादव के कोटा के भीतर कोटे के बयान के बावजूद संवादहीनता की स्थिति कैसे बनी, इसका कोई जवाब टाइटलर साहब के पास नहीं है.

दरअसल पूरा मामला अनिल शर्मा की राजनीतिक हैसियत व उनके कद को लेकर है. कांग्रेस के कई नेता बार-बार आलाकमान को यह समझाने में लगे हैं कि चुनावी साल में बिहार कांग्रेस को एक बड़ा राजनैतिक कद वाला चेहरा चाहिए. नीतीश के विकल्प के रूप में बेदाग छवि व सभी को साथ लेकर चलने वाले नेता की अगुआई में ही मिशन बिहार का सपना पूरा हो सकता है. अभी हालत यह है कि कोई बड़ा नेता अनिल शर्मा की बात मानने के लिए तैयार नहीं है. सभी सीधे दिल्ली बात करने की हैसियत में हैं. रंजीत रंजन व साधु यादव प्रकरण में यह बात सार्वजनिक तौर पर साबित भी हो गई. सभा-समारोह में अनुशासन की धज्जियां उड़ रहीं हैं और किसी का नियंत्रण इस पर नहीं है. आरा की सभा में अनिल शर्मा व जगदीश टाइटलर की मौजूदगी में कांग्रेस के दो गुट भिड़ गए और जमकर कुर्सियां चलीं. पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ बयान देने वाले नेता को दिन में अनिल शर्मा निलंबित करते हैं और शाम में जगदीश टाइटलर उन्हें वापस ले आते हैं. इन घटनाओं से जनता का कांग्रेस के प्रति बढ़ रहा भरोसा टूटने लगा है. लोगों का सवाल भी साफ़ है कि आपस में ही लड़ रहे कांग्रेसी नेता उनके हक़ व सम्मान की लड़ाई कैसे लड़ेंगे. नीतीश, लालू व रामविलास की कड़ी चुनौती का सामना इस अंदाज़ में कांग्रेस कैसे कर पाएगी. सोनिया गांधी व राहुल गांधी अगली बार जब बिहार के दौरे पर होंगे तो उनके सामने भी यह सवाल होंगे और मिशन बिहार को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो उन्हें इन सवालों का जवाब देना ही होगा.


feedback@chauthiduniya.com

अशोक कुमार के निवास पर कांग्रेस की बैठक में मौजूद नेतागण

रेलवे मनोरंजन संस्थान का संचालन 11 सदस्यीय संचालन समिति द्वारा होता है जिसके पेट्रॉन महाप्रबंधक पूमरे, अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक एवं सचिव रेलवे के अधिकारी हैं.



कई पुश्तों से झरिया की माटी से लगाव अब याद भर रह जाएगा. झरिया के विस्थापन की तलवार जिन लोगों पर लटकी है वे कई तरह के सवाल पूछते हैं.



# ममता दीदी, ज़रा नज़र इधर भी डालें






विकास कुमार

देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाने वाली भारतीय रेल में कल्याणकारी योजना के तहत कई अर्द्धसरकारी संस्थाएं चलाई जाती हैं जिनमें रेलवे मनोरंजन संस्थान, कैंटीन, को-ऑपरेटिव, सिलाई सेंटर, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र आदि हैं. इन संस्थानों में हज़ारों श्रमिक कार्यरत हैं लेकिन विडंबना है कि रेलवे के इन उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों को जो मासिक वेतन दिया जा रहा है उसमें श्रम अधिनियम एवं रेलवे बोर्ड के नियमों की खुल्लम-खुल्ला अवहेलना की जा रही है. इन संस्थानों में वर्षों से कार्यरत श्रमिकों से मात्र 600 से 900 रुपये मासिक वेतन पर कार्य लिया जा रहा है परिणामस्वरूप ऐसे श्रमिक रेलवे के बंधुआ मज़दूर बनकर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं. ऐसे श्रमिकों के बच्चों को अर्थाभाव में विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता है लेकिन विभागीय अधिकारियों को यह सब देखने की ज़रूरत ही कहां है?

पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत समस्तीपुर मंडल के अधीन तथा मंडल मुख्यालय समस्तीपुर स्थित रेलवे मनोरंजन संस्थान (बाज़ार एवं मनोरंजन संस्थान) माधुरी चौक सहित दरभंगा, नरकटियागंज एवं सहरसा में ऐसी कई मनोरंजन संस्थान हैं जहां के श्रमिकों को 25-30 वर्ष से कार्य कराया जा रहा है. इन श्रमिकों को मासिक वेतन के नाम पर 20-30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है जिससे ऐसे श्रमिकों के परिवार एवं बच्चे भूखे-नंगे रहने को विवश हैं. इन श्रमिकों के वेतन निर्धारण हेतु रेलवे बोर्ड के मास्टर परिपत्र के मुताबिक़ बाज़ार दर को मापदण्ड मानते हुए वेतन का निर्धारण कराना है. लेकिन इन नियमों के विपरीत विभागीय स्तर पर न तो वर्षों से कार्यरत श्रमिकों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है और न ही स्थाई नियुक्ति की जा रही है. रेलवे बोर्ड के नियमों के मुताबिक़ सामान्य श्रमिक जिन्होंने 500 दिन कार्य किया है और अनुसूचित जनजाति के श्रमिक जिन्होंने 300 दिन कार्य किया है उनका स्क्रीनिंग कर रेल सेवा में समायोजन का प्रावधान है. बावजूद इसके श्रमिकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है.

इस संबंध में समस्तीपुर स्थित रेलवे मनोरंजन संस्थान के श्रमिकों का कहना है कि रेलवे को इस मनोरंजन संस्थान से लाखों की वार्षिक आमद होती है लेकिन संस्थान में कार्यरत मज़दूरों को श्रम अधिनियम एवं बाज़ार दर पर मज़दूरी नहीं मिल पाती है. मालूम हो कि मंडल मुख्यालय समस्तीपुर स्थित मनोरंजन संस्थान में कार्यरत कर्मी मुन्ना राय, रामकुमार राम, हरिचंद्र झा, आदित्य नारायण पोद्दार एवं विमल यादव पिछले 25-30 वर्षों से कार्यरत हैं. इन्होंने अनेकानेक बार पूर्व के महाप्रबंधक, रेलवे बोर्ड एवं मंडल रेल प्रबंधक से न्याय की गुहार लगाई लेकिन आज तक स्थानीय रेलवे अधिकारियों की सुस्ती के कारण रेलवे बोर्ड के निर्देश का अनुपालन नहीं हो रहा है और मात्र 20-30 रुपये की कमाई पर श्रमिकों के परिजन भुखमरी के शिकार हो रहे हैं. श्रमिकों की आर्थिक बदहाली के हालात यह रहे हैं कि विगत 25 जून 2008 को वहां के चौकीदार रामभरोसे महतो ने आर्थिक तंगी व भुखमरी की सूचना विभागीय अधिकारियों को देते हुए ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली थी. मृत चौकीदार की विधवा किरण देवी अपने दो बच्चों की परवरिश एवं संस्थान में नियुक्ति की ख़ातिर मंडल रेल प्रबंधक एवं सीनियर डीपीओ के कार्यालय का चक्कर काट रही हैं लेकिन उसकी नियुक्ति की फ़ाइल जस की तस कार्यवाई के लिए अटकी पड़ी है. किरण देवी अपने दो बच्चों जितेंद्र (11) एवं रानी (10) के साथ रेलवे मनोरंजन संस्थान के बाहर फुटपाथ पर कभी फल-सब्ज़ी तो कभी चाय का स्टॉल लगाकर किसी प्रकार गुज़र बसर कर रही है.

विदित हो कि रेलवे मनोरंजन संस्थान का संचालन 11 सदस्यीय संचालन समिति द्वारा होता है जिसके पेट्रॉन महाप्रबंधक पूमरे, अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक एवं सचिव रेलवे के अधिकारी हैं. एक समय था कि इस मनोरंजन संस्थान के 2000 से ऊपर रेलकर्मी सदस्य हुआ करते थे जबकि आज उपेक्षा के कारण 400 से 500 सदस्य बमुश्किल रह गए हैं. इस रेलवे मनोरंजन संस्थान से जुड़े फुटबॉल, टेनिस, कैरमबोर्ड, शतरंज आदि खेल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सदस्य हुआ करते थे और यह मनोरंजन संस्थान समस्तीपुर की शान कहलाती थी. आज इस संस्थान के भव्य लाइब्रेरी की पुरानी पुस्तकें धूल फांक रही हैं. श्रमिकों का कहना है कि मनोरंजन संस्थान के हाल बुकिंग, रूम बुकिंग, कुर्सी एवं ज़मीन बुकिंग आदि मदों से लाखों की आमदनी होती है तथा रेलवे द्वारा इसके रख-रखाव हेतु अतिरिक्त अनुदान मिलता है लेकिन फिर भी संस्थान में कार्यरत श्रमिकों एवं उसके परिजनों को दो जून की रोटी तक नसीब नहीं हो पाती. पता नहीं संस्थान की आय कहां गुम हो जाती है? नियमत: इनके ख़र्च का भी विभागीय ऑडिट होता है लेकिन संस्थान के कर्मियों का कहना है कि सब कुछ काग़ज़ पर ही होता है क्योंकि ख़र्च के संबंध में श्रमिकों से पूछताछ करने कोई भी अधिकारी आज तक नहीं आया. मंडल मुख्यालय के अंतर्गत 5-5 होम्योपैथिक स्वास्थ्य उप केंद्र चलाए जाते हैं उनके कर्मचारी भी बाज़ार दर एवं रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार वेतन के मोहताज बने हुए हैं.

विदित हो कि मंडल मुख्यालय स्थित लोको शेड एवं कारख़ाना स्टोर के अंतर्गत कैंटीन चलाए जाते हैं. इनमें जूनियर श्रमिकों को तो स्थाई नियुक्ति दी गई पर अर्थाभाव के चलते सीनियर श्रमिक आज भी स्थाई नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं. रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार इन श्रमिकों का समायोजन ग्रुप डी के रेलकर्मी की तरह स्थाई नियुक्ति करने के मामले में मंडल रेल प्रबंधक कुंदन चौधरी कुछ सकारात्मक होते भी हैं तो उनके अधीनस्थ सीनियर डीपीओ के समक्ष श्रमिकों के स्थाई नियुक्ति का मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है.

पिछले 22 फरवरी को श्रमिकों ने फिर एक बार रेलवे बोर्ड के निर्देश का अनुपालन करते हुए बाज़ार पर वेतन भुगतान एवं स्थाई नियुक्ति करने की मांग दुहराई है. रेल मंत्री ममता बनर्जी एक ओर जहां रेलवे के निजीकरण के ख़िलाफ़ हैं ऐसे में उनके कार्यकाल में भी रेलवे के उपक्रमों में कार्यरत हज़ारों श्रमिकों को बंधुआ मज़दूरों की ज़िंदगी से मुक्ति मिल पाती है या नहीं, यही देखना है.

feedback@chauthiduniya.com



# धनौती मठ की ज़मीन पर दबंगों का क़ब्ज़ा

लगभग पांच सौ साल पहले संत कबीर के चार शिष्यों में प्रमुख रहे भगवान गोस्वामी द्वारा स्थापित धनौती मठ की सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर वर्षों से दबंगों का क़ब्ज़ा है. मठ की अकूत संपत्ति को लेकर हुई ख़ून की होली से भी इस मठ की ख्याति को दाग लगा है. सीवान मुख्यालय से करीब आठ किमी दूर पश्चिम-उत्तर दिशा में स्थित इस मठ के अधीन क़रीब 550 बीघा ज़मीन थी. किन्तु आज लगभग पौने दो सौ बीघा ही शेष है. यह ज़मीन, आसपास के गांवों जैसे धनौती, भरथुई, मोजाहिदपुर और सरसा में है. बहुत पहले राज्य सरकार ने सारी ज़मीन पर सिलिंग एक्ट लागू कर इस मठ को सिर्फ़ एक यूनिट मानकर 15 एकड़ सिंचित भूमि ही मठ को रखने का प्रावधान निर्धारित किया. बाकी ज़मीन की बिक्री पर रोक लगा दी गई, लेकिन बिहार में सीलिंग एक्ट सफल नहीं होने के कारण यह ज्यादा प्रभावी नहीं हो सका. अगर राज्य में यह एक्ट प्रभावी हुआ होता और इसके द्वारा अधिग्रहीत मठ की ज़मीन ग़रीबों एवं भूमिहीनों के बीच वितरित कर दी गई होती तो शायद यह मठ हत्याओं-नरसंहारों का अंतहीन दास्तान नहीं बनता और न ही अपराधियों की शरणस्थली! क्योंकि इस धर्मस्थली को अपराधियों की शरणस्थली बनने की मुख्य वजह इसकी अकूत संपत्ति एवं ज़मीन मानी जाती रही है.

धनौती मठ का प्रारंभिक विवाद काल 1970-71 से माना जाता है. इस दौर के धनौती मठाधीश रामधारी गोस्वामी ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपने शिष्य नरसिंह गोंसाई को निबंधित मठाधीश बनाया, लेकिन तीन-चार महीने के पश्चात अपने स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार देखकर रामधारी गोस्वामी ने उक्त अनुबंधित इकरारनामे को रद्द करा दिया. तब नरसिंह गोसाई ने महंती की दावेदारी का एक मुकदमा न्यायालय में दायर किया. जिसमें श्री गोंसाई ने रामधारी गोस्वामी, भुनेश्वर गोस्वामी, श्रीराम गोस्वामी और देवनंदन गोस्वामी को पक्ष बनाया. इसी दौरान नरसिंह गोस्वामी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके कथित शिष्य गुरु प्रसाद उर्फ गरभू गोस्वामी ने मुख्तारनामा के तहत उनका वारिस बनकर न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया. न्यायालय ने जांच के बाद 1989 में इस दावेदारी के मुख्तारनामा को रद्द कर दिया गया. तब गरभू गोस्वामी ने पटना उच्च न्यायालय में इस रद्द किए गए आदेश के ख़िलाफ़ एक अपील की, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने भी उक्त याचिका को रद्द कर दिया. तत्पश्चात उन्होंने उच्चतम न्यायालय में भी इस आदेश के विरूद्ध अपील की, लेकिन वहां भी यह मामला ख़ारिज़ कर दिया गया.



धनौती मठ का पुराना मुख्य द्वार और मठ का आंगन

इसी दौरान भुनेश्वर गोस्वामी और बालछड़ी गोस्वामी की हत्या हो गई. इस मठ में हत्याकांड की यह पहली घटना थी. मुफस्सिल थाना में इस हत्याकांड के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज़ की गई. जिसके फर्दबयान में गरभू गोस्वामी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया. उसके बाद हत्या के शिकार भुनेश्वर गोस्वामी के एक वफ़ादार एवं वहां के मुखिया ललन सिंह की भी हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड का भी नामजद अभियुक्त गरभू को ही बनाया गया. उसके बाद मृतक ललन सिंह के छोटे भाई डॉ. रामनाथ सिंह की भी हत्या कर दी गई. 1999 में हुई इस हत्या के नामजद अभियुक्त गरभू गोस्वामी ही बनाए गए. इन सभी हत्याकांडों का मामला अभी न्यायालय में लंबित है. इसके अलावा 26 जुलाई 2000 को शिव कुमार गोस्वामी के गाड़ी चालक इदरीश मियां की हत्या कर दी गई. इसमें भी गरभू गोस्वामी को अभियुक्त बनाया गया. इस हत्याकांड की प्राथमिकी मुफस्सिल थाने में दर्ज़ है.

इस मठ के महंत आचार्य शत्रुघ्न गोस्वामी ने बताया कि धनौती गांव एवं यहां के तत्कालीन पोस्टमैन रामेश्वर कलवार के हत्याकांड में गरभू गोस्वामी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा दी, जो सीवान मंडलकारा में बंद हैं. उन्होंने बताया कि गरभू गोस्वामी 1970 में धनौती मठ में आए. इसके पूर्व कुछ साल तक वे इस जिले के पचरूखी थानांतर्गत सदिकपुर कबीर मठ में रहे, जो वहां के तत्कालीन महंत बच्चा गोस्वामी की लंगोटी स्वयं पहनकर यह प्रचार करने लगे कि महंत जी ने हमें अपनी लंगोटी दे दी है. दरअसल इस शातिर की मठ में पैठ बनाने की पहली कोशिश थी. इसके बाद वे धनौती मठ में आकर रहने लगे. देखते ही देखते इस मठ में हत्याओं का दौर शुरू हो गया. उन्होंने यह भी बताया कि समस्तीपुर ज़िलांतर्गत रोसड़ा के चोरवा डूमरा गांव के मूल निवासी गरभू बताए जाते हैं, जिनके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में दो दर्ज़न से अधिक हत्याकांड और आपराधिक मामले दर्ज़ हैं. हालांकि इनमें कई मामले ऐसे हैं , जो साक्ष्याभाव के कारण गरभू बरी हो गए हैं.



व्यवस्थापक महंत देवजी गोस्वामी

धनौती मठ के व्यवस्थापक महंत देवजी गोस्वामी का कहना है कि अपने स्वार्थ के लिए गरभू गोस्वामी ने इस मठ के अधीन पचरूखी प्रखंड के नरहट गांव स्थित 25 बीघा ज़मीन दबंगों के नाम निबंधित कर दी गई, जबकि इस मठ के अधीनस्थ क्षेत्र के सादिकपुर गांव स्थित 30 एकड़ ज़मीन और एमएच नगर थानांतर्गत लहेजी गांव स्थित लगभग 10 एकड़ के आम बागीचे को और 50 एकड़ ज़मीन सालों से दबंगों ने क़ब्ज़ा कर लिया है. इसके अलावा धनौती और आसपास के गांवों में मठ की 26 बीघा से अधिक ज़मीनों की अवैध मिट्टी कटाई दबंग ईंट-भट्ठा चिमनी वालों ने कर लिया है, जो खेत अब गड्ढ़ों में तब्दील हो गए हैं. वहीं सीवान सदर प्रखंडान्तर्गत बांसोपाली गांव स्थित लगभग 12 बीघा ज़मीन पर दबंगों का क़ब्ज़ा बताया जाता है. इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न प्रांतों के अलावा इस आचार्य मठ के अधीन मॉरीशस में भी तीन कबीर पंथी मठ हैं, लेकिन विडंबना यह है कि धनौती और आसपास के गांवों में स्थित इस मठ के खेत-बगीचों में लगे हरे पेड़ों की कटाई भी कथित दबंग व्यक्तियों द्वारा धड़ल्ले से की जा रही है, जिसके सुरक्षार्थ महंत श्री गोस्वामी ने ज़िलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को आवेदन देकर गुहार लगाई थी, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कारगर कार्रवाई नहीं हो पाई है.

धनंजय मिश्र
feedback@chauthiduniya.com

# आग पर झरिया



कोयले की राजधानी झरिया की आग को बुझाने में देश ही नहीं विदेशी एजेंसियां भी हाथ आजमाती रही हैं, लेकिन अरबों रुपए ख़र्च करने के बाद भी आग दहकती ही जा रही है. अब हालत यह है कि जहां-तहां बेक़ाबू आग धरती का सीना चीरकर बाहर भी झांकने लगती है. उसके बाद अचानक धरती नीचे धंस जाती है. ऐसे में जानमाल कुछ भी सुरक्षित नहीं है. ईमानदारी की कोशिश हुई या नहीं यह बहस का विषय है. वैसे जो हालात हैं, काफ़ी गंभीर हैं. पहली बार 1916 में भूमिगत आग झरिया कोयलांचल के भौंरा में दिखी. विशेषज्ञों की मानें तो तबाही के लिए ज़िम्मेदार चिंगारी संभवत: और पहले सुलगी होगी. लगभग 94 वर्ष से कार्बन मोनोआक्साईड की दम घोंटू गंध गोफ और भू-धसान की पीड़ा तथा घरों की फटी दीवारों के बीच भय के साये में ज़िंदगी गुज़ारते लोग. वृद्ध चल बसे, बच्चे अब बूढ़े हो गए हैं और नई पीढ़ी आग की लपेटों में झुलसने को विवश है. लोग कहते हैं कि अब पलायन की बेला है. पांच लाख लोग विस्थापन के कगार पर हैं. कई पुश्तों से झरिया की माटी से लगाव अब याद भर रह जाएगा. झरिया के विस्थापन की तलवार जिन लोगों पर लटकी है वे कई तरह के सवाल पूछते हैं. वैसे दबी ज़ुबान में लोग इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि देश दुनिया के कई हिस्से में इस तरह की आग लगती है और इस पर क़ाबू भी पा लिया जाता है. यदि शुरू में ही ईमानदारी से प्रयास किया जाता तो शायद इतनी ख़तरनाक हालत नहीं होती.

राष्ट्रीयकरण के समय 17.32 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में आग थी. फायर फाइटिंग कार्यक्रम एवं ओसीपी के विस्तार से अब 8.9 किलो वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में आग है. भूमिगत आग का दायरा घटने के बावजूद आग की लपेट में बीसीसीएल की 41 खदानें हैं. ज़्यादातर में काम बंद है पर कई रिहायसी इलाक़े के नीचे भी आग है.

भारत सरकार ने 1996 में फायर कंट्रोल के लिए प्रयास किया था और झरिया एवं रानीगंज अग्नि प्रभावित क्षेत्र के हाई पावर समिति का गठन भी किया गया था. कोयला सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति में डीजीएमएस, चैयरमैन सी.आई.एल., सी.एम.डी., बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., ई.सी.एल. एवं सी.एम.पी.डी.आई. को सदस्य बनाया गया था. समिति ने रिपोर्ट बनाने की ज़िम्मेदारी सीएमपीडीआई को सौंपी. इस रिपोर्ट पर कोयला मंत्रालय की ओर से फायर फाइटिंग के लिए दो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए. जिसमें डाटा संग्रह एवं भू-धसान क्षेत्रों की पहचान के लिए 25.84 लाख एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए 48.30 लाख रुपये स्वीकृत किए गए. विश्व बैंक ने झरिया माइन फायर कंट्रोल टेकनिकल असिस्टेंट प्रोजेक्ट नाम से 1993 में एमजीएआई, एमइटी, सीएचटीएम जो ज्वाइंट वेंचर अमेरिका एवं कनाडा की कंपनी है. इन दोनों कंपनियों ने भी आग पर क़ाबू पाने का प्रयास किया. भारी राशि ख़र्चने के बावजूद परिणाम कुछ भी नहीं निकला. 1998 में पहली बार पुर्नवास की बात हुई जिसमें झरिया मास्टर प्लान के लिए 7028.40 करोड़ रूपए स्वीकृत किये गये . इनमें पुर्नवास पर्यावरण की सुरक्षा तथा फायर फाइटिंग के लिए भी राशि शामिल है. बीसीसीएल तथा ग़ैर बीसीसीएल के अलावा अनेक अनधिकृत रुप से बसे लोगों का पुर्नवास भी शामिल है. इसके तहत चार नये टाउनशिप की भी स्वीकृति है. इसकी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की एजेंसी झरिया रिहैबिलिटेशन एवं डेवलपमेंट ऑथिरिटी को दी गई है. बीसीसीएल कर्मी के पुर्नवास की ज़िम्मेदारी कंपनी करेगी. अब देखना है कि सरकार द्वारा जारी इतने बड़े फंड में सरकारी अधिकारी बंदरबांट ज़्यादा करते हैं या आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचने देते हैं.



राजीव रंजन
feedback@chauthiduniya.com

# सिर्फ़ आबादी नहीं आधी शक्ति हैं हम



मनोज कुमार राव

महिला बिल पास होने पर चंपारण की महिलाओं में जगा आत्मविश्वास देखते ही बनता है. मैंने जब एक घंटे पहले की एक ग़रीब प्रसूति को इंटरमीडिएट की परीक्षा में कराहते हुए शामिल होते हुए देखा तो मुझसे रहा न गया. मैंने स्वयं उसे परीक्षा डेस्क से हटाकर वहीं क्लास रूम में आराम करने की व्यवस्था की और उसे गर्म पानी व चाय पीने को दिया. उसके प्राथमिक उपचार व आराम करने की व्यवस्था करने के बजाए उसके घर वालों ने उसे मोतिहारी स्थित महारानी जानकी कुंवर कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर सिर्फ़ इसलिए पहुंचा दिया था क्योंकि उसने दूसरी बार एक बच्ची को जन्म दिया था. उसकी बिगड़ती हालत ने मुझे झकझोर कर रख दिया. ऐसी महिलाएं जो उपेक्षित आश्रित व मजबूर हैं अगर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं तो आधी आबादी के चेहरे पर भी संतोष के भाव देखे जा सकेंगे. ऐसी उपेक्षित महिलाओं के लिए महिला बिल का पास होना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है. ऐसा सोचती है पूर्वी चंपारण ज़िले के मुख्यालय स्थित महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय की प्राचार्या शशिकला. उन्होंने चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह कार्य तो पहले ही हो जाना चाहिए था क्योंकि वह जिला, सूबा व देश तभी उन्नती कर सकता है जब वहां की आधी आबादी को भी समान अधिकार मिले. उन्होंने बताया कि आज हमारे कॉलेज की छात्राओं के चेहरे पर आने वाले सुनहरे भविष्य की कल्पना मात्र से ही एक अजीब आत्मविश्वास के भाव हैं.

इस महिला बिल को पास करने व इसे लागू करने में लगी सभी ताक़तों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं. ज़िला अध्यक्ष मंजू देवी ने चौथी दुनिया से बातें की और उन सभी राजनीतिक दलों व व्यक्तियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने महिला बिल के पास होने में अपना सहयोग दिया. उन्होंने बताया कि एक गाड़ी के दो पहिये के बराबर होते है स्त्री व पुरूष. आज वर्षों बाद दूसरे पहिये को अधिकार व ताक़त मिली है इसलिए अब ज़िला सूबा व देश के आगे बढ़ने की रफ़्तार दोगुनी हो जाएगी. उन्होंने बताया कि अब हमारे बीच कई प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी ,सुषमा स्वराज व अन्य पेशे की सफल महिलाओं जैसी स्त्रियां देश के नाम को रोशन करेंगी. प्रसिद्ध चिकित्सक व राजनीतिज्ञ श्रीमति चंद्रलता झा ने चौथी दुनिया से बातें की और अपने विचार व्यक्त किये. उन्होंने बताया कि हाल ही में उनके क्लीनिक पर एक संभ्रात घर की महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे उसके ससुराल वाले अवैध मान रहे थे. दिनभर वह महिला अपने नवजात को देखती रही और रोती रही. कोई पूछने वाला नही था बाद मे उस नवजात ने दम तोड़ दिया. उस महिला के लिए क्या मायका व क्या ससुराल.

> **रेणु देवी के मुताबिक़ महिला बिल का पास होना अपने आप में ऐतिहासिक फ़ैसला है. ऐसा करके भारतीय संविधान ने अपनी मज़बूती को पूरे विश्व के सामने परोसा है. चंपारण की महिलाओं में तो पहले से ही क़ाबिलियत थी लेकिन इस बिल के पास हो जाने से शर्तिया उनके आत्मविश्वास में इज़ाफ़ा होगा.**



मंजू देवी, मंजू राम, नसीमा ख़ातून, राजकुमारी गुप्ता, रामादेवी, रेणु सिन्हा, यशोदा देवी, सुमित्रा यादव, शशिकला, डॉ सी एल झा

बस स्त्री होना ही उसके लिए अभिशाप था. वैसी महिलाओं के लिए महिला बिल का पास होना अपने आप मे एक वरदान की तरह है जो सभी गुण होने के बावजूद भी आज उपेक्षित है. उन्होंने सभी सांसदों व अन्य लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने महिला बिल को पास होने में मदद की. राजद महिला प्रकोष्ट की अध्यक्ष नसीमा ख़ातून ने चौथी दुनिया को बताया कि महिला बिल का पास होना हम सभी महिलाओं के लिए वरदान है. उन्होंने बताया कि हमारी आंखों के सामने लगातार प्रताड़ित होती है महिलाएं और हम अधिकार के अभाव में कुछ नहीं कर पातीं लेकिन शायद अब हालात बदलेंगे क्योंकि अब हमारी भी पहचान है. उन्होंने बताया कि छौड़ादानो प्रखंड की उमा देवी को हत्या के झूठे आरोप मे जब फंसाया गया तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था. उस महिला के पास न आत्मविश्वास था ना ही उसे सहारा देने वाला कोई व्यक्ति. मजबूर उमा को मैंने पुलिस कप्तान से मिलवाया और उसकी मदद की. आज जबकि महिला बिल पास हो गया है तो निसंदेह उमा जैसी महिलाओं को बेवजह हत्या जैसे संगीन जूर्म में फंसाना आसान नहीं होगा. दलित साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार पा चुकी नसीमा ने बताया कि हम महज आधी आबादी नहीं बल्कि इस देश की आधी ताक़त है और प्रगति तभी संभव है जब दोनों ताक़तों को समान अधिकार मिले. उन्होंने बताया कि तुरकौलिया की एक दलित महिला के 18 साल के बेटे को संभ्रांत लोगों ने लाठी से पीटकर मार डाला. दलित महिला लाचार अपनी किस्मत पर रोती रही. उसे मैंने सहारा दिया और एक ही दिन के अंदर ज़िलाधिकारी से मिलकर एक लाख पच्चीस हज़ार की मुआवज़े की राशि दिलवायी. जिस आत्मविश्वास से मैंने यह कार्य किया आज महिला बिल के पास हो जाने से पूर्वी चंपारण की शायद सभी महिलाएं आत्मविश्वास से कार्य करेंगी क्योंकि आज के बाद से महिलाओं की भी एक विशेष पहचान है.

केसरिया की प्रखंड प्रमुख और अपनी बोल्ड छवि के लिए मशहूर नेत्री सुमित्रा यादव ने चौथी दुनिया से बातचीत की और बताया कि हाल ही में उत्तरी हुसैनी पंचायत से उर्मिला देवी ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. प्रतिद्वंद्वियों ने ठीक होली के दिन ही लाठी से पीट कर उसके पति की हत्या कर दी. उर्मिला के सिर पर भी गंभीर चोटें आईं. मुखिया को सूचित किया गया लेकिन बाहर होने के कारण वे इस दुखियारी के पास नहीं पहुच सके. ऐसे में लाचार उर्मिला रोती रही कलपती रही. सुमित्रा स्वयं उर्मिला के लिए खड़ी हुई और आज उसे मुआवज़ा मिलने के पूरे आसार हैं. सुमित्रा ने बताया कि हमारी महिलाएं अब तक आत्मविश्वास के मामले में एकदम कमज़ोर थी लेकिन महिला बिल पास होने से महिलाएं संभवत जुल्मों की शिकार होने से बच पायेंगी. पश्चिमी चंपारण की कांग्रेसी पार्टी की अध्यक्ष मंजू देवी ने चौथी दुनिया से बातचीत की और बताया कि सालों बाद यह एक ऐसी ख़बर आयी है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे. उन्होंने बताया कि नारी का दर्ज़ा अब सही रूप में सम्मानित कर दिया गया है अब दहेज हत्या जैसे उत्पीड़न का ग्राफ भी कम होगा. पश्चिमी चंपारण के चनपटिया की पूर्व ज़िला पार्षद यशोदा देवी ने चौथी दुनिया को बताया कि यह संविधान की संभवत सबसे बड़ी उपलब्धि है. उत्तर बिहार से अनारक्षित सीट पर ज़िला पार्षद का चुनाव जीतने वाली संभवत पहली महिला यशोदा देवी ने बताया कि जब मैंने 14 पुरूषों को पराजित किया तो मुझे उस क्षण यह एहसास हुआ कि योग्यताएं तो हम जैसी महिलाओं में भी है बस उन्हें सही रास्ता व मौक़ा नहीं मिलता.

आज महिला बिल पास हो जाने से संभवत पूरे देश की महिलाओं को पूरा मौक़ा मिला है और महिलाओं की हिम्मत भी बढ़ी है. उन्होंने लौरिया व चनपटिया विधान सभा के सभी मतदाताओं की तरफ से देश के उन सभी सांसदों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस बिल को पास करवाने में अपना योगदान दिया. उन्होंने केंद्र सरकार व विशेष रूप से प्रतिभा पाटिल मनमोहन सिंह व सोनिया गांधी को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद दिया. पूर्वी चंपारण की नगर परिषद उपाध्यक्ष राजकुमारी गुप्ता ने भी चौथी दुनिया से बातचीत के दौरान महिला बिल के पास होने को अपने आप मे एक एतिहासिक कदम बताया. साथ ही उन्होंने महिलाओं को सावधान करते हुए यह नसीहत भी दी कि महिला बिल के पास होने का यह अर्थ नही है कि हम महिलाएं अपने घर परिवार की पहली जिम्मेवारी को न समझे बल्कि बात तभी बनेगी जब हम अपने घरौंदों कों भी संभालें और आने वाले समय में कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी पहचान को सार्थक करें.

बहरहाल चौथी दुनिया ने पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के की प्रसिद्ध व अपने अपने क्षेत्र में सफल हो चुकी महिलाओं से बातें की उनकी संवदेनाओं अपेक्षाओं कर्तव्यों व भविष्य को लेकर योजनाओं को समझा. इस परिपेक्ष्य में इन महिलाओं ने महिला बिल को एक वरदान के रूप में देखा साथ ही आने वाली चुनौतियों को भी समझा. हालांकि इस बिल को अमली जामा पहनाने में अभी वक़्त है लेकिन महिलाओं में जो ज़ोश व उत्साह है उससे इतना तो ज़रूर लगा है कि आने वाला वक़्त उन्हीं का है और अब उनकी भी पहचान है.

feedback@chauthiduniya.com

# अस्थावां विधानसभा क्षेत्र : आसान नहीं विधायक की राह

बिहार विधान सभा के आगामी चुनाव में नए परिसीमन के अनुसार अब नालंदा ज़िले के आठ विधान सभा की जगह सात विधान सभा क्षेत्र में चुनाव होंगे. नए परिसीमन में जहां एक ओर चंडी विधान सभा क्षेत्र को विलोपित कर उसे हरनौत विधान सभा क्षेत्र में मिला दिया गया है, वहीं राजगीर (सुरक्षित) विधान सभा क्षेत्र के कतरीसराय प्रखंड के पांच पंचायत के लगभग तीस हज़ार मतदाताओं को अस्थावां विधान सभा से जोड़ दिया गया है. यह विधान सभा क्षेत्र पूर्व से संवेदनशील रहा है. बेलछी कांड के मुख्य अभियुक्त रहे स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी से लेकर कुर्मी चेतना महारैली के महानायक सतीश कुमार तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बिहार विधान सभा में कर चुके हैं. नालंदा का डॉन स्वर्गीय टी.पी. सिंह भी इस क्षेत्र से विधान सभा चुनाव में अपना भाग्य आज़मा चुके हैं.

अस्थावां विधान सभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग दो लाख पचास हज़ार है जिसमें महिलाओं की संख्या 90469 है. पुराने परिसीमन के अनुसार अस्थावां विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक बनावट में बिंद, सरमेरा, एवं अस्थावां प्रखंड ही शामिल था. पिछले दो बार से इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे जदयू के डा. जितेंद्र कुमार का विरोधी का खेमा सक्रिय होने लगा है, इस कारण जदयू से टिकट पाने वालों की आशा पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं में उपजी है. क्षेत्र के मतदाताओं का अनुमान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर नालंदा में काम करने के आधार पर कुछ क्षेत्रों में प्रत्याशी बदलेंगे तो उसमें अस्थावां के वर्तमान विधायक डा. जितेंद्र कुमार का भी पत्ता कट सकता है. अगर अक्टूबर 2005 के अस्थावां विधान सभा चुनाव को देखें तो यह स्पष्ट है कि सबसे कम उम्मीदवार इसी क्षेत्र में थे, जहां से कुल पांच उम्मीदवार चुनाव लड़े थे. उनमें वर्तमान विधायक डा. जितेंद्र कुमार जद(यू) से, डा. कुमार पुष्पाजंय (निर्दलीय), अनुग्रह सिंह (निर्दलीय), ध्यान प्रकाश उर्फ़ ओम प्रकाश बीएसपी, एवं जितेंद्र प्रसाद एसएपी शामिल थे. जद(यू) के जितेंद्र कुमार ने कुल 40474 मत प्राप्त किया था वहीं निर्दलीय प्रत्याशी डा. कुमार पुष्पाजंय को 24988 मत प्राप्त हुए थे और 15486 मतों से डा. जितेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी.



अनिल महाराज, अनीता सिंह, डॉ जितेंद्र कुमार, पुष्पाजंय कुमार, सतीश कुमार

पिछले दो विधान सभा चुनाव में जीत हासिल कर रहे वर्तमान विधायक डा. जितेंद्र कुमार द्वारा अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की कथित धीमी गति से मतदाताओं के बीच काफ़ी रोष देखा जा रहा है. इस क्षेत्र से डा.जितेंद्र कुमार के पिता अयोध्या प्रसाद ने वर्ष 1985 में एवं डा. कुमार पुष्पाजंय के पिता आर.पी. शर्मा वर्ष 1985,1990,एवं 2000 में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. डा. कुमार पुष्पाजंय वर्ष 2005 में दो बार हुए चुनावों में राजद एवं निर्दलीय टिकट पर चुनाव लड़े , परंतु उन्हें दोनों ही बार हार का मुंह देखना पड़ा. वर्तमान में भी इनके जनाधार में कोई इज़ाफ़ा नज़र नहीं हो रहा है. फिर भी इनका प्रयास इस बार लोजपा से टिकट लेने का है. वर्ष 2009 में कुमार पुष्पाजंय जद(यू) के टिकट पर विधान परिषद का सीट भी लोजपा प्रत्याशी राजू यादव से हार चुके हैं.

इस क्षेत्र से कुर्मी चेतना महारैली के नायक सतीश कुमार जो वर्ष 1995 में अस्थावां क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस बार पुन: स्वयं या अपने पुत्र को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं. जहां तक श्री सतीश कुमार की बात है कुर्मी चेतना महारैली को सफल बनाने के बावजूद उन्हें कोई ख़ास लाभ नहीं मिल पाया है. पिछले 2009 के लोकसभा चुनाव में सतीश कुमार ने नालंदा संसदीय क्षेत्र से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा परंतु जदयू के प्रत्याशी से बुरी तरह पराजित हुए. अस्थावां विधान सभा क्षेत्र कुर्मी बहुल क्षेत्र है. कुर्मी जाति के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग एक लाख है. वहीं मुस्लिम जाति की संख्या लगभग 25 हज़ार, यादव की संख्या 10 से 15 हज़ार, पासवानों की संख्या 15 हज़ार, भूमिहार की संख्या 15 हज़ार एवं अन्य जातियों की संख्या 80 हज़ार है. ज़ाहिर है कि वर्तमान राजनैतिक हालात से तो संकेत यही है कि आगामी विधान सभा चुनाव में मतदाताओं की जातीय कतारबंदी अगर हुई तो कर्मी, भूमिहार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं रविदास छोड़कर शेष महादलित एक ख़ेमे मे होंगे और वह ख़ेमा होगा जद(यू) का, मुस्लिम को रिझाने की दो तरफ़ा कोशिशें जारी है. परंतु तय है कि उक्त चुनाव में मुस्लिम मतदाता वहीं होंगे जहां भाजपा नहीं होगी. यादवों, पासवानों का राजद लोजपा खेमे में रहना तय है तो रविदासों का बसपा में रहना भी. अगर ललन फैक्टर ने काम किया तो भूमिहार मतदाताओं की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हो सकता है.

जदयू से टिकट पाने वालों में वर्तमान विधायक डा. जितेंद्र कुमार के अतिरिक्त सक्रिय रूप से अस्थावां से राजनीति कर रहे अनिल कुमार उर्फ़ महाराज जी, राज्य परिषद सदस्य (महिला प्रकोष्ठ) जद (यू) अनिता सिंह शामिल है जो सभी एक ही कुर्मी जाति (घमैला उपजाति) के हैं. इस क्षेत्र से वर्तमान विधायक डा. जितेंद्र कुमार को जदयू ने टिकट दे भी दिया तो इनके विरूद्ध जदयू के बागी सक्रिय प्रत्याशी का चुनाव लड़ने की काफ़ी संभावना बनी हुई है और यह सीट जदयू की झोली में पुन: जाए इसके लिए पार्टी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है.

डॉ. शोभा कुमारी
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 22 मार्च–28 मार्च 2010

सूबे में भेड़पालन और कंबल निर्माण का कार्य परंपरागत रूप से पाल बिरादरी द्वारा किया जाता है, जिन्हें गड़ेरिया भी कहा जाता है.



# जीटी रोड पर अवैध कारोबार

सुनील सौरभ

गया ज़िले में ग्रैंड ट्रंक रोड, अब राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या दो में क़रीब 72 किलोमीटर का हिस्सा तमाम तरह के अवैध कारोबार करने वालों के लिए अभयारण्य बन गया है. इस बात का पुख्ता प्रमाण जीटी रोड पर पड़ने वाले गया ज़िले के चार थाने –आमस, शेरघाटी, डोभी और बाराचट्टी, पुलिस पदाधिकारियों तथा शेरघाटी अनुमंडल मुख्यालय में प्रशासनिक पदाधिकारियों की पदस्थापना के लिए ऊंची पहुंच और मोटी रक़म चर्चा का विषय बन गए हैं. इस बात से गया ज़िला ही नही, बल्कि छोटी–मोटी समझ रखने वाले आम लोगों से लेकर पुलिस प्रशासन के उच्च पदाधिकारी भी वाक़िफ़ हैं.

जीटी रोड पर जिस्मफ़रोशी से लेकर अवैध कोयला, खाद्यान, एलपीजी गैस, किरासन तेल, स्प्रिट, अवैध शराब, नकली सामानों के निर्माण से लेकर अन्य तरह के कारोबार इन दिनों बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं. इनमें एक धंधा दस टन से अधिक माल ले जाने वाले ट्रकों को ग़लत तरीक़े से पार कराने का है, जिसे एंट्री का कारोबार कहते हैं. इससे बिहार सरकार को प्रति माह लाखों ही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है. आमस थाना से लेकर इस सड़क की पूर्वी सीमा बाराचट्टी थाना क्षेत्र तक बनी झोपड़ियों में ट्रक चालकों द्वारा कोयला चोरी कर बेच दिया जाता है. यह कारोबार धड़ल्ले से संबंधित पदाधिकारियों को सेवा शुल्क देकर किया जा रहा है. इसी क्षेत्र में डोभी थाना के अंतर्गत पड़ने वाले पोखरा नामक स्थान पर कई लाइन होटलों में ट्रकों से माल काटने का कारोबार ट्रक चालकों की मिलीभगत से किया जा रहा है. बताया जाता है कि मलकटवा गिरोह ट्रक चालकों के इशारे पर या फिर अपनी चालाकी से लाइन होटलों पर लगे ट्रकों से पलक झपकते ही माल साफ़ कर देते हैं. चोरी के इन मालों को तुरंत ठिकाने भी लगा दिया जाता है.

राज्य के परिवहन विभाग द्वारा डोभी के निकट बनाए गए जांच चौकी पर एंट्री माफिया काफ़ी सक्रिय हैं. प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों को जांच चौकी के पदाधिकारियों की मिलीभगत से पार कराकर अवैध रूप से राशि वसूली जाती है. इसके लिए एंट्री माफियाओं द्वारा सांकेतिक भाषा तथा मोबाइल फोन का उपयोग किया जाता है. यदि जांच चौकी पर पदस्थापित पदाधिकारी से लेकर पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन का प्रिंट आउट निकाला जाए, तो पता चल जाएगा कि राज्य सरकार को किस तरह राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है. इसी प्रकार जीटी रोड के किनारे स्थित लाइन होटलों में जिस्मफ़रोशी का धंधा भी होता है. शाम होने के साथ ही जीटी रोड के लाइन होटलों में जिस्मफ़रोशी का धंधा परवान चढ़ने लगता है. इस रोड पर रात के समय पुलिस के आने का ख़तरा भी नही रहता है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण शाम के बाद पुलिस का सारा ध्यान नक्सली गतिविधियों पर लगा रहता है. यदि कोई इस धंधे में पकड़ा भी गया, तो पैरवी के कारण थाने से ही छोड़ दिया जाता है. यही कारण है कि एक रिपोर्ट के अनुसार शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र से ही एचआईवी पॉजीटिव से पीड़ित मरीजों की रिपोर्ट सर्वाधिक है. जीटी रोड पर बाराचट्टी थाना क्षेत्र के रोही गांव में बड़े पैमाने पर नकली चाय पत्ती बनाने का कार्य किया जा रहा है. बताया जाता है कि चना के छिलके की भूसी को पीसकर चाय पत्ती में मिलाकर उसे ट्रकों से कोलकाता भेजा जाता है. इस कार्य में रोही गांव के ही कई लोग लगे हुए हैं. इसके लिए संबंधित थाने के पुलिस पदाधिकारियों को भी भरोसे में रखा जाता है. उपर्युक्त कारोबार के अलावा पेट्रोलियम पदार्थों, कैरासिन तेल के साथ–साथ अन्य कई तरह के अवैध कारोबार किए जा रहे हैं. हालांकि परिवहन जांच चौकी पर पदस्थापित पदाधिकारी एंट्री माफियाओं के द्वारा सीमा से अधिक लदे माल वाले ट्रकों को पार कराए जाने की बात से अनभिज्ञता ज़ाहिर करते हैं. शेरघाटी अनुमंडल में पदस्थापित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी इस अनुमंडल के अंतर्गत जीटी रोड पर किए जा रहे अवैध कारोबार के संबंध में कुछ भी बोलने से मना करते हैं. प्राचीन काल में व्यापार के लिए सम्राट अशोक ने भारत के जिस सिल्क मार्ग का निर्माण कराया था और बाद में जिस सड़क का जीर्णोद्धार और विस्तार प्रसिद्ध शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में पेशावर से कलकत्ता तक कराया, उसकी यह दशा इलाक़े के लोगों के लिए चिंता का विषय है.

feedback@chauthiduniya.com

# सब पर भारी हूं मैं

मोनालिसा ने अपनी सेक्सी इमेज का जादू कुछ इस तरह चलाया है कि भोजपुरी की कोई छोटी या बड़ी फ़िल्म उनके बिना पूरी ही नहीं होती. फ़िल्मों में लीड रोल्स में तो वह नज़र आती ही हैं. जिस फ़िल्म में दूसरी हीरोइनें काम कर रही होती हैं उसमें मोनालिया का आइटम ज़रुर रख दिया जाता है. नतीजा यह निकलता है कि उनके डांस में ठुमकों और लटकों–झटकों का जादू इस क़दर चलता है कि वह फ़िल्म लीड हीरोइनों पर भी भारी पड़ जाती हैं. यहां तक तो ठीक था. लेकिन अभी मोनालिसा ने एक नया पैंतरा आज़माया है. अभी तक यह माना जाता रहा है कि अगर नंबर एक की कतार की सफलतम अभिनेत्री बनना है तो सिर्फ़ लीड रोल्स में ही नज़र आना ज़रूरी है. मल्टीस्टारर फ़िल्मों में जोख़िम ज़्यादा होता है. इसकी वजह यह होती है कि एक ही फ़िल्म में कई हीरोइनों को एक साथ होने की वजह से उसे वह मौक़ा नहीं मिल पाता है, जो लीड रोल्स में मिलना चाहिए. यही वजह है कि अधिकतर अभिनेत्रियां मल्टीस्टार फ़िल्मों में काम करने से कतराती हैं. लेकिन मोनालिसा के जलवों की बात ही कुछ और है. लीड रोल और आइटम गीत के अलावा अब वह बड़ी बड़ी मल्टीस्टारर फ़िल्मों में भी नज़र आ रही हैं. दिलीप जायसवाल की फ़िल्म *देवरा बड़ा सतावेला* में मोनालिसा में नज़र आएंगी. फ़िल्म में उन पर फ़िल्माए गए हॉट दृश्यों को लेकर ख़ासी चर्चा है. फिल्म में तीन जोड़ियों में रवि किशन, रानी चटर्जी, पवन सिंह, मोनालिसा, बृजेश त्रिपाठी ओर नेहा महमूद शामिल हैं. अब इतने सारे दूसरे स्टारों के बीच काम करना और उपस्थिति दर्ज़ कराना आसान नही होता. पर मोनालिसा को भरोसा है कि वह सब पर भारी पड़ेंगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# भेड़पालकों का दर्द बढ़ता जा रहा है

प्रेमचंद पाल अब भी भेड़ पालते हैं, लेकिन भेड़ उनकी अपनी न होकर बटाई की होती है. एक वक़्त था जब भेड़ उनकी अपनी हुआ करती थी. मगर, समय के चक्र कुछ यूं बदला कि सारी हालत बदल गयी. दरअसल सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के चलते कैमूर के भेड़पालक बटाईदार बनने को विवश हैं. उनके पिता–पितामह कभी सैकड़ों भेड़ों के मालिक हुआ करते थे. अब उनके वारिस सरकारी मदद के अभाव में बटाई पर दूसरों की भेड़ चरा रहे हैं. इलाके के अधिकांश भेड़पालकों की यही कहानी है. कई लोगों ने तो इस दुर्दशा से तंग आकर अपने इस पुश्तैनी पेशे को त्यागकर जीविकोपार्जन के लिए मज़दूरी करना शुरू कर दिया है.

भेड़पालकों की यह दुर्दशा भारतीय कृषि संस्कृति को तार–तार कर रही पूंजीवादी सभ्यता की इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का भी परिचायक है, जिसके तहत किसान अपनी ज़मीन से वंचित होकर पहले बटाईदार बनता है और अंत में मज़दूर बनने को विवश हो जाता है. इस दु:स्थिति के चलते मानव सभ्यता के विकास के आरंभिक पशुचारी चरण की याद दिलानेवाला भेड़पालन का पेशा तो ख़तरे में है ही, परंपरागत कंबल निर्माण उद्योग भी बंदी के कगार पर पहुंच गया है.

कैमूर ज़िला के कुदरा प्रखंड के रामपुर ग्राम निवासी प्रेमचंद की बदनसीबी की कहानी तब शुरू हुई, जब किसी अज्ञात बीमारी से वर्ष 2006 में उनकी 75 भेड़ें मर गईं. अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए मजबूरी में उन्हें एक चावल मिल मालिक की भेड़ें बटाई पर लेनी पड़ी. प्रेमचंद बताते हैं कि अब वे बटाई की भेड़ों को ही चराते और पालते हैं, जो भी ऊन निकलता है और जितने भी मेमने जन्म लेते हैं, उनका आधा हिस्सा उन्हें भेड़ों के स्वामी को दे देना पड़ता है. सरकारी मदद की बात पूछने पर प्रेमचंद बिफर पड़ते हैं. वे बताते हैं कि उनकी भेड़ें मरने लगीं तो मवेशी अस्पताल से कोई दवा नहीं मिली और चिकित्सक भी विलंब से पहुंचे. मवेशी चिकित्सक ने मरी हुईं भेड़ों का बेसरा पटना वेटेनरी कॉलेज जांच के लिए भेजा, जिसे अपनी गरज से प्रेमचंद ख़ुद लेकर गए, लेकिन काफ़ी दौड़–धूप के बाद आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिली और भेड़ों की इस जानलेवा बीमारी से उनके गांव के भेड़पालक अनजान ही रहे. कैमूर ज़िले के जहानाबाद, सकरी, लालापुर, गोराडीह, दरौली, बेलांव आदि गांवों के अलावा अमूमन हर गांव में भेड़पालकों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन हर जगह उनकी दुर्दशा की एक जैसी ही कहानी है. भेड़पालन के प्रति सरकारीतंत्र की उपेक्षा का आलम यह है कि कृषि विभाग इससे अपना वास्ता ही नहीं मानता. ज़िला कृषि पदाधिकारी ललिता प्रसाद कहते हैं, भेड़पालकों के लिए कृषि विभाग में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी करेगा, पशुपालन विभाग ही. इधर पशुपालन विभाग के पास सिर्फ़ आंकड़े हैं. जिससे कुछ होने वाला नहीं है. जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. उपेंद्र नारायण शर्मा बताते हैं कि कैमूर ज़िले में 34258 भेड़ें हैं. हालांकि सरकारी सहायता के बारे में वे कहते हैं, भेड़पालकों के लिए अलग से कोई सहायता इस समय उपलब्ध नहीं है. अन्य पशुओं के लिए जो सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, वही भेड़ों के लिए भी है. सूबे में भेड़पालन और कंबल निर्माण का कार्य परंपरागत रूप से पाल बिरादरी द्वारा किया जाता है, जिन्हें गड़ेरिया भी कहा जाता है. भेड़पालकों को चारे की तलाश में अपने मवेशियों के झुंड के साथ खुले आसमान के नीचे दूर–दूर तक भटकना पड़ता है. अक्सर वे अपनी भेड़ों के साथ कई–कई महीने घर से बाहर रहते हैं. अतिक्रमण और सरकारी बंदोबस्ती के चलते चारागाहों के समाप्त होने से उनकी परेशानी और अधिक बढ़ गयी है. मौसम ख़राब होने पर तो भेड़पालकों पर क़हर ही टूट पड़ता है. भेड़ भारत की परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था व कृषि संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं. कृषक समाज के लिए भेड़ से अधिक लाभदायक शायद ही कोई पशु हो. भेड़ से खाने के लिए मांस व दूध तथा पहनने के लिए ऊन मिलता है. भेड़ों के इतना अधिक उपयोगी होने के बावजूद भेड़पालन के पेशे को उपेक्षित किया जाना दु:खद है. बिहार राज्य पाल महासंघ के महासचिव चंद्रमोहन पाल आक्रोश जताते हुए कहते हैं, सरकार मत्स्यपालन, सूअरपालन और मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देती है, लेकिन भेड़पालन उसकी प्राथमिकता सूची में कहीं नहीं है. पाल बिरादरी से कैमूर ज़िला परिषद के इकलौते सदस्य सुरेन्द्र पाल इस बदहाली को अपने समुदाय के राजनीतिक पिछड़ेपन से जोड़कर देखते हुए कहते हैं, यदि अन्य जातियों की तरह पाल समुदाय का भी राजनीति में प्रतिनिधित्व रहता तो शायद भेड़पालन को इतने हल्के तौर पर नहीं लिया जाता.

बटाई की भेड़ों के साथ एक भेड़ पालक

भेड़पालन के पेशे की तरह परंपरागत कंबल निर्माण उद्योग भी दम तोड़ रहा है. लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकारी हलकों में बातें ख़ूब होती हैं, लेकिन कंबल उद्योग की मौजूदा स्थिति कुछ और ही बयां करती है. वैसे भी जब भेड़ पालने वालों की संख्या घटती ही जाएगी तो कंबल के लिए ऊन आएगा कहां से. चंद्रमोहन पाल बताते हैं कि पुराने समय में कैमूर का कुदरा सूबे भर में कंबल उद्योग के लिए पहचान रखता था, लेकिन अब कंबलों की सरकारी ख़रीद बंद हो गई है. सरकार द्वारा न भेड़ों की नस्ल सुधारने की कोशिश हुई, न ही कंबल निर्माण की तकनीक संवारने की. नतीजतन मिल–निर्मित कंबलों के साथ प्रतिस्पर्धा में टिके रहना परंपरागत रूप से निर्मित कंबल के लिए मुश्किल होता गया. अब यहां कंबल की बुनाई करने वाले करघे भी गिने–चुने ही रह गए हैं. अपनी मेहनत और लगन के लिए याद किए जाने वाले पाल समुदाय में पुश्तैनी पेशे को लेकर निराशा इस क़दर व्याप्त है कि जिनके पास पैसा है वे भी अपनी पूंजी चावल निर्माण जैसे दूसरे उद्योगों में लगा रहे हैं. ज़ाहिर है, यदि समय रहते कुछ नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में भेड़पालन और परंपरागत कंबल निर्माण उद्योग अतीत की बातें हो जाएंगीं.

अशोक कुमार पांडेय
feedback@chauthiduniya.com

# चौथी दुनिया

दिल्ली, 22 मार्च-28 मार्च 2010 www.chauthiduniya.com


# नर्मदा घाटी में कभी उड़ते थे डायनासोर

**अब तक उड़ने वाले डायनासोर केवल कल्पना में ही रहे हैं, लेकिन हाल ही मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के मध्य क्षेत्र में उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिलने से यह कल्पना साकार रूप लेने लगी है कि कभी धरती और आकाश पर विशालकाय डायनासोर का एकछत्र साम्राज्य था.**

संध्या पाण्डे

धरती का सबसे प्राचीन अतिविशालकाय जीव डायनासोर, जीव विज्ञानियों और धरती के इतिहासकारों के लिए रहस्यमय प्रजाति बना हुआ है. लगभग 6 से साढ़े 6 करोड़ साल पहले धरती पर विचरण करने वाले इन जीवों को लेकर सदियों से जीव विज्ञानी और प्राणी शास्त्री अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह अध्ययन आज तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि दुनिया में जब तब डायनासोर के जीवाश्म मिलने से इस जीव के बारे में नये रहस्यों का ख़ुलासा होने लगता है.

अब तक उड़ने वाले डायनासोर केवल कल्पना में ही रहे हैं, लेकिन हाल ही मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के मध्य क्षेत्र में उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिलने से यह कल्पना साकार रूप लेने लगी है कि कभी धरती और आकाश पर विशालकाय डायनासोर का एकछत्र साम्राज्य था. डायनासोर के जीवाश्मों की खोज के इतिहास में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. मध्य प्रदेश में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खोज अभियान चलाए. इन अभियानों में स्थानीय जनता के अलावा भारतीय वैज्ञानिकों ने भी गहरी रूचि ली और पश्चिमी वैज्ञानिकों की भरपूर सहायता की. इन्हीं अभियानों के तहत 20वीं सदी के प्रारंभ में मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में लमेटा चट्टानों के बीच प्राप्त एक संपूर्ण डायनासोर के अस्थियों के ढांचे की खोज ने डायनासोर अध्ययन को एक नई दिशा दी है.

जानकारों का कहना है कि बालाघाट में प्राप्त डायनासोर के ढांचे को पश्चिमी विद्वानों ने इंगलैंड भेज दिया और आज इंगलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय में डायनासोर का जो ढांचा हैं, वह मध्य प्रदेश की ही अनमोल देन है.

1930 में प्रो. लीडेकर ने मध्य भारत के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर डायनासोर के अवशेषों की खोज करने के बाद दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि विश्व का प्राचीनतम प्राकृतिक जुरासिक पार्क मध्यभारत में ही था. इसके बाद यह क्षेत्र अमेरिका और यूरोप के जीव वैज्ञानिकों की खोज का मुख्य केंद्र बन गया. कई खोजकर्ताओं को समय-समय पर मध्य भारत के नर्मदा घाटी क्षेत्र से डायनासोर के विभिन्न अंगों की हड्डियां मिलीं, जबड़े मिले, तो अंडे भी बड़ी मात्रा में मिले. पिछले वर्ष धार ज़िले में स्थानीय खोजकर्ताओं को सैकड़ों की संख्या में डायनासोर के अंडे मिलने से एक बार फिर यह क्षेत्र चर्चा में आ गया.

सदियों से चल रहे डायनासोर खोज अभियान की कड़ी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के खोजकर्ताओं ने प्राप्त की है.

हाल ही में मध्य प्रदेश के मध्य नर्मदाघाटी क्षेत्र में विशालकाय उड़ने वाले डायनासोर प्राणियों के जीवाश्म खोजने का दावा पुरातत्ववेत्ताओं और वनस्पतिशास्त्र के विद्वानों ने किया है. पुरातत्वविद् वसीम खान, नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद के वनस्पति विभाग के अध्यक्ष डॉ. केडब्ल्यू शाह और रवि उपाध्याय ने इस बारे में बताया कि होशंगाबाद से उत्तर में रायसेन ज़िले की देवरी तहसील के ग्राम पतई के पास नर्मदा के सिद्ध घाट के किनारे दो किलोमीटर लंबे क्षेत्र में जुरासिककाल के जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए गए हैं. इन जीवाश्मों में बड़ी-बड़ी हड्डियां, अंडों के छिलके, डायनासोर के पंख, पंजे और नाख़ून आदि मिले हैं, जो अब पत्थर के रूप में तब्दील हो चुके हैं.

नर्मदा घाटी में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज में जुटी सिदरा आर्कियोलाजी इन्वॉयरमेन्ट रिसर्च, ट्रायव वेलफेयर सोसाइटी के पुरातत्वविद् एवं वनस्पति शास्त्रियों ने मिलकर करोड़ों वर्ष पुराने ये जीवाश्म खोज निकाले हैं. सोसाइटी के पुरातत्वविद् मुहम्मद वसीम ख़ान का मानना है कि नर्मदा घाटी का यह स्थान डायनासोर की विभिन्न प्रजातियों का पसंदीदा स्थान रहा होगा. यहां काफ़ी मात्रा में अंडों के शल्क, हड्डियों के जीवाश्मों के समूह मिले हैं. पुरातत्वविद् वसीम ख़ान, नर्मदा कॉलेज के वनस्पतिशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. डॉ. के डब्ल्यू शाह व प्रो. डॉ. रवि उपाध्याय के मुताबिक़ यहां जुरासिक काल के जीवाश्म होने की पुष्टि इससे होती है कि इन जीवाश्मों के पास ही उस समय की सायकास समूह के वृक्षों के तने व कोन के जीवाश्म भी मिले हैं. अगर इन सभी अवशेषों पर विधिवत रिसर्च की जाए तो इस प्रजाति से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा खुल सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

# कुपोषण हज़ारों बच्चों को लील रहा है



विनय दीक्षित

मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 30 हजार बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही बेमौत मर जाते हैं. ये वो अभागे बच्चे हैं, जो जन्म से ही कुपोषण के शिकार होते हैं और जन्म के बाद पोषण आहार की कमी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं.

मध्य प्रदेश देश के उन चंद पिछड़े राज्यों में है, जहां शिशु मृत्युदर सबसे ज्यादा है. राज्य में शिशु मृत्यु दर 70 प्रति हजार है. गरीबी, पिछड़ेपन और अशिक्षा की मार झेल रहे मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है. पिछले विधानसभा चुनाव में कुपोषण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने जोर-शोर से उठाया था. शुरू में तो भाजपा सरकार ने माना ही नहीं कि राज्य में कुपोषण की गंभीर समस्या है, लेकिन जब कांग्रेस की ओर से सरकार के मंत्रियों को राज्य सरकार और भारत सरकार के अधिकृत प्रतिवेदनों का संदर्भ देकर बताया गया कि राज्य में हर साल हजारों बच्चे कुपोषण के कारण बेमौत मारे जा रहे हैं, तो सरकार को कुछ शर्म आई.

भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्य को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने का वायदा किया था, लेकिन यह वायदा कोरा शाब्दिक आश्वासन ही बनकर रह गया. आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं. वर्ष 2008-09 में राज्य में कुपोषण के कारण 29 हजार 274 बच्चों की मौत होने की पुष्टि खुद लोक स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा ने विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में की है.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तृतीय चक्र के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुपोषण 54 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत है. मध्य प्रदेश में 12.6 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित है, जबकि देश में औसतन 6.4 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं. मध्य प्रदेश में 13 लाख 35 हजार बच्चे (पांच वर्ष तक की आयु के) गंभीर रूप से कुपोषित हैं. प्रदेश में पिछले 32 महीनों में 81 हजार 622 शिशुओं की मौत हो गई. अकेले सतना जिले में पिछले 32 महीनों में 4 हजार 954 शिशुओं की मौत हुई, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है.

सर्वोच्च न्यायालय की एक रिपोर्ट की मानें तो प्रदेश में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की कुल संख्या एक करोड़ दस लाख के आसपास है. पिछले विधानसभा चुनाव में कुपोषण चुनावी मुद्दा बना था. तब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने चुनाव घोषणा पत्रों में कुपोषण की समस्या को हल करने और राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने का वायदा किया था. लेकिन कमजोर प्रशासन तंत्र, शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार और जनता के प्रति संवेदनहीन रवैये के कारण हर साल करोड़ों, अरबों रूपए खर्च होने के बाद भी कुपोषण की समस्या अपने भयावह रूप में बनी हुई है.

राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्रोथ चार्ट के मानदण्डों के अनुसार राज्य में कुपोषित बच्चों का पता लगाने के लिए दिसम्बर 2009 में एक अभियान चलाया था. इसके तहत छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों का वजन लेकर उनमें कुपोषण के स्तर का पता लगाना था. इस आधार पर बच्चों की तीन श्रेणियां तय की गई, जो इस प्रकार हैं:- सामान्य, कम वजन वाले और अति गंभीर कुपोषित बच्चे. सरकारी सूत्रों के अनुसार इस अभियान के तहत कुल 57 लाख बच्चों का वजन लिया गया. इनमें 36 लाख बच्चे सामान्य वजन के पाये गए और 18 लाख बच्चे औसत से कम वजन के पाए गए. अति गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या दो लाख 82 हजार आंकी गई. इस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के आदिवासी बहुल जिले में कुपोषण की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक पाई गई है. राज्य के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, मंडला, सीधी और अनूपपुर जिलों में अतिकुपोषित बच्चों की संख्या 7 से 15 प्रतिशत तक रही.

जानकारों का कहना है कि कुपोषण की छानबीन के लिए बच्चों के वजन मापने के इस अभियान में कई कमियां और गड़बड़ी रही हैं और इस कारण इस अभियान से जो नतीजे आए हैं, वे ज्यादा भरोसेमंद नहीं हैं. जानकारों ने बताया कि वजन मापने की मशीनों की कमी के कारण 30 हजार से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में दूसरे स्थानों से मशीने लाई गईं और कई मशीनें बिगड़ जाने से सुदूर ग्रामीण अंचलों में उन्हें सुधारा भी नहीं गया और मनमाने तौर पर बच्चों का वजन लिया गया. पहली बार इस वर्ष लड़के और लड़कियों के वजन के अलग-अलग चार्ट बनाए गए और लिंग के आधार पर कुपोषण मानदण्ड में भी अंतर किया गया. फिर भी इन ताजे नतीजों से भी यह सिद्ध होता है कि राज्य में बच्चों में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. दूसरी ओर कुपोषण की समस्या का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार की तैयारियां कितनी कम हैं और इच्छाशक्ति का कितना अभाव है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य में समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए पूरे राज्य में जहां एक लाख 46 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकता है, वहीं राज्य में केवल 70 हजार आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जो कि राज्य के केवल 76 प्रतिशत बच्चों को ही अपनी सेवाएं देते हैं. इस प्रकार एक चौथाई बच्चे अभी भी बाल कल्याण सेवाओं से वंचित हैं.

राज्य की केवल 13 हजार आदिवासी बस्तियों में समेकित बाल विकास सेवा का लाभ पहुंच रहा है, लेकिन लगभग 4200 आदिवासी बस्तियां इस सेवा से अभी भी वंचित हैं. राज्य में वर्ष 2007-08 में इस सेवा के लिए जहां 1320 करोड़ रूपयों की धनराशि की आवश्यकता थी, सरकार ने केवल 320 करोड़ रूपए ही उपलब्ध कराए और इसमें से पोषण आहार के लिए तो केवल 255 करोड़ रूपए ही उपलब्ध कराए ता सके . अब केंद्र सरकार ने कुपोषित बच्चों और स्तनपान कराने वाली तथा गर्भवती माताओं को पोषण आहार के लिए 4 रूपए प्रति हितग्राही के मान से केंद्रीय सहायता देना शुरू किया है, तब राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से दिए जाने वाले अंशदान में कुछ बढ़ोतरी की है. मध्य प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 में बताया गया है कि राज्य में कुल 367 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 69238 आंगनवाड़ी केंद्रों से लगभग 49 लाख 24 हजार बच्चों तथा दस लाख 31 हजार गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार सेवा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

2003 के विधानसभा चुनाव में सड़कों की कमी और सड़कों की दुर्दशा को भाजपा ने मुद्दाबनाया और चुनाव जीता और जल्द ही भूल गई.





सरकार और समाज बच्चों को नशे की आदत से बचाने के जो भी उपाय कर रही हैं, वे पर्याप्त और प्रभावी नहीं हैं.



# बनते ही उखड़ती हैं सड़कें



मध्य प्रदेश में सड़कें बनने के तुरंत बाद टूटने लगती हैं. यह सिलसिला कांग्रेस और भाजपा, दोनों की सरकारों के दौरान बदस्तूर जारी है. इसका एक बड़ा कारण सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और कमीशन-घोटाले हैं जिसके कारण निर्माण के गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है. आरोप है कि अधिकारी केवल सरकारी पैसे खर्च करने और जल्दी-जल्दी निर्माण कार्य पूरा करने पर ही ध्यान देते हैं. इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकारी सड़कों के बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है कि सड़कें पूरी बनकर तैयार होती नहीं कि उखड़ने लगती हैं और उनकी मरम्मत की मांग करने लगती हैं. मध्य प्रदेश में सड़क, परिवहन यातायात के साधन के रूप में भले ही ज़्यादा उपयोगी न हो, राजनीति के लिए सड़क ज़रूर एक भड़काऊ मुद्दा रही हैं.

2003 के विधानसभा चुनाव में सड़कों की कमी और सड़कों की दुर्दशा को भाजपा ने मुद्दा बनाया था और चुनाव भी जीता. चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार ने बड़े पैमाने पर गांव और शहरों में सड़कें बनाने का काम शुरू किया और इसका श्रेय लूटने के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार के लिए ख़र्च कर दिया. रोज़ 8 किलोमीटर सड़क बनाने का दावा करने वाली सरकार ने कभी यह नहीं देखा कि जल्दी-जल्दी बन रही सड़कों की असली हालत क्या है. पता चला है कि लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों के टूट-फूट जाने और उखड़ जाने से परेशान होकर राज्य के संबंधित विभाग ने इन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सरकार से अतिरिक्त 300 करोड़ रूपयों की मांग की है. सरकार के पास पैसा है नहीं, इसलिए सैंकड़ों ग्रामीण सड़कें अपनी दुर्दशा ख़ुद ही बयान कर रही हैं.

राज्य में वर्ष 1999-2000 से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ हुई थी. पहले चरण में इस योजना के तहत पांच सौ की आबादी से 32 तथा एक हज़ार की आबादी के 173 गांव तथा दूसरे चरण में पांच सौ की आबादी के 199 गांव एवं एक हज़ार की आबादी के 731 गांव सड़कों से जोड़ने का कार्यक्रम बनाया था. इन सड़कों के निर्माण का ठेका भी पांच साल तक मेंटेनेंस योजना में ठेकेदारों को दिया गया था. पहले चरण में 207 सड़कें 207 करोड़ की राशि ख़र्च कर निर्मित कराई गई थीं और दूसरे चरण में 793 सड़कों के निर्माण पर 638 करोड़ की राशि व्यय की गई थी. अधिकृत सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण सड़क योजना में निर्मित लगभग 1100 सड़कों के रख-रखाव का कार्य पांच साल तक तो ठेकेदारों ने किया, मगर बाद में उन्होंने इससे अपना हाथ खींच लिए. रखरखाव के अभाव में पिछले पांच साल से इन सड़कों की मरम्मत पर केंद्र सरकार ने कोई अतिरिक्त फंड रिलीज़ नहीं किया. यही स्थिति फेस-3 में निर्मित कराई गई 573 सड़कों तथा फेस-4 में निर्मित 743 सड़कों की भी हो रही है.



ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कार्य पर पहले चरण में सड़कों पर लगभग 65 करोड़ और दूसरे चरण में 214 करोड़ रुपयों की राशि ख़र्च होने का अनुमान है. अब हालत यह है कि ख़राब हालत में पहुंच चुकी ग्रामीण सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए पुन: ठेके दिए जाएंगे और इस कार्य में पुराने ठेकेदार फिर से सक्रिय नज़र आएंगे. मतलब वही ढाक के तीन पात वाला किस्सा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# रेत माफिया के कारण घड़ियालों पर संकट





एस बी सिंह

खनिज और रेत माफिया मध्य प्रदेश के एक और अभ्यारण्य को समाप्त करने जा रहा है. जैव विविधता की परिकल्पना मध्य प्रदेश में अलग-अलग माफियाओं के चलते इन दिनों संकट में है. विंध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी नदियों में शामिल की गई सोन नदी के तट पर बना घड़ियाल अभ्यारण्य राज्य शासन की उपेक्षा और अनदेखी का शिकार बन चुका है.

सोन घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में सोन नदी की विविधता और प्राकृतिक सौन्दर्य को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के आदेश से 23 सितम्बर 1981 को स्थापित किया गया था. उस समय के एक सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में मगरमच्छ और घड़ियालों की कुल संख्या 13 बताई गई थी, जबकि वास्तविकता कुछ और थी. क्षेत्र में कार्यरत पर्यावरणविदों के अनुसार इस क्षेत्र में घड़ियालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और उसका प्रमुख कारण सोन नदी के तट पर अनधिकृत रूप से कार्यरत रेत माफिया हैं.

रेत माफिया के अवैध संग्रहण के कारण मगरमच्छ और घड़ियाल सोन नदी से क़रीब बसाहट वाले गांव में घुसकर जानवरों और ग्रामीणों को शिकार बना रहे हैं. ज़िला चिकित्सालय सीधी में पदस्थ चिकित्सक डॉ. आर.बी. सिंह के अनुसार प्रतिवर्ष 40 से 50 लोग घड़ियालों के हमले का शिकार होकर यहां आते हैं, जिनमें से कुछ को तो बचा लिया जाता है पर कई लोग अकाल मौत का भी शिकार हो जाते हैं. रेत माफिया सोन नदी से अवैध रूप से उत्खनन करने के लिए नदी को लगातार खोदने का काम करता है, परिणामत: पानी में होने वाली लगातार हलचल के परिणाम स्वरूप घड़ियालों के लिए निर्मित किए गये इस प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन आता है.

इस अभ्यारण्य का उद्घाटन प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा 10 नवम्बर 1981 को किया गया था. अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 209.21 किमी का है. इसमें सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल जिले में प्रवाहित होने वाली सोन नदी के साथ गोपद एवं बनास नदी का कुछ क्षेत्र भी शामिल है. सोन घड़ियाल अभ्यारण्य नदियों के दोनों ओर 200 मीटर की परिधि समेत 418.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित घोषित है.



सोन घड़ियाल अभ्यारण्य

मध्य प्रदेश में विलुप्ति की कगार पर जा रहे घड़ियाल, मगरमच्छों की दुर्लभ जलीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई थी. इस अभ्यारण्य के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का बजट आवंटित करती है. प्रतिबंधित क्षेत्र में रेत माफिया द्वारा लगातार किया जा रहा अवैध उत्खनन राज्य शासन के स्थानीय अधिकारियों के लिए चिंता का विषय नहीं है. रेत माफिया स्थानीय अधिकारियों और नेताओं से ही पिछले दो वर्षों से सक्रिय है. सूत्रों की मानें तो भारत शासन द्वारा घड़ियाल अभ्यारण्य में खर्च की जाने वाली राशि फर्जी बिल वाउचरों के ज़रिए वन अधिकारियों एवं स्थानीय अधिकारियों के निजी खजाने में जा रही है. सोन नदी के जोगदाह पुल से कुछ आगे रेत का अवैध उत्खनन रहील बना हुआ है, जहां से रेत माफिया इस क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय हैं. सोन घड़ियाल के प्रभारी संचालक ने चौथी दुनिया को बताया कि 200 किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र के लिए केवल 13 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हैं. मगरमच्छ एवं घड़ियालों की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये का बजट आवंटित किया जाता है. अब तक तक़रीबन 250 मगरमच्छ एवं घड़ियालों के बच्चे संरक्षित क्षेत्र में छोड़े गए हैं, जिनकी संख्या अब लगभग 150 के क़रीब है. श्री वर्मा के अनुसार शीघ्र ही वैज्ञानिक सर्वे कराया जाना प्रस्तावित है, इसके बाद भिन्न प्रजातियां एवं उनकी वास्तविक संख्या का आंकलन किया जा सकेगा. वरना बाघों की तरह इनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

# नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं



मध्य प्रदेश सरकार राज्य में क़ानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होने के लाख दावे करे, लेकिन इस हकीकत को सरकार छिपा नहीं सकी है कि राज्य में उग्रवादी नक्सली संगठन अपने पांव पसार रहे हैं. इसी कारण उनका प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है. सन् 2000 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद राज्य में केवल बालाघाट ज़िला ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार के गृह विभाग ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें मंडला, डिंडोरी, सीधी और सिंगरौली जिलों को भी नक्सल प्रभावित मानने का प्रस्ताव भेजा है. इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों की रोकथाम में पूरी तरह विफल रही है और सरकार की कमजोरी का लाभ उठाकर उग्रवादी नक्सली संगठन अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने में सफल हुए हैं. उल्लेखनीय हैं कि कुछ वर्ष पूर्व भोपाल में बिजली नगर क्षेत्र की आवासीय बस्ती में नक्सलियों का एक अड्डा पकड़ा गया था, जिसमें अवैध हथियार बनाने का काम चलता था. इसके बाद भी राज्य सरकार का खुफिया तंत्र सचेत नहीं हुआ. बालाघाट जिले में बस्तर के साथ ही नक्सली गतिविधियां शुरू हुई थीं और एक दशक बीत जाने के बाद भी सरकार इस जिले में नक्सलियों पर नियंत्रण नहीं पा सकी. बालाघाट जिले के नक्सली संगठनों का संबंध महाराष्ट्र के गढ़चिरोली के नक्सलियों से है और दोनों में आपसी सहयोग के रिश्ते भी कायम हैं. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हाल ही देश के नक्सल प्रभावित राज्यों से इन संगठनों के बारे में जानकारी मांगी हैं, इसके उत्तर में मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने यह सूचना दी हैं कि राज्य में नक्सली अब चार और जिलों में फैल गए हैं अत: इनके विरूद्ध कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त पुलिस बल और संसाधन उपलब्ध कराए जाय।

# नशे की लत में डूबा बचपन

राष्ट्र का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों में नशाख़ोरी की लत इस तेज़ी से बढ़ रही है कि दस वर्ष की आयु में प्रवेश करते ही ज़्यादातर बच्चे विभिन्न प्रकार के नशीले और मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं.

संयुक्त राष्ट्र संघ के नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2009 की रिपोर्ट में बताया गया है कि दस से ग्यारह वर्ष की आयु के 37 प्रतिशत स्कूली विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और वे नशाख़ोरी की आदत के शिकार हो जाते हैं. सबसे ज़्यादा चिंता की बात है अति ग़रीब और ग़रीब वर्ग के बच्चों की, जो सबसे ज़्यादा नशे की गिरफ़्त में आ रहे हैं.

> संयुक्त राष्ट्र संघ के नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2009 की रिपोर्ट में बताया गया है कि दस से ग्यारह वर्ष की आयु के 37 प्रतिशत स्कूली विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और वे नशाख़ोरी की आदत के शिकार हो जाते हैं.



कुछ यू नशे की [illegible] पूरा करते हैं बच्चे

अब यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ये बच्चे तंबाखू, गुटखा से लेकर गांजा, अफ़ीम, चरस, हेरोईन जैसे घातक मादक पदार्थों का सेवन करते हैं. इन बच्चों के माता-पिता और वयस्क परिवारजन रोज़ी-रोटी की जुगाड़ में व्यस्त रहते हैं और वे बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं. यहां तक कि दस वर्ष की उम्र में ही बच्चे भी स्कूल छोड़कर कचरा बीनने, होटलों, ढाबों में मज़दूरी करने या बाज़ार में फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करने लगते हैं और वे अपनी कमाई से मादक पदार्थ ख़रीदने में सक्षम हो जाते हैं.

बच्चों में नशाख़ोरी की लत का अध्ययन करने वालों का कहना है कि ज़्यादातर बच्चों को नशे की लत उनके वयस्क या हमउम्र नशाख़ोरों के ज़रिए ही लगती है. परिवार की उपेक्षा के कारण ये भोले-भाले बच्चे नशा कराने वाले को ही अपना मित्र और सच्चा हमदर्द मान लेते हैं और नशे की आदत में पड़कर हर तरह के शोषण का शिकार हो जाते हैं.

नशे की गिरफ़्त में आए बच्चे जब मनचाहा नशा नहीं कर पाते हैं तो वे खून में बढ़ती मादक पदार्थो की मांग को पूरा करने के लिए शरीर के लिए घातक पदार्थों का भी सेवन करने लगते हैं, जैसे कि बोन फिक्स, क्यूफिक्स और आयोडेक्स. कई बच्चे तो पेट्रोल और केरोसिन भी पीकर नशे की प्यास बुझाते हैं.

नशे के गुलाम ये बच्चे या तो बेमौत मर जाते हैं या फिर अपराध की अंधी दुनिया में प्रवेश कर समाज और देश के लिए विकट समस्या बन जाते हैं. सरकार और समाज बच्चों को नशे की आदत से बचाने के जो भी उपाय कर रही हैं, वे पर्याप्त और प्रभावी नहीं हैं. इसलिए ज़रूरी है कि देश के भविष्य को पतन के रास्ते से बचाने के लिए परिवार से उपेक्षित, ग़रीब, अशिक्षित और बाल मज़दूरी करने वाले बच्चों को नशे से बचाने के लिए गंभीरता से प्रभावी और कारगर उपाय किए जाने चाहिए.

आरती पटेल
feedback@chauthiduniya.com

# सार-संक्षेप

## इंजीनियर को एक वर्ष का कारावास

आय से अधिक संपत्ति रखने और सरकारी नियमों के अनुसार उसका ख़ुलासा न करने के आरोप में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री महेंद्र सिंह चौहान को विशेष न्यायालय जबलपुर ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हज़ार रुपये के ज़ुर्माने से दंडित किया है. महेंद्र सिंह चौहान जब जबलपुर में इंजीनियर पद पर कार्यरत थे, तब 24 फरवरी 1995 को लोकायुक्त-पुलिस ने उनके आवास पर छापा मारकर लाखों रुपये की अघोषित चल-अचल संपत्ति का पता लगाया था. इस पर 26 फरवरी 1995 को अपराध दर्ज़ कर जांच की गई तो पता चला कि चौहान के पास आय से अधिक सवा 18 लाख रुपये की संपत्ति है. इस पर लोकायुक्त कार्यालय स्थित विशेष न्यायालय जबलपुर में जनवरी 1999 में प्रकरण प्रस्तुत किया गया. इसका फ़ैसला हाल में हुआ है.

## डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग की नकेल

मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे चिकित्सकों पर एक बार फिर से लगाम कसने का प्रयास किया है, जो मरीज़ों को ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं धड़ल्ले से लिखकर आर्थिक लाभ कमा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने हाल में एक आदेश जारी किया है कि अब सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक मरीज़ों के पर्चे पर जेनरिक दवाओं को ही लिख सकेंगे, ब्रांडेड दवाएं नहीं. इसके पीछे शासन की सोच यह है कि दवा कंपनियों से चिकित्सकों को मिलने वाले कमीशन और गिफ्ट पर रोक लग सके. इससे ग़रीब मरीज़ों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, लेकिन आदेश को सरकारी चिकित्सकों के अलावा निजी चिकित्सकों पर भी सख्ती से लागू किया जाना ज़रूरी है. पांच साल पहले भी राज्य सरकार ने इस आशय का एक आदेश जारी किया था, जिसमें सरकारी डॉक्टरों को अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीज़ों को ब्रांडेड कंपनियों के नाम न लिखने के निर्देश दिए गए थे. आदेश में स्पष्ट किया गया था कि डॉक्टर रोगी के पर्चों में दवाओं के केमिकल नाम भी लिखें, जिससे वह अपनी सुविधा के अनुसार दवाएं ख़रीद सके. लेकिन इस आदेश का पालन एक माह भी नहीं हो सका था.

## भूजल स्तर गिरने से पन्द्रह हज़ार हैण्डपंप ठप्प



ग्रीष्म ऋतु के आते ही मध्य प्रदेश में जल संकट गहराने लगा है. राज्य में जिस तेज़ी से भूजल स्तर नीचे खिसक रहा हैं, वह चिन्ता का विषय बना हुआ है. हाल ही राज्य के मुख्य सचिव अवनि वैश्य ने पेयजल आपूर्ति और ग्रीष्म ऋतु में संभावित जल संकट के बारे में लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आला अफसरों से चर्चा की. इस चर्चा में बताया गया कि राज्य में कुल चार लाख 40 हज़ार हैण्डपंप हैं, जिनमें से लगभग 15 हज़ार हैण्डपंप जल स्तर खिसक जाने से बेकार हो गए हैं. यह भी बताया गया कि राज्य में लगभग 2900 बस्तियों में स्वच्छ और निरापद पेयजल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है. शासन ने ग्रीष्मकाल में जल संकट वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए 115 करोड़ रूपए लागत की कार्ययोजना तैयार की है.

## अफ़सरों के भोज में नदारद रहे मुख्यमंत्री

मध्य प्रदेश आईएएस ऑफीसर्स एसोसिएशन द्वारा ऑफीसर्स मेस में पिछले दिनों आयोजित भोज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के शामिल न होने को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. पिछले दिनों आयकर विभाग ने छापामार कार्यवाही कर राज्य के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और कुछ अन्य आला अफसरों के घर और दूसरे ठिकानों से करोड़ों रूपयों की अघोषित नगदी, जेवरात और अचल संपत्ति का पता लगाया है. इसके बाद प्रशासन की भ्रष्ट छवि को लेकर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में भारी चिन्ता व्याप्त हो गई. अधिकारी अपराध बोध से ग्रस्त होकर, शासन की छवि सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिले और उनसे शासन प्रशासन के बीच उत्पन्न अविश्वास के माहौल को सुधारने की अपील की. मुख्यमंत्री ने भी राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों में परस्पर विश्वास की भावना विकसित करने पर ज़ोर दिया. इसी प्रक्रिया में आईएएस एसोसिएशन ने भोज का आयोजन किया था और आयोजन से तीन दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को न्यौता दिया था जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन जिस दिन भोज का आयोजन होना था, उसी दिन वे अपने पूर्व निर्धारित मंडला प्रवास पर चले गए और वहां से जबलपुर होते हुए भोपाल आए. अचानक भोपाल हवाई अड्डे से मुख्यमंत्री सीधे इन्दौर रवाना हो गए. इस भोज में राज्य के मुख्य सचिव अवनि वैश्य, पूर्व मुख्य सचिव और बिजली बोर्ड के अध्यक्ष राकेश साहनी सहित 90 आईएएस अधिकारियों ने भाग लिया. लेकिन मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को लेकर अफसरों में अटकलें लगाई जाती रहीं. ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अभी भी आईएएस अफसरों के कामकाज और व्यवहार से खुश नहीं है.

## महिला सरपंच ने गांव छोड़ा

सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए चाहे जितने भी उपाय कर ले और चाहे कितने भी बिल पास कर ले, लेकिन पुरूष प्रधान समाज व्यवस्था में आज भी ऐसे कई लोग हैं, जो राजनीति में महिलाओं के वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं करते हैं. मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बुडरक की सरपंच श्रीमती हब्बीबाई पत्नी परमलाल कुशवाह, हाल ही ग्राम पंचायत चुनाव में जनादेश से सरपंच बनी हैं, लेकिन गांव के कुछ सवर्ण दबंग इस ग़रीब अनुसूचित जाति की महिला को अपना ग्राम प्रधान नहीं मानते हैं और उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करते हैं. दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर हब्बीबाई अपने परिवार सहित ज़िला मुख्यालय छतरपुर में डेरा डाले हुए है. उसने बताया कि 24 फरवरी की रात में कृष्णपाल सिंह उर्फ़ राजा और उसका रिश्तेदार बलवीरसिंह, छह-सात लोगों को लेकर उसके घर आ गए और ज़बरन दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करने लगे. दरवाजा न खुलने पर इन दबंगों ने घर के बाहर बंदूक से हवाई फायर करके सरपंच और उसके परिवार वालों को डराया, धमकाया. महिला सरपंच का कहना हैं कि कृष्णपाल सिंह एक आपराधिक मामले में फ़रार है और पुलिस को उसकी तलाश है, लेकिन वह गांव में बेधड़क रहता है और ग़रीब लोगों को डराता-धमकाता है. उसे हब्बीबाई का सरपंच पद पर आसीन होना पसंद नहीं है. इसीलिए वह उसे और उसके परिवार वालों को जब-तब डराता-धमकाता रहता है. इतना ही नहीं, मोबाईल फोन पर वह हब्बीबाई के खेत की फ़सल जला देने की धमकी भी देता है और जब कभी भी उसके परिवार का कोई सदस्य अपने खेत पर जाता है तो उसके साथ मारपीट भी करता है. हब्बीबाई ने बताया कि उसने कृष्णपाल सिंह के ख़िलाफ़ थाना महाराजपुर में शिकायत भी की है, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है. उसने ज़िला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से संरक्षण देने की मांग की है और कहा है कि जब तक सरंक्षण नहीं मिलेगा वह अपने गांव वापस नहीं लौटेगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# मध्य प्रदेश नाकारा और निरंकुश अफ़सरशाही के शिकंजे में

राजधानी में होली पर्व की पूर्व बेला में प्रसारित एक गुमनाम पर्चा प्रशासनिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था. यह पर्चा कुछ स्थानीय अख़बारों में पूरे नमक मिर्च के साथ छापा भी गया है. इस पर्चे ने प्रशासन का मनोबल और भी कमज़ोर दिया है.

यह पर्चा प्रशासन के 133 आईएएस अफ़सरों के बारे में है. इन अफसरों को भ्रष्ट, महाभ्रष्ट और अय्याश जैसे वर्गों में वर्गीकृत कर इस पर्चे में आगे बताया गया है कि कई अफसरों ने अपनी दो नंबर की कमाई को कहां-कहां और किस-किस कारोबार में निवेश किया है. पर्चे में कुछ अफसरों को ईमानदार और उज्जवल छवि का कुशल प्रशासक भी बताया गया है. इससे लगता है कि प्रशासन में आला अफसरों में गुटबाज़ी अब सार्वजनिक संघर्ष के रूप में दिखाई देने लगी है.

बताया जाता हैं कि इस गुमनाम पर्चे में दो-चार महिला अधिकारियों के चरित्र पर भी कीचड़ उछाला गया है. पर्चा राज्य के मुख्य सचिव अवनि वैश्य और पुलिस महानिदेशक एस के राउत के पास भी पहुंचाया गया है और वे अपने स्तर पर इस पर्चे के मूल स्रोत का पता लगाने के प्रयास में जुट भी गए हैं. एक यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि पिछले दिनों राज्य के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति से पूर्व कुछ आला अफसर अपने पक्ष में मुख्यमंत्री से पैरवी कर रहे थे या करवा रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने वर्षों से दिल्ली में पदस्थ अवनि वैश्य को मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया, तब यह सर्वोच्च पद पाने से निराश अफसरों ने ख़ुराफात करना शुरू किया है.

> गुमनाम पर्चे में दो-चार महिला अधिकारियों के चरित्र पर भी कीचड़ उछाला गया हैं. पर्चा राज्य के मुख्य सचिव अवनि वैंश्य और पुलिस महानिदेशक एस के राउत के पास भी पहुंचाया गया हैं और वे अपने स्तर पर इस पर्चे के मूल स्रोत का पता लगाने के प्रयास में जुट भी गए हैं.

इस पूरी स्थिति को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नौकरशाही पर कमज़ोर हो रही पकड़ की तरह देखा जा रहा है. वातावरण यह बनाया जा रहा है कि राज्य में शासन का प्रशासन पर से नियंत्रण लगातार कमज़ोर होता लगे. अनेक लोग तो खुलकर कहने भी लगे हैं कि नौकरशाही निरंकुश और स्वच्छंद हो गई लगती है. पिछले दिनों आयकर विभाग ने राज्य के प्रमुख सचिव स्तर के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों सहित कई दूसरे अधिकारियों और उनके सहयोगियों के यहां छापा मार कर करोड़ों रूपयों की अवैध संपत्ति का पता लगाया, तो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम राज्य के शासन-प्रशासन के होश उड़ गए.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैरान हो गए और उन्हें कहना पड़ा कि इससे तो जंगलराज अच्छा है. वैसे तो उनकी यह टिप्पणी उनकी कमज़ोरी को ही बयान करती है, पर यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इन अधिकारियों ने इतनी कमाई की है, वह केवल चौहान के शासनकाल में नहीं की गई होगी. पर इस छापे के तुरंत बाद से ऐसा लगने लगा है कि मुख्यमंत्री ने सरकार की इमेज सुधारने के लिए मुख्य सचिव और सभी आला अफसरों को कड़े आदेश दिए हैं. उसके बाद ही मुख्य सचिव ने राज्यव्यापी दौरे करके अपनी सक्रियता दिखाने का प्रयास आरंभ किया है. मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाही करने के नेक इरादे ज़ाहिर करने के बावजूद प्रशासन का मनोबल निरंतर गिरता लग रहा है और मुख्यमंत्री तथा शासन द्वारा प्रशासन के गिरते मनोबल को संभालने के लिए कोई प्रयास नहीं होता आम जनता को महसूस नहीं हो रहा है.

मध्य प्रदेश में भाजपा शासन के दौरान आईएएस अफसरों में काफ़ी असंतोष और क्षोभ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि राज्य में कई आला अफ़सरों के पास तो काम का भारी बोझ है और कई ऐसे भी हैं जिनके पास कोई काम नहीं हैं. एक अधिकारी को एक साथ कई महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिए गए हैं, तो किसी को मामूली विभाग सौंपकर राज्य मंत्रालय में बेकार बैठे रहने की सजा दी गई है. इसके अलावा संभागों में आयुक्त और ज़िलों में कलेक्टर की नियुक्ति में भी





अवनि वैश्य | शिवराज सिंह चौहान

राजनैतिक कारणों से फ़ैसले लिए गए और यह भी आरोप है कि पदोन्नत आईएएस अधिकारियों को अधिक महत्व दिया गया. कुछ मामलों में तो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को संभागायुक्त पद पर बैठा दिया गया. इसी तरह दूसरे विभागों में भी पदस्थापना को लेकर मनमानी की गई है. मुख्य सचिव ने भी पदस्थापना और स्थानांतरण के मामले में अपने अधिकारी बंधुओं के हितों और उनकी भावनाओं को नजरंदाज़ करते हुए मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन किया, इससे भी अधिकारियों का असंतोष बढ़ने लगा. जिन अरविन्द जोशी पर आयकर छापे में करोड़ों की अघोषित आय का पता चला है, वे पिछले पांच वर्षों से जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव पद पर आसीन थे. चूंकि अरविंद जोशी की मुख्यमंत्री और अपने विभाग के मंत्रियों से अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्हें उनके मनचाहे पद पर ही रखा गया. लेकिन तब किसी ने जल संसाधन विभाग में चल रही तमाम तरह की अनियमितताओं की ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया गया.

महत्वपूर्ण पदों पर आसीन आईएएस अधिकारियों को जब कभी भी कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना होता है, तो वे शासन-प्रशासन का मुंह ताकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे फ़ैसले हो जाते हैं, जिनसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है. ऐसे मामलों में राज्य में पिछले दस महीनों में छह आईएएस अफसर निलंबित हो चुके हैं.

कटनी की पूर्व कलेक्टर अंजु सिंह बघेल भूमाफिया और खनिज माफिया की मदद करने के आरोप में निलंबित हैं. ज़िला पंचायत कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर पाटिल बड़े ही शर्मनाक मामले में बदनाम होने के कारण निलंबित किए गए थे, लेकिन बाद में वे साफ़ बच गए. उन पर कार्यालय में एक युवक के देह शोषण का आरोप था. लेकिन बाद में आरोप ग़लत पाया गया. टीकमगढ़ के कलेक्टर रोज़गार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हुए. भिण्ड कलेक्टर सुहेल अली पर भी ऐसे ही आरोप थे, लेकिन वे बचा लिए गए.

रोज़गार गारंटी योजना में पूरे राज्य में घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों की गूंज दिल्ली तक हुई है. भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस योजना में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने में रुचि ले रही है. जांच होती है तो निश्चित ही कई आला अफसर मुसीबत में पड़ जाएंगे.

मध्य प्रदेश में संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, एक ऐसा पद बन गया है, जिस पर एक के बाद एक दाग़दार अफसर आसीन हुए और मलाई छानकर निलंबित होकर आराम से बैठ गए. डॉ. योगीराज शर्मा पर दो वर्ष पूर्व आयकर विभाग का छापा पड़ा और करोड़ों रूपयों की अघोषित संपत्ति का पता चलने के बाद उन्हें शासन ने निलंबित कर दिया, लेकिन न्यायालय से निलंबन आदेश रद्द कराकर वे फिर पद पर बहाल हो गए. बाद में उन्हें दोबारा निलंबित किया गया.

उनके बाद इस पद पर नियुक्त हुए डॉ. अशोक शर्मा भी भ्रष्टाचार के संदेह के घेरे में आ जाने के कारण काफ़ी लंबे समय बाद निलंबित किए गए हैं. अब इस पद को पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों में होड़ लगी हुई है.

## 36 आईएएस लोकायुक्त जांच के घेरे में

वर्तमान में मध्य प्रदेश के 36 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन में जांच चल रही है. इससे स्पष्ट हैं कि राज्य प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारियों की छवि कितनी घूमिल है.

इनके अलावा शासन के 25 आईएएस अधिकारियों की जांच राज्य सरकार का आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है. यह ब्यूरो पुलिस विभाग का ही अंग हैं और राज्य के पुलिस महानिदेशक का इस ब्यूरो पर नियंत्रण रहता है. ब्यूरो में सभी पदों की नियुक्तियां राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा की जाती है, अत: गृह सचिव और प्रमुख सचिव गृह विभाग का ब्यूरो पर अंकुश रहता है.

## 17 अधिकारियों के ख़िलाफ़ चालान

लोकायुक्त संगठन जनवरी 2004 के बाद से अब तक 17 आईएएस अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर चुका है. अधिकृत सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले एक दो महीने में पांच से सात आईएएस अधिकारियों के ख़िलाफ़ अदालत में प्रकरण दर्ज़ कराने की प्रक्रिया चल रही है.

## अफ़सर उच्च न्यायालय की भी परवाह नहीं करते

मध्य प्रदेश में अफसरशाही कितनी निरंकुश और स्वच्छंद है, इसका एक यही उदाहरण पर्याप्त है कि अफसर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों-निर्देशों की भी परवाह नहीं करते हैं और शासन-प्रशासन के प्रमुख भी ऐसे अफसरों को न्यायालय का सम्मान करने की सीख नहीं देना चाहते हैं. राज्य में अनेक ऐसे आईएएस और दूसरे आला अफसर हैं, जिन पर जब तब न्यायालय की अवेहलना करने या आदेशों की उपेक्षा करने के मामले चल रहे हैं. एक आईएएस अफसर पर तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अदालत की मानहानि के 136 प्रकरण दर्ज़ हैं, लेकिन अफसर को कोई परवाह नहीं हैं. ये अफसर हैं- मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध संचालक अनिरुद्ध मुखर्जी.

मध्य प्रदेश संवर्ग के आईएएस अफसर अनिरुद्ध मुखर्जी पर 136 मामलों में न्यायालय की मानहानि की कार्यवाही चल रही हैं. जबलपुर उच्च न्यायालय में ही मानहानि के 103 मामले चल रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ में 24 और इन्दौर खण्डपीठ में 27 मामले चल रहे हैं. परिवहन निगम के कर्मचारियों की याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के फ़ैसलों का पालन नहीं होने के कारण न्यायालय ने प्रबंध संचालक के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना के प्रकरण कायम किए हैं.

इस बारे में बताया जाता है कि याचिकाओं पर निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय ने निगम को याचिकाकर्ता कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन भत्तों का भुगतान तथा अन्य आर्थिक दायित्वों के भुगतान के आदेश दिए हैं, लेकिन निगम की वित्तीय स्थिति ख़राब होने के नाम पर न्यायालय के इन आदेशों का पालन नहीं किया जा सका है. प्रबंध संचालक मुखर्जी ने इस बारे में राज्य शासन को भी समय-समय पर सूचना दी है, लेकिन शासन ने भी न्यायालय के आदेशों को पालन कराने के लिए निगम की कोई सहायता नहीं की. नतीजा यह हुआ कि याचिकाकर्ता कर्मचारियों ने न्यायालय में अवमानना की शिकायत की और इस शिकायत को सही पाते हुए न्यायालय ने प्रबंध संचालक के ख़िलाफ़ अवमानना के मामले दर्ज़ कर लिए. एक के बाद एक अब तक 136 मामले दर्ज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अनिरुद्ध मुखर्जी पद पर बने हुए हैं और शासन भी इस पूरे मामले में तमाशबीन बना हुआ है.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 22 मार्च–28 मार्च 2010

चित्रकूट जिले के इस गांव से 500 मीटर पहले नदी तट के किनारे इच्छाधारी ने 2009 में 5 एकड़ जमीन खरीदी थी.



# जनसंख्या के आधार पर आदिवासी आरक्षण की मांग

सुब्रत भौमिक

छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण देने का मुद्दा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है.

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के झण्डे तले राज्य के 18 आदिवासी संगठनों ने हाल ही रायपुर में अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जनमत जागृत करने की जो मुहिम छेड़ी, उसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आदिवासी एकता का राग अलापने लगे थे और वे भी राज्य में आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग के पक्ष में खड़े हो गए.

आदिवासी सम्मेलन में उपस्थित नेतागण

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कांग्रेस ने अजीत जोगी को आदिवासी प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य दलों के आदिवासी नेताओं ने जोगी के आदिवासी होने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया. फिर भी अजीत जोगी ने अपनी राजनीति के लिए हमेशा आदिवासी कार्ड खेला और ऊपरी तौर पर ही सही, हमेशा आदिवासियों के विकास और कल्याण के कार्यक्रमों पर जोर देते रहे. विधानसभा चुनाव हारने के बाद जोगी ने भाजपा में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाने में उत्प्रेरक की भूमिका अदा की. लेकिन डॉ. रमनसिंह अपनी लोकप्रियता और शीर्ष भाजपा नेताओं की स्वीकृति के बल पर दुबारा मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे. इससे भाजपा के अन्य नेता शिवप्रताप सिंह, नंदकुमार शाह, ननकीराम कवर आदि भीतर ही भीतर असंतुष्ट रहकर आदिवासियों की एकता के लिए प्रयास करते रहे. इस एकता का ही नतीजा है कि राज्य के 18 आदिवासी संगठन, अपने दलीय लगाव को भूलकर एकजुट हुए हैं. इनका सवाल है कि झारखण्ड में भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया और हाल ही शिबु सोरेन को सरकार बनाने में सहयोग दिया, तब छत्तीसगढ़ में भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का क्यों विरोध कर रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है.

**छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कांग्रेस ने अजीत जोगी को आदिवासी प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य दलों के आदिवासी नेताओं ने जोगी के आदिवासी होने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया.**

आदिवासी विकास परिषद में भाजपा सरकार की खुलकर आलोचना भी की गई है. मुख्यमंत्री रमन सिंह के कामकाज के बारे में साफ शब्दों में कहा गया है कि वे सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हुए हैं और सरकार और भाजपा पर पूरा नियंत्रण रखकर राज्य में वन मैन शो कर रहे हैं. सरकार के कई आदिवासी मंत्री केवल शोभा के पात्र बनकर रहे गए हैं, क्योंकि सरकार के आला अफसर उनके आदेशों और सुझावों पर ध्यान नहीं देते हैं. कहने को तो ननकीराम कवर गृहमंत्री हैं, लेकिन राज्य के पुलिस महानिदेशक न तो उनकी सुनते हैं और न ही उन्हें गृहमंत्री का सम्मान देते हैं.

यह भी कहा गया कि नगरीय और ग्रामीण संस्थाओं के चुनाव में आदिवासियों को उचित प्रतिनिधित्व न मिल सकें, इसके लिए सरकार ने सभी कानूनी और प्रशासनिक उपाय किए थे. नक्सलवाद की समस्या से जूझने के नाम पर बस्तर और दूसरे कई स्थानों पर निर्दोष आदिवासियों की पुलिस द्वारा हत्या करने और उन्हें प्रताड़ित करने के बारे में आदिवासी नेताओं ने विस्तार से चर्चा करते हुए सरकार और पुलिस के रवैये को आदिवासी विरोधी करार दिया है. आदिवासी नेताओं ने एकजुट होकर भाजपा के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से मुलाकात करने और अपनी तमाम मांगों पर बातचीत करना तय किया है. लेकिन जानकारों का कहना है कि आदिवासी नेता वास्तव में भाजपा पर राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री नियुक्त करने का दबाव बनाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर वे गडकरी से मुलाकात करना चाहते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

# चित्रकूट इच्छाधारी की जन्मभूमि है

पुष्पेंद मोर्या

मध्य प्रदेश का अविकसित कहा जाने वाला क्षेत्र अभी तक विंध्य क्षेत्र ही माना जाता था, परंतु उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे होने के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पिछले दिनों अपराधियों तथा असामाजिक गतिविधियों में आश्यर्चजनक रूप से वृद्धि हुई है. इस क्षेत्र के चित्रकूट धाम निवासी इच्छाधारी बाबा का सेक्स रैकेट और गतिविधियां इन दिनों पूरे देश के सनातन धर्मी संतों की मान और प्रतिष्ठा पर एक बदनुमा दाग बन चुकी हैं.

मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त क्षेत्र चित्रकूट को हिन्दू समाज एक पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में मानता है. इसी क्षेत्र के चमरौंहा गांव के निवासी राजीव रंजन द्विवेदी उर्फ शिवा द्विवेदी उर्फ भीमानंद उर्फ इच्छाधारी बाबा ने राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कांड किया जिससे संत समाज और चित्रकूट धाम दोनों ही अपमानित हुए हैं. इच्छाधारी बाबा इसी गांव का निवासी था और यहीं, हाई स्कूल में तीन बार फेल होने के बाद वह आगरा के एक होटल में वेटर की नौकरी करने गया था.

चित्रकूट जिले के मानिकपुर कस्बे से 23 किलोमीटर दूर स्थित चमरौंहा गांव में इच्छाधारी बाबा का अपना साम्राज्य है. बाबा के पिता बच्चालाल द्विवेदी के अलावा मां, पत्नी मुन्नी बाई और बाबा की 13 वर्ष की पुत्री यहां निवास करते हैं. ढोंगी बाबा का बड़ा भाई राममूरत द्विवेदी परिवार सहित सतना जिले के सगमनिया गांव में रहता है और वह झोलाछाप डॉक्टर है. बाबा के पिता का कहना है कि तीन बार हाई स्कूल में फेल होने के बाद उनका बेटा शिवा द्विवेदी घर से भागकर आगरा चला गया था और वहां के एक होटल में वेटर का काम करता था. घर के किसी सदस्य का कोई संपर्क इस शिवा के साथ कभी नहीं रहा, इसी बीच उसकी शादी हुई और वह एक बच्ची का बाप बन गया. 1997 में पहली बार भीमानंद ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा सेक्स रैकेट में पकड़ा गया था.

एक कार्यक्रम में शिरकत करता इच्छाधारी बाबा

चित्रकूट जिले के इस गांव से 500 मीटर पहले नदी तट के किनारे इच्छाधारी ने 2009 में 5 एकड़ जमीन खरीदी थी. इसी वर्ष जमीन पर भव्य आश्रम बनाने के लिए कराई गई पूजा अर्चना में दिल्ली और बम्बई की बार– बालाएं भी बुलाई गई थीं. इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री दद्दू प्रसाद, दस्यु साम्राट ददुवा का पुत्र, जिला पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह और कई तेंदूपत्ता व्यापारियों ने शिरकत की थी. बाबा की इस जमीन पर तत्कालीन कलेक्टर हृदेश कुमार ने बाबा से खुश होकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की राशि से 1500 पेड़ उस जमीन पर लगवा दिए थे, जहां वर्तमान में इच्छाधारी ने तीन मंजिला साई आश्रम मंदिर बनवाया है.

बाबा स्वयं स्वीकार कर चुका है कि ददुवा से उसके संपर्क थे. अब जबकि एक–एक करके बाबा से संबंधित सारे तथ्य पूरे देश में खुलते जा रहे हैं, तो चित्रकूट में बाबा के पाले हुए गुंडों के सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न खड़ा हो गया है. बाबा इस क्षेत्र में सक्रिय डकैतों के आंतक का राष्ट्रीय स्तर पर कितना उपयोग करता था यह जांच का विषय हो सकता है.

इस क्षेत्र में इच्छाधारी जैसे बाबाओं को स्थानीय स्तर पर दोनों राज्यों की सीमा होने के कारण सक्रिय तस्कर समूहों, व्यापारियों और राजनेताओं का व्यापक संरक्षण मिलता रहा है. इस क्षेत्र में पिछले दिनों हुए परिवर्तनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अविकसित कही जाने वाली विंध्य की संस्कृति पर माफिया का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ही इच्छाधारी जैसे कथित बाबाओं को लोग व्यापक संरक्षण देते रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

# पुलिस विभाग को कुत्तों के लिए पैसे नहीं

मध्य प्रदेश पुलिस का बजट विगत एक दशक में 813 करोड़ रूपए से बढ़कर लगभग 2000 करोड़ रूपए का हो गया है, लेकिन फिर भी यहां पैसे की तंगी बनी ही रहती है. हालत इतनी दयनीय है कि सुरक्षा और निगरानी के लिए उत्तम नस्ल के कुत्तों के लिए भी पुलिस विभाग के पास पैसा नहीं है और सरकार भी इसके लिए अतिरिक्त धन आवंटन के लिए राजी नहीं है.

राज्य पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पुलिस के पास केवल 70 कुत्ते हैं, जो 48 जिलों में जरूरत के अनुसार तैनात हैं. ये कुत्ते जर्मन शेपर्ड, लेब्राडोर और बुल्डॉग प्रजाति के हैं, लेकिन पुलिस की सेवा कर रहे इन कुत्तों में से ज्यादातर बूढ़े हो चुके हैं और रिटायर किए जाने योग्य हैं. फिर भी उनसे काम लिया जा रहा है क्योंकि नए कुत्तों के खरीदने के लिये विभाग के पास पैसे नहीं हैं. बाजार में सभी चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के श्वान दस्ते को आज के बाजार मूल्य पर नये कुत्ते खरीदने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं.

पुलिस विभाग इस वर्ष अपने बेड़े में बीस नए कुत्ते लाने की तैयारी में है. इसके लिए एक पुलिस टीम इसी माह हैदराबाद जाना चाहती है, लेकिन पैसे की कमी के कारण इस टीम को भरोसा नहीं है कि उसे अच्छी नस्ल के कुत्ते पर्याप्त संख्या में मिल भी पाएंगे. राज्य शासन द्वारा अभी भी एक कुत्ते खरीदने के लिए 16 हजार रूपए दिए जाते हैं, जबकि आज एक लेब्राडोर की कीमत 24 हजार रूपए से ज्यादा है. इससे बेहतर नस्ल के जर्मन शेपर्ड और बुल्डॉग की कीमत तो 24 हजार रूपए से कहीं ज्यादा है.

पुलिस के काम आने वाले कुत्ते तीन प्रकार के होते हैं. नारकोश ट्रेक कुत्ते नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के काम आते हैं, क्योंकि वे सूंघकर ही नशीले पदार्थों का पता लगा लेते हैं. ट्रेकर कुत्ते चोर और डकैत पकड़ते हैं तथा स्नाईफर कुत्ते बम और विस्फोटक पदार्थों का पता लगाते हैं.

पुलिस विभाग अपनी जरूरत के अनुसार चार से छह माह की आयु के कुत्ते खरीदकर लाता है. खरीदी से पहले विभाग केनल क्लब ऑफ इंडिया से कुत्तों के बारे में तमाम जानकारी लेता है क्योंकि इस क्लब के पास ऊंची नस्ल के प्रत्येक कुत्ते की वंशावली होती है. खरीदने के बाद पुलिस उन कुत्तों को पहले तीन महीने प्रारंभिक प्रशिक्षण देती हैं, इस प्रशिक्षण में इन्हें आज्ञा मानने और आदेश के अनुसार काम करने के लिए तैयार किया जाता है. इसके बाद छह माह की अवधि के लिए कुत्तों को किसी एक अपराध शाखा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है. यह प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रत्येक कुत्ते को विशेषज्ञ बनाने के लिए विशेष मेहनत की जाती है. इसके बाद इन्हें उनके प्रशिक्षण नतीजों के आधार पर नारकोश ट्रेक, ट्रेकर और स्नाईफर शाखा में नियुक्त किया जाता है. इन खोजी कुत्तों का पुलिस संवर्ग के अनुसार वर्गीकरण भी किया जाता है. वर्तमान में मध्य प्रदेश में सहायक पुलिस अधीक्षक रैंक के कुत्ते सेवारत् हैं. रैंक के अनुसार प्रत्येक कुत्ते के रखरखाव, भोजन और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com